सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

09 मार्च, 2018

षोडश विधान-सभा — शुक्रवार,तिथि 09 मार्च, 2018 ई0

नवम् सत्र — 18 फाल्गुन, 1939 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है । प्रश्नोत्तर-काल । अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे । प्रश्न सं0-12, माननीय सदस्य श्री श्याम रजक । स्वास्थ्य विभाग ।

श्री अब्दुलबारी सिद्दिकी : स्वास्थ्य का प्रभार आप ही को मिल गया ?

श्री नन्दकिशोर यादव,मंत्री : हम उस समय पूछते थे तो आप क्या जवाब देते थे, याद है न ? महोदय, इनको मालूम है, जवाब सरकार देती है । आप भुला गये ।

श्री भोला यादव : महोदय, माननीय पथ निर्माण मंत्री जी का स्वास्थ्य ठीक है, इसलिए जवाब दे सकते हैं ।

श्री नन्दकिशोर यादव,मंत्री : मेरा स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहता है, हम दूसरे का स्वास्थ्य जो खराब रहता है, उसको ठीक करने की कोशिश करते रहते हैं ।

श्री अब्दुलबारी सिद्दिकी : सिर्फ दूसरे का खराब करते हैं ?

श्री नन्दकिशोर यादव,मंत्री : ठीक करने की कोशिश करते रहते हैं ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, सदन का समय जाया नहीं किया जाय ।

श्री नन्दकिशोर यादव : यह तो वहां न कहिए बगल में ।

प्रश्नोत्तरकाल

अल्पसूचित प्रश्न सं0-12(श्री श्याम रजक)

श्री नन्दकिशोर यादव,मंत्री : महोदय, उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि बजट पूरे वित्तीय वर्ष में होने वाले व्यय का मात्र पूर्वानुमान होता है । वास्तविक आवश्यकता इससे कम या अधिक हो सकती है ।

यह सही है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के बजट प्रावधानों क्रमशः रू0 8234.69 करोड़ एवं रू0 7001.52 करोड़ की तुलना के उपरान्त 15.5 प्रतिशत की कमी प्रतिबिम्बित होती है ।

परन्तु वास्तविकता है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 का वास्तविक व्यय 8234.69 करोड़ रू0 के बजट उपबंध के विरूद्ध मात्र 5551.08 करोड़ है ।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के वास्तविक व्यय के परिप्रेक्ष्य में 2017-18 का बजट प्राक्कलन रू0 7001.52 करोड़ का था, जो पुनरीक्षित होकर के 7533.57 करोड़ रू0 हो गया है ।

इस प्रकार वस्तुतः वित्तीय वर्ष 2016-17 की तुलना में 2017-18 के पुनरीक्षित बजट में लगभग 27 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2018-19 में 7793.81 करोड़ रू0 का प्रावधान किया गया है, जो वास्तव में 2017-18 के पुनरीक्षित बजट आकलन की तुलना में 3.5 प्रतिशत अधिक है ।

सरकार आंतरिक मशीनरी को सुदृढ़ एवं विकसित करने का प्रयास कर रही है, जिससे अधिक से अधिक राशि का व्यय किया जा सके और जन सामान्य को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो सके ।

श्री श्याम रजक : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि 3.5 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई है, जबकि हमारे पास सर जो रिपोर्ट है, जो बंटा है इनके बजट का, उसके अनुसार 2016-17 में 8246.44 करोड़ था यानी 82 अरब 46 करोड़ रू0 और 2017-18 में 70 अरब 1 करोड़ रू0 था, इस प्रकार से तो 4 प्रतिशत इनका घटोत्तरी हुआ है । दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि हर जगह कमियां हैं डॉक्टर की, इन्फ्रास्ट्रक्चर की । एक तरफ आपका 2004-05 का बजट जो था 23885 करोड़ रू0 का, उसमें आठ गुना वृद्धि यानी 2018-19 में 1 करोड़ 76 लाख 990 करोड़ रू0 का आपने बजट बनाया । जब आम बजट में बढ़ोत्तरी हुई है तो स्वास्थ्य बजट में कटौती क्यों ? जबकि कई समस्यायें हैं स्वास्थ्य विभाग में , आप देखते होंगे समाचार-पत्रों में, खुद माननीय मंत्री जी पटनासिटी के हैं, पटना के हैं, देखते हैं कि पटना में भी जिस तरह का हाहाकार है, डॉक्टर की कमी है, इन्फाट्रक्चर की कमी है, दवा की कमी है, एक्सपर्ट डॉक्टर की कमी है । खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में इतनी बुरी स्थिति है अध्यक्ष महोदय ......

अध्यक्ष : आप पूरक पूछ लीजिए ।

श्री श्याम रजक : अध्यक्ष महोदय, 90 प्रतिशत ग्रामीण अस्पतालों में महिला चिकित्सक नहीं हैं तो क्या उन चिकित्सकों की बहाली के लिए बजट जो आयेगा, उसमें बढ़ाना चाहेंगे ?

श्री नन्दकिशोर यादव,मंत्री : महोदय, चिकित्सक की बहाली का इस बजट से कोई मतलब नहीं है । चिकित्सकों की बहाली में जितने रूपये की आवश्यकता होगी, उसमें राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग खर्च करने के लिए तैयार है । उसमें पैसा बाधा नहीं बनेगा, यह मैं विश्वास दिलाता हूँ ।

दूसरा महोदय, मैंने अपने जवाब में बताया है, आप जानते हैं और माननीय सदस्य श्री श्याम रजक जी भी जानते हैं चूँकि मंत्री रहे हैं महोदय, यह भी जानते हैं कि जो विभाग बजट बनाता है, वह अनुमान के आधार पर बनाता है । मैंने कहा महोदय कि

जो 2016-17 में बजट बना था 8234 करोड़ रू0 का, उसमें केवल 5551 करोड़ रू0 ही खर्च हुआ । महोदय, उसकी तुलना में आप देखेंगे तो हर साल वृद्धि हो रही है। इसलिए जो पुनरीक्षित प्राक्कलन था 2017-18 का वो 7533 करोड़ रू0 था और आप देखेंगे कि उसके हिसाब से बढ़ोत्तरी हुई 3.5 प्रतिशत की पिछले वर्ष की तुलना में । हम इसमें बढ़ोत्तरी करने में सफल हुए हैं । मैं फिर से विश्वास दिलाना चाहता हूँ सदन को और सदन के माध्यम से पूरे राज्य की जनता को कि एन0डी0ए0 की सरकार ने बिहार के स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार का जो कार्यक्रम प्रारंभ किया था, उसे किसी भी कीमत में रूकने नहीं देंगे, बेहतर स्वास्थ्य देने के लिए हमारी प्रतिबद्धता है, हम उसको पूरा करेंगे और इसको पूरा करने में जो राशि की आवश्यकता पड़ेगी, राज्य सरकार उस राशि को मुहैय्या करायेगी ।

अल्पसूचित प्रश्न सं0-13(श्री ललित कुमार यादव)

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह,मंत्री : महोदय, वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य स्कीम मद में मूल स्वीकृत उद्व्यय 80891.61 करोड़ है, पुनरीक्षित उद्व्यय 87362.60 करोड़ है । वित्तीय वर्ष 2017-18 में 15 नवम्बर,2017 तक मूल उद्व्यय 80891.61 करोड़ के विरूद्ध 30500.49 करोड़ जो 37.71 प्रतिशत है । दिनांक 15.11.2017 तक निर्धारित उद्व्यय के विरूद्ध पथ निर्माण विभाग द्वारा 55.23 प्रतिशत एवं ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा 39.35 प्रतिशत राशि व्यय की गयी । वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रथम सात माह में लगभग 4 माह राज्य के अधिकांश जिले बाढ़ की विभीषिका से प्रभावित रहे, जिसके फलस्वरूप इस अवधि में विकास से संबंधित योजनाओं एवं राज्य की कल्याणकारी योजनाओं पर प्रावधानित राशि व्यय नहीं हो पायी ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जवाब हम मान भी लें, जो यह आंकड़ा प्रस्तुत कर रहे हैं, अब मार्च के अंतिम में, हमलोग इस वित्तीय वर्ष के अंतिम महीना में हैं । लेकिन जो आंकड़ा प्रस्तुत किये हैं खर्च का ब्यौरा दिये, वह संतोषजनक नहीं है । लेकिन उसको अगर हम मान लें माननीय मंत्री जी का जवाब तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो राशि आपने खर्च किया, उस राशि से राज्य की जनता की कितनी योजना पूर्ण हुई और राज्य की जनता को कितनी योजना समर्पित करने जा रहे हैं, माननीय मंत्री जी थोड़ा बतायेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, ये तो अलग-अलग विभाग का मामला है, विभाग से पूछना पड़ेगा ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, प्रश्न ही यही है । मूल प्रश्न को देखा जाय, इसमें है कि पथ निर्माण विभाग और ग्रामीण कार्य विभाग सहित सभी विभागों में .....

अध्यक्ष : आपके प्रश्न में है कि राशि खर्च नहीं होने का औचित्य, योजना के संबंध में नहीं है। राशि कम खर्च होने के औचित्य पर आपका प्रश्न है । इसलिए हम कह रहे हैं ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, यह राशि जो कम खर्च हुई है,.......

अध्यक्ष : अल्पसूचित प्रश्न ....

श्री ललित कुमार यादव : महोदय,महोदय, यह क्या जवाब हुआ, यह कोई जवाब हुआ ?

अध्यक्ष : जवाब तो बता दिये ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, क्यों कम खर्च हुआ, बाढ़ की विभीषिका आप बताईयेगा, आप अक्टूबर से लेकर ......

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह : अब हो गया न आपका सवाल । महोदय, माननीय सदस्य को यह मालूम है कि जो वर्किंग सीजन है, वह जून से सितम्बर तक वर्किंग सीजन नहीं होता है । सितम्बर के बाद ही वर्किंग सीजन शुरू होता है । इससे माननीय सदस्य भली-भाँति परिचित है । अगर माननीय सदस्य जानना चाहेंगे तो मेरे पास अद्यतन 8 मार्च, 2018 तक के खर्च का ब्यौरा है । माननीय सदस्य अगर जानना चाहेंगे तो विभागवार जो खर्च हुआ है, उसका भी ब्यौरा मेरे पास उपलब्ध है । हम सारा ब्यौरा सदन के पटल पर रख दे रहे हैं । लेकिन 8 मार्च तक माननीय सदस्य को यह बता देना चाहते हैं कि मूल उद्व्यय के विरूद्ध 60.16 प्रतिशत खर्च हो चुका है और संशोधित उद्व्यय के विरूद्ध 55.70 प्रतिशत, पिछले वर्ष की तुलना में 2016-17 की तुलना में अगर आप तुलना करेंगे तो हमारा 4820.10 करोड़ रू0 अधिक उद्व्यय खर्च हुआ है । इसलिए ये सारे खर्च जो है और पूरा मार्च बचा हुआ है । इसलिए खर्च जो सरकार का है, वह है । लेकिन एक बात और बता देते हैं कि मूल राशि खर्च होने में थोड़ी सी कठिनाई आयी, जो केन्द्र प्रायोजित योजनायें हैं, उसमें केन्द्रांश जो हमको जितना मिलना चाहिए, वह पूरा केन्द्रांश नहीं मिला । हमारा जो डिमांड था 31654.68 करोड़ के विरूद्ध 13503.20 करोड़ रू0 हमको सेंट्रल से जो केन्द्र प्रायोजित राशि है, वह विमुक्त हुई है, उसमें लगभग 18 विभाग इसके साथ जुड़े होते हैं,

...... क्रमशः ....

टर्न-2/अंजनी/दि0 09.03.18

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह,मंत्री : ..क्रमशः.. तो इसलिए इसके कारण खर्च में थोड़ी जो कमी आयी है, वह उसके कारण आयी है । सेंट्रल की राशि विमुक्त हो रही है और आ रहा है । जैसे-जैसे आ रहा है, वैसे-वैसे जो मैचिंग ग्रांट है उसको खत्म करके उसको जोड़ा जा रहा है । खर्च हो रहा है ।

श्री ललित कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, हम माननीय मंत्री जी के जवाब को चुनौती देते है और यह बताना चाहते हैं कि जो राशि निकासी की गयी है, जो बैंक में रखी गयी है, एक तरह से जो पी0एन0बी0 में घोटाला हुआ, सृजन में घोटाला हुआ, उसका द्योतक है । महोदय, मैं चुनौती देता हूँ कि राज्य की जनता को कितनी योजना ये समर्पित किये, यह राशि शत-प्रतिशत खर्च नहीं हुई है, यह फेक है महोदय । माननीय मंत्री जी विभागवार

बतायें कि कितना ये राज्य की जनता को योजना समर्पित किये हैं । मैं माननीय मंत्री जी के जवाब को चुनौती देता हूँ ।

अध्यक्ष : पी0एन0बी0 का घोटाला तो दूसरा घोटाला है । वह तो एन0पी0ए0 का पैसा निकालकर .....

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, बैंक में जो राशि रखी गयी है, एक तरह से वह भी घोटाला ही हो गया, आप इसकी जांच कराइए, योजनावार रिपोर्ट दिया जाय ।

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य बड़ा भारी घोटाला की बात कह रहे हैं, एक विभाग का ये लिखकर दें कि कहां का पैसा घोटाला हुआ है, उसकी जांच हो जायेगी, इसमें कौन खास बात है । ऐसे नहीं होता है वेग ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि आपको किसी विभाग की सूचना है कि वह एकाउंट में रखे हुए है, पैसा नहीं निकाल रहा है, नहीं कर रहा है, आप उसकी सूचना दीजिए, वे जांच करा देंगे ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, जनता के राज्य की योजना कितना पूर्ण हुआ है, कितना समर्पित हुआ है, उसी से स्पष्ट हो जायेगा ।

अध्यक्ष : आप उनको दे दीजियेगा, माननीय मंत्री जी जांच करा देंगे ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, उसी में स्पष्ट हो जायेगा कि राशि कहां रखी गयी है, योजना कितनी पूर्ण हुई, योजनावाइज लिस्ट दें, इसलिए आज इस प्रश्न को स्थगित रखा जाय ।

अध्यक्ष : क्यों इस प्रश्न को स्थगित रखा जाय ?

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, हम सदन से चाहेंगे कि कितना योजना पूर्ण हुआ है, ये सदन को बतायें । मैं मंत्री जी के जवाब को चुनौती देता हूँ ।

<u>अल्पसूचित प्रश्न संख्या-14(श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी)</u>

श्री दिनेश चन्द्र यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1- उत्तर स्वीकारात्मक है ।

2- जिला पदाधिकारी, पूर्णियां के प्रतिवेदनानुसार बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा की राशि का अन्तरण सीधे उनके बैंक खाते में किया गया है । दूरभाष पर डगरूआ अंचल में संचालित सामुदायिक रसोई के अधिश्रवण के भुगतान में शिकायत प्राप्त होने पर जांच दल द्वारा जांच करायी गयी है । डगरूआ अंचल के प्रधान लिपिक एवं अंचल नाजिर को निलंबित कर दिया गया है। तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह अंचल अधिकारी, डगरूआ के विरूद्ध प्रपत्र-क में आरोप गठित कर कार्रवाई की जा रही है ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : महोदय, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया कि अनियमितता हुई है और कुछ पदाधिकारियों पर कार्रवाई की गयी है । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि वायसी अनुमंडल के प्रोवेशनल अनुमंडल पदाधिकारी, जो आई0ए0एस0

पदाधिकारी थे, उन्होंने अपना एक जांच करके किन-किनको दोषी करार दिया है, उसकी क्या उच्चस्तरीय समीक्षा हुई है और उस जांच प्रतिवेदन पर कार्रवाई अबतक क्या हुई है? आपने दो आदमी का नाम लिया और डगरूआ प्रखंड के बारे में उन्होंने जो रिपोर्ट किया है, उसमें है कि ब्लॉक एजुकेशन अफसर, ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर, नाजीर, हेड क्लर्क, इनको अनियमितता के लिए उनके जांच प्रतिवेदन में अनियमित पदाधिकारी पाया गया है, इसपर अबतक सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

श्री दिनेश चन्द्र यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जब हम इस प्रश्न की समीक्षा कर रहे थे तो जिला पदाधिकारी, पूर्णियां से हम कहे हैं कि आपने जो जांच कराया है, वह जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराइए लेकिन वह नहीं उपलब्ध हो सका है और हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो जांच रिपोर्ट आयेगा, अभी जो जानकारी जिला पदाधिकारी से मिली है, उसके बारे में तो हम बता दिये, वह भी आयेगा तो उसकी भी जानकारी निश्चित रूप से हम आपको देंगे ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : महोदय, यह तो जवाब ही नहीं हुआ । माननीय मंत्री जी ने खुद स्वीकार किया कि इस प्रश्न की जब उनके स्तर पर समीक्षा की जा रही थी और जिलाधिकारी से जब जांच प्रतिवेदन मांगा गया तो जिला पदाधिकारी ने सरकार को जांच प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया, इसलिए सरकार अपने स्तर से प्रतिवेदन मंगाकर समीक्षा करके तब उत्तर दे तबतक इस प्रश्न को स्थगित रखा जाय महोदय।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि प्रतिवेदन नहीं आया है, इसलिए इस प्रश्न को स्थगित रखा जाता है ।

श्री दिनेश चन्द्र यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, एक घंटा पहले इस प्रश्न की समीक्षा कर रहे थे, जब आयेगा तो आपको निश्चित रूप से बतायेंगे ।

<u>अल्पसूचित प्रश्न संख्या-15(श्री संजय सरावगी)</u>

श्री नंद किशोर यादव, मंत्री : महोदय, उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में क्रय किये गये जीवन रक्षक दवाइयों, सलाइन या अन्य उपचार सामग्रियों को दवा भंडार में ही रखा जाता है । पूर्व में औषधि भंडार में जगह की कमी के कारण आई0डी0एच0 वार्ड के दवा भंडार में कुछ स्लाइन रखा गया था । बरसात में पानी के रिसाव को देखते हुए पुनः इसे अन्य सुरक्षित औषधि भंडार में रख दिया गया । सामान्य भंडार में जगह की कमी के कारण अन्य सामग्री डायट विभाग हेतु चिंहित कमरे में रखा जाता है । बरसात में किसी भी सामग्री की कोई क्षति नहीं हुई है ।

श्री संजय सरावगी : महोदय, यह मेरे क्षेत्र का विषय है और इसके विषय में मुझे पूरी जानकारी है, इसलिए माननीय मंत्री जी से केवल यही आग्रह करना चाहता हूँ कि जो जवाब आया है, उसकी क्या जांच करा देंगे किसी वरीय पदाधिकारी से ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी इसको देखवा लीजियेगा ।

श्री नंद किशोर यादव, मंत्री : महोदय, देखवा लेंगे ।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-16(श्री श्याम रजक)

(व्यवधान)

अध्यक्ष : मैं बार-बार सभी माननीय सदस्यों से कहता हूँ और माननीय मंत्रियों से भी कि जो भी बोलिए आसन की तरफ देखकर, आपस में एक-दूसरे को देखकर बात करने लगते हैं तो बीच में सभी माननीय सदस्यों से लेकर आसन का समय जाया होता है।

श्री नंद किशोर यादव, मंत्री : महोदय, 1-आंशिक स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत राज्य में कुष्ठ, मलेरिया, फाईलेरिया, कालाजार का नियंत्रण हेतु राज्य में मद संबंधी कार्यक्रमों का संचालन एवं पर्यवेक्षण निमित्त राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी के रूप में चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति की जाती है । कार्यक्रमों का संचालन एवं पर्यवेक्षण हेतु अनुभवी सामान्य चिकित्सक/विशेषज्ञ चिकित्सक तथा इस क्षेत्र में विशिष्ट योग्यताधारी पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल की सेवा भी उपलब्धता के आधार पर ली जाती है ।

2 एवं 3- उपरोक्त खंडों के उत्तर से स्वत: स्पष्ट है ।

श्री श्याम रजक : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी जो जवाब दे रहे हैं कि विशेषज्ञों को हमलोग वहां पर रखते हैं, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ कि कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम में राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी डा0 विजय कुमार पाण्डेय हैं, जो जेनरल फिजिशियन हैं । मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी डॉ0 एम0एम0पी0 सिन्हा हैं जो जेनरल फिजिशियन हैं- इन्हें न तो कुष्ठ रोग की विशेषज्ञता हासिल है, न कालाजार रोग की और ये कालाजार रोग के भी राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी हैं । फलेरिया नियंत्रण में राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी डा0 बिपिन कुमार सिन्हा हैं । ये भी फलेरिया रोग के कोई विशेषज्ञ नहीं हैं । जबकि सरकार के जो कार्यक्रम हैं, अगर उसे पढ़े तो बहुत समय लग जायेगा । कई कार्यक्रम हैं जिससे कि कुष्ठ रोग, फलेरिया रोग, मलेरिया रोग, कालाजार पर रोक लगाया जा सकता है, लेकिन इसके विशेषज्ञ के नहीं रहने के कारण इस कार्यक्रम में इलाज नहीं हो रहा है और कार्यक्रम का लाभ नहीं मिल रहा है । सरकार चाहती है, लेकिन उसके बाद भी लाभ नहीं हो रहा है । मैं जानना चाहता हूँ कि क्या विशेषज्ञों की वहां पर पदस्थापन करना चाहेंगे, जल्द से जल्द ?

टर्न-3/शंभु/09.03.18

श्री नन्दकिशोर यादव, मंत्री : महोदय, मैंने अपने उत्तर में इस बात का जिक्र किया है कि इस कार्यक्रम के संचालन के लिए और पर्यवेक्षण के लिए अनुभवी सामान्य चिकित्सक, विशेषज्ञ चिकित्सक मैंने दोनों का जिक्र किया है- माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं कि जिन चिकित्सकों का नाम उन्होंने लिया है वे सामान्य चिकित्सक हैं, लेकिन इस विषय में अनुभवी हैं । महोदय, माननीय सदस्य भी जानते हैं कि विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ चिकित्सकों की केवल राज्य में नहीं देशभर में कमी है तो उस कमी के कारण हम इन योजनाओं को बंद कर दें, हम इन योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं करें, पर्यवेक्षण नहीं करें- यह कहीं से भी राज्य के लोगों के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है । इसलिए जो सामान्य चिकित्सक इस क्षेत्र के जो अनुभवी हैं, जानकार हैं, हम उनको इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं ताकि यह कार्यक्रम चल सके । इस राज्य के अंदर कुष्ठ नियंत्रण के लिए, मलेरिया नियंत्रण के लिए, फलेरिया नियंत्रण के लिए और कालाजार के लिए जो कार्यकल चलाये जा रहे हैं उसका क्रियान्वयन ठीक से हो सके ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, ये मलेरिया, फाईलेरिया, कालाजार इन सब बीमारियों की विशेषज्ञता का कोई मेडिकल कोर्स में अलग पाठ्यक्रम होता है क्या ?

श्री नन्दकिशोर यादव,मंत्री : महोदय, यह तो सामान्य चिकित्सकीय.........

अध्यक्ष : वही तो हम समझना चाह रहे थे कि आप कह रहे थे कि सामान्य चिकित्सक देखते हैं विशेषज्ञ नहीं हैं । क्या इन बीमारियों की विशेषज्ञता की कोई अलग पढ़ाई होती है ?

श्री नन्दकिशोर यादव,मंत्री : महोदय, पढ़ाई अलग नहीं होती है, लेकिन मैंने कहा अनुभवी सामान्य चिकित्सक तो अनुभवी सामान्य चिकित्सक का अर्थ जरूर है कि जो इस विषय में थोड़ी जानकारी रखते हों........व्यवधान..अरे भाई मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ । अब इनका जवाब तो होने दीजिए न । इसलिए मैंने कहा महोदय, अनुभवी सामान्य चिकित्सक चूंकि इसकी अलग से कोई पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन जो चिकित्सा का इस विषय में अनुभव रखते हों उनको ही इस काम में हम लगाते हैं ताकि कार्यक्रम ठीक से चल सके ।

श्री श्याम रजक : इन्होंने कहा अनुभवी हैं, हम चुनौती देना चाहते हैं कोई अनुभवी नहीं है और न इनकी ट्रेनिंग हुई है इन बीमारियों की जॉच के लिए । हम जानना चाहते हैं कि क्या ट्रेनिंग कराकर ऐसे लोगों की पोस्टिंग करना चाहेंगे ?

श्री नन्दकिशोर यादव,मंत्री : महोदय, हमने कहा है कि अनुभवी हैं तो अनुभवी हैं और यदि माननीय सदस्य को यह लगता है कि अनुभवी नहीं हैं, पता नहीं कैसे इनको अनुभव है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अगर माननीय सदस्य को लगता है तो हम इसको देखवा लेते हैं । यह होना ही चाहिए ।

तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न सं0-827(सुश्री पूनम कुमारी उर्फ पूनम पासवान)

श्री नन्दकिशोर यादव,मंत्री : महोदय, उत्तर स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि सरकार द्वारा सभी स्वास्थ्य केन्द्रों के चहारदीवारी निर्माण कराने का निर्णय लिया गया है । जिसे चरणबद्ध ढंग से कराया जाना है । विहित प्रक्रिया के अनुसार निर्णय के उपरान्त राशि उपलब्ध होने पर ग्राम पंचायत भंगहा स्थित स्वास्थ्य उपकेन्द्र के चहारदीवारी निर्माण कार्य प्राथमिकता पर करायी जायेगी । भूमि अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, फलका द्वारा अंचल पदाधिकारी फलका से अनुरोध किया गया है ।

सुश्री पूनम कुमारी उर्फ पूनम पासवान : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जो अतिक्रमण है, वहां पर घर भी बन गया है काफी लोगों का, वहां पर लोग बस भी रहे हैं। दूसरी चीज है कि घेराबन्दी सभी स्वास्थ्य केन्द्र की, लेकिन वहां पर माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि कब तक वहां पर इस तरह की व्यवस्था की जायेगी, जिससे कि और भी लोग जो अतिक्रमण कर रहे हैं, उनको रोका जा सके।

श्री नन्दकिशोर यादव,मंत्री : महोदय, मैंने कहा कि अतिक्रमण हटाने के लिए अंचलाधिकारी फलका से अनुरोध किया गया है और वे उसपर कार्रवाई करेंगे । हमलोग उसको देखेंगे कि उसपर कार्रवाई हो । दूसरा महोदय, मैंने कहा आपसे कि पूरे राज्य के अंदर ऐसे स्वास्थ्य केन्द्रों की चहारदीवारी हम कराना चाहते हैं, लेकिन राज्य के सभी केन्द्रों की चहारदीवारी एक साथ संभव नहीं है, हम क्रमवार ढंग से इसको करेंगे । हम जरूर इन्होंने जो प्रश्न में जिन चीजों का जिक्र किया है, उसका विशेष ध्यान रखेंगे ।

तारांकित प्रश्न सं0-828(श्रीमती स्वीटी सीमा हेम्ब्रम)

श्री नन्दकिशोर यादव,मंत्री : उत्तर अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि संगा पंचायत के पथरिया गांव में स्वास्थ्य उपकेन्द्र खोलने का निर्णय नहीं लिया गया है । यहां स्वास्थ्य उपकेन्द्र स्वीकृत नहीं है । संगा पंचायत के अन्तर्गत भुरभुरी एवं रांगदा में स्वास्थ्य उपकेन्द्र स्वीकृत एवं कार्यरत है । जो पथरिया गांव से 3-4 कि0मी0 की दूरी पर अवस्थित है ।

श्रीमती स्वीटी सीमा हेम्ब्रम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यही आग्रह करूँगी कि वह अगर स्वीकृत नहीं है तो कब तक वहां पर पथरिया गांव अन्तर्गत वे स्वीकृत करायेंगे ? मैं चाहूंगी कि उस क्षेत्र में 3-4 कि0मी0 जो आप कह रहे हैं वह लगभग 7 कि0मी0 की दूरी पर है । वहां की जनता को परेशानी होती है तो मैं यही इनसे आग्रह करूँगी कि कब तक उसको स्वीकृत करेंगे ? यह जानना चाहेंगे आपसे ।

श्री नन्दकिशोर यादव,मंत्री : महोदय, आप जानते हैं कि स्वास्थ्य उपकेन्द्र के चयन की एक प्रक्रिया है- सामान्य तौर पर 5 हजार की आबादी पर एक स्वास्थ्य उपकेन्द्र खोलने का विचार सरकार ने किया था और जिला अधिकारी की अध्यक्षता में कमिटी थी जो कमिटी इस बात का निर्णय करती थी कि इस 5 हजार की आबादी में कहां-कहां स्वास्थ्य उपकेन्द्र खोला जाय । वहां के

जिला अधिकारी ने जो रिपोर्ट दिया है उसके आधार पर स्वास्थ्य उपकेन्द्रों का चयन किया गया, वहां खोला भी गया है, लेकिन जो प्रश्नगत गांव है वहां के बारे में कोई रेकोमेन्डेशन नहीं आया है, इसलिए खोलने का विचार नहीं है । फिर भी अगर माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है मैं विभाग को जरूर कहूँगा कि इसको देखे ।

श्रीमती स्वीटी सीमा हेम्ब्रम : अध्यक्ष महोदय, यह रिपोर्ट इनको गलत दिया गया है ।

अध्यक्ष : उन्होंने कहा है कि देखवा लेंगे ।

श्रीमती स्वीटी सीमा हेम्ब्रम : चूंकि मैं उस क्षेत्र की जनप्रतिनिधि हूॅ । वे देखवा लें बेहतर होगा।

तारांकित प्रश्न सं0-829(श्री अशोक कुमार सिंह-अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-830(श्री सुधांशु शेखर-अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-831(श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह)

श्री नन्दकिशोर यादव,मंत्री : महोदय, 1-उत्तर अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि स्वस्थ्य उपकेन्द्र बेलासपुर अपने जर्जर भवन में संचालित है । जहां ए0एन0एम0 के द्वारा टीकाकरण एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं उपलब्ध करायी जा रही है ।

2- आंशिक स्वीकारात्मक है । स्वास्थ्य उपकेन्द्र बेलासपुर के नजदीक में ही दूसरा भवन, भवन निर्माण के द्वारा बनाया जा रहा है । भवन तैयार होते ही इसे स्वास्थ्य उपकेन्द्र के रूप में स्थापित कर दिया जायेगा ।

3- उपरोक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है ।

श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, ये चन्द्रगढ़ से संबंधित प्रश्न है- प्रश्नगत चन्द्रगढ़ पंचायत के बेलासपुर गांव में स्वास्थ्य केन्द्र में भवन के लिए काम लगा था और वह अधूरा बिल्डिंग पड़ा हुआ है तो अस्वीकारात्मक कैसे हुआ ? हमको समझ में नहीं आया। ऐसा एक दो जगह नहीं है, कई एक जगह है हमारे प्रखंड में जहां लिंटर लेवेल तक स्वास्थ्य भवन बन गया उप स्वास्थ्य केन्द्र और अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र और अब जो ठीकेदार छोड़कर भाग गया, इसके बाद उसका निर्माण हो ही नहीं रहा है । वह निर्माण होगा कि नहीं होगा, इस संबंध में हम सरकार से जानना चाहते हैं ?

श्री नन्दकिशोर यादव,मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य का प्रश्न जायज है, लेकिन मैंने कहा है कि जो भवन बन रहा है वह भवन पूरा हो जायेगा तो उसको हम शिफ्ट करेंगे । महोदय, आपको ध्यान में होगा कि पहले स्वास्थ्य विभाग भवनों का काम नहीं करता था और अस्पतालों के निर्माण के लिए जो राशि स्वास्थ्य विभाग को मिलती थी वह भवन निर्माण विभाग के माध्यम से ही भवनों के निर्माण का काम किया जाता था, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गयी है । अब स्वास्थ्य विभाग ने अलग से कॉरपोरेशन बनाया है जिसके माध्यम से भवनों के निर्माण का काम करते हैं, लेकिन यह प्रश्न पुराने समय का है और स्वास्थ्य विभाग भवन निर्माण विभाग

से समन्वय बैठाकर के जो अधूरे भवन हैं उनको शीघ्र पूरा करने की कोशिश कर रहा है । मैं समझता हूँ कि जरूर इसपर सकारात्मक परिणाम दिखायी पड़ेगा ।

तारांकित प्रश्न सं0-832(श्री आबिदुर रहमान-अनुपस्थित)

टर्न-4/अशोक/09.03.2018

तारांकित प्रश्न संख्या-833(डा0 विनोद प्रसाद यादव)

अध्यक्ष : श्री अशोक कुमार जी पूछेंगे । पर्यटन विभाग ।

श्री प्रमोद कुमार, मंत्री : जिला पदाधिकारी, गया से विभागी ज्ञापांक-290, दिनांक 15.02.2018 एवं पत्रांक -464 दिनांक 07.03.2018 द्वारा प्रतिवेदन की मांग की गयी है । प्रतिवेदन प्राप्त होने पर निधि की उपलब्धता तथा प्राथमिकता के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी । इस स्थल को निर्माणाधीन पर्यटन रोडमैप में सम्मलित कर लिया गया है । तत्काल पर्यटन विभागमें उक्त स्थल के लिए कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

तारांकित प्रश्न संख्या-834(श्री ललन पासवान)

श्री नंद किशोर यादव, मंत्री : उत्तर स्वीकारात्मक है ।

विकसित बिहार के सात विनिश्यचयों मे से एक " अवसर बढ़े, आगे पढ़े " के अन्तर्गत राज्य में तकनीकी शिक्षा के अवसरों को और बढ़ाने एवं युवाओं को राज्य में ही शिक्षण-प्रशिक्षण को बेहतर अवसर सप्रदान किये जाने के उद्येश्य से प्रत्येक जिला में एक पारा-मेडिकल संस्थान एवं प्रत्येक अनुमंडल में एक ए0एन0एम0 स्कूल की स्थापना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

उपरोक्त के अन्तर्गत रोहतास जिला में एक पारा मेडिकल संस्थान एवं रोहतास जिला के विक्रमगंज अनुमण्डल में ए.एन.एम. स्कूल की स्थापना की जा रही है ।

श्री ललन पासवान : महोदय, विक्रमगंज-सासाराम माननीय मंत्री जी कह रहे हें लेकिन 120 कि.मी. की दूरी पर, मैं सदन को बतलाना चाहता हूँ कि डिहरी से 120 कि.मी. कीइ दूरी है नौहट्टा का जगन्नाथपुर का, वह सुदूर इलाका है, पूरा उग्रवाद इलाका है, मेडिकल की जो सदर अस्पताल की जो हालत हैं बड़ा परेशानी का है, बड़ी दिक्कत का है और पहाड़ से 70-80 गांव के लोग उतर कर आते हैं, प्रसव से लेकर सारे रोगों का, काला जार से लेकर मलेरिया तक, इसलिए वहां , हमारे यहां बड़ी परेशानी है, नौहट्टा-रोहतास में । इसमें माननीय मंत्री से कहेंगे कि आप विक्रमगंज में खोल दिये तो डिहरी अनुमण्डल में जो खोलना हैं, पौंलिटेकनिक कॉलेज आपने खोल दिया डेहरी में और सरकार की व्यवस्था है लेकिन एक नौहट्टा-रोहतास में बीच का सेन्टर है, 4-5 प्रखण्ड के बीच में, बगल में तिलौथू

है, बगल में अमझौर है, नौहट्टा-रोहतास है, इसलिए एक आग्रह है माननीय मंत्री जी से कृपा कर जवाब दीजिये कि कम कसे कम नौहट्टा-रोहतास में भी कृपा कर दीजिये, सरकार कृपा करे तो नियम के अनुसार से एक अनुमण्डल डिहरी भी है, एक अनुमण्डल डिहरी के आधार पर उसमें भी खोला जा सकता है नौहट्टा-रोहतास में माननीय मंत्री जी ।

श्री नंद किशोर यादव, मंत्री : महोदय, इसको मतलब इस संस्थान को चिकित्सा सुविधा से कोई सीधा तालमेल नहीं है, वह तो जो अस्पताल है स्वास्थ्य प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, वहां भी महोदय इलाज होता है, यह तो ट्रेनिंग देने के लिए है और महोदय थोड़ा देर कर दिया है ललन जी, सब आर्डर हो गया है, महोदय पारा मेडिकल संस्थान के आधारभूत संरचना लगभग 45 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है महोदय, और यथाशीघ्र हम उसको पूरा करने जा रहें हैं । यह जो विक्रमगंज अनुमण्डलन का ए.एन.एम. प्रशिक्षण संस्थान है महोदय इसका भी टेण्डर हो गया है और इसको वर्क आर्डर भी दिया जा चुका हैं। इसलिए महोदय इसका काम भी शीघ्र प्रारम्भ हो जायेगा । माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है विभाग जरूर इसकरे बारे चिंता करेगा, देखेगा।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-835(श्री रामचन्द्र सहनी)</u>

अध्यक्ष : सचीन्द्र जी पूछेंगे । स्वास्थ्य विभाग ।

श्री नंद किशोर यादव, मंत्री : महोदय, आंशिक स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द रामगढ़वा को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द में उत्क्रमित किया गया है, जिसका निर्माण Multi Sectoral Development Programme योजना के अन्तर्गत किया जा रहा है । वर्त्तमान में वहॉ पॉच चिकित्सक एवं दो आयुष चिकित्सक एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा स्वास्थ्य सुविधा दी जा रही है । भवन निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के अनुरूप चिकित्सक एवं चिकित्सीय उपकरण उपलब्ध कराया जाएगा ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, भवन निर्माण की प्रक्रिया कब तक पूरी हो जायेगी, आंशिक स्वीकारात्मक है तो इसका मतलब है कि कुछ कमी है ।

श्री नंद किशोर यादव, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य जानते हैं कि बिहार के अन्दर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में परिवर्त्तित किया जा रहा है । पहले जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 6 बेड के हुआ करते थे अब उनको 30 बेड का अस्पताल के रूप क्रमवार ढंग से परिवर्त्तित किया जा रहा है और उसके निर्माण का कार्य, अस्पताल के निर्माण का कार्य चल रहा है और जिन उपकरणें की चर्चा माननीय सदस्य ने की है महोदय, अस्पताल के भवन के निर्माण के काम जल्दी

पूरा हो जाय इसकी हम कोशिश कर रहे हैं । जब परू हो जायेगा हम उसमें उपकरणादि की व्यवस्था जल्दी करेंगे ।

श्री ललित कुमार यादव : महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाह रहा हूँ, माननीय मंत्री ने अपने जवाब में बतलाये हैं राज्य के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को अपग्रेड किया जा रहा है तो हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि क्या राज्य में जितने उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं उन सभी का कि उसमें चिन्हित हैं?-यह थोड़ा स्पष्ट जानना चाहेंगे।

श्री नंद किशोर यादव,मंत्री : महोदय, ये तो पुराने आदमी है महोदय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से स्वास्थ्य केन्द्र पर आ गये, फिर कह देंगे स्वास्थ्य उपकेन्द्र फिर कह देंगे अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, महोदय मैंने कहा कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है उनको धीरे धीरे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में परिवर्त्ति करने का हमारा लक्ष्य है । और हम क्रमवार ढंग से हम सब को करेंगे धीरे-धीरे ।

श्री ललित कुमार यादव : शतप्रतिशत कर रहे हैं या कुछ चिन्हित करके कर रहे हैं ?

श्री नंद किशोर यादव, मंत्री : महोदय, अरे टेलमा दे क्या, टेलमा-40 दें, टेलमा-80 दे ? टेलमा-40 दें । क्या दिक्कत हो रहा है आपको भईया ।

तारांकित प्रश्न संख्या-836(श्री(मो.) आफाक आलम)

माननीय सदस्य श्री (मो.) आफाक आलम- अनुपस्थित ।

तारांकित प्रश्न संख्या-837(श्री फैयाज अहमद)

माननीय सदस्य श्री फैयाज अहमद- अनुपस्थित ।

तारांकित प्रश्न संख्या-838(श्री लक्ष्मेश्वर राय)

श्री नंद किशार यादव, मंत्री : खंड-1: आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

स्वास्थ्य उपकेन्द्र, ललमनिया एवं नेउर नेपाल के सीमावर्त्ती क्षेत्र में स्थित है जबकि रतौली सीमावर्त्ती क्षेत्र में अवस्थित नहीं है ।

खंड-2: आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण संबंधी कार्रवाई जिला संचालन समिति के स्वीकृति के पश्चात विहित प्रक्रियानुसार किया जाएगा ।

खंड-3: उपरोक्त खंडों में स्थिति स्पष्ट है ।

अध्यक्ष : ठीक ।

तारांकित प्रश्न संख्या-839(श्री सदानंद सिंह)

अध्यक्ष : श्री रामदेव राय जी पूछेंगे । (माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अनुपस्थित) दोनों माननीय सदस्य अनुपस्थित हैं ।

तारांकित प्रश्न संख्या-840(श्री चन्द्रसेन प्रसाद)

अध्यक्ष : श्री लक्ष्मेश्वर राय पूछेंगे । उर्जा विभाग । आपका तो पहला ही धराया है ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : सब तो अबसेन्ट ही हैं तो हम क्या करें ।

खंड-1: नालंदा जिलान्तर्गत इसलामपुर प्रखंड के जैतीपुर बाजार एवं इसके आस-पास के क्षेत्रों में विद्युत की आपूर्त्ति 33/11 के0भी0 शक्ति उपकेन्द्र मुसहरी से होती है जिसकी दूरी मुसहरी शक्ति उपकेन्द्र से लगभग 10 कि.मी. है ।

जैतीपुर बाजार एवं इसके आस-पास के क्षेत्रों की विद्यत आपूर्त्ति में सुधार हेतु जैतीपुर बाजार से लगभग 3-4 कि.मी. हटकर जमुआवॉ ग्राम में 2x5 MVA का शक्ति उपकेन्द्र के निर्माण का प्रताव दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में स्वीकृत है, जिसको दिसम्बर 2018 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है । निर्माण कार्य भी प्रारम्भ हो गया है ।

अत: जैतीपुर बाजार में शक्ति उपकेन्द्र का निर्माण किया जाना तकनीकी दृष्टिकोण से आवश्यक नहीं है ।

तारांकित प्रश्न संख्या-841(श्री(डा.) विनोद प्रसाद यादव)

अध्यक्ष : श्री अशोक कुमार जी पूछेंगे । विधि विभाग ।

श्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद, मंत्री:खंड-1 : स्वीकारात्मक है ।

खंड-2 : स्वीकारात्मक है ।

खंड-3 :राज्य में किसी भी नये न्यायालय की स्थापना माननीय उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है ।

शेरघाटी व्यवहार न्यायालय में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नयायालय की स्थापना हेतु माननीय उच्च न्यायालय के निदेशानुसार राजपत्रित पद का सृजन किया जा चुका है। संबद्ध अराजपत्रित पदों का सृजन संप्रति प्रक्रियाधीन है सभी पदों के सृजनोपरान्त माननीय उच्च न्यायालय के परामर्श से ही शेरघाटी में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय की स्थापना पर निणर्य लिया जा सकेगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या-842(श्री (डा.) अब्दुल गफूर)

श्री नंद किशोर यादव, मंत्री : उत्तर अस्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि सहरसा के महिषी प्रखड अन्तर्गत अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुन्दह एवं तेलवा चालू अवस्था में है । विगत माह में अतिरिक्त प्राथमिक सवस्य केन्द्र कुन्दह में OPD में कुल 1143 मरीजों का इलाज किया गया है तथा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तेलवा में OPD में कुल 966 मरीजों का इलाज किया गया है ।

अतिरिक्त प्राथमिक स्वस्थ्य केन्द्र कुन्दह में एक चिकित्सा पदाधिकारी, एक आयुष चिकित्सक तथा चार पारा मेडिकल पदस्थापित हैं ।

अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तेलवा में एक आयुष चिकित्सक एवं एक पारा मेडिकल कार्यरत है, जिससे उक्त संस्थानों में चिकित्सीय कार्य लिया जाता है ।

टर्न-5/09-03-2018/ज्योति

डा0 अब्दुल गफूर : अध्यक्ष महोदय, यह मेरे क्षेत्र के अलावा दोनों हौस्पिटल मेरे गांव के बगल का है और हमलोग देखते हैं बराबर, एकदम बंद रहता है, शत प्रतिशत बंद है, जो रिपोर्ट है कंपाउन्डर वगैरह बनाकर दे दिया है, बिल्कुल 100 परसेंट फेक रिपोर्ट है। माननीय मंत्री जी से चूँकि प्रभारी मंत्री हैं, दूसरे मंत्री हैं लेकिन इसपर कार्रवाई होनी चाहिए, इस गलत रिपोर्ट पर जो इस तरह से झूठा रिपोर्ट है । हौस्टिपल की तो बिल्डिंग भी नहीं है कुन्दा में, तेलबा में बिल्डिंग है, कई बार हमलोग जाकर ग्रामीण को जमा करके, कंपाउन्डर एक उस गांव का है, उसको कहते हैं कि भाई सफाई भी तो रखो । कुछ नहीं है, साफ बंद है, 15 साल से बंद है, एक दो साल से नहीं बंद है ।

अध्यक्ष : ठीक है, तो पूरक पूछ लीजिये ।

डा0 अब्दुल गफूर : डॉक्टर की पोस्टिंग होती है । हमलोग यहां आग्रह करके - उसको चालू कराना चाहते हैं कि चालू करा दीजिये डौक्टर रहे, इसकी व्यवस्था करा दीजिये इंटेरियर इलाका है, बाढ़ प्रभावित इलाका है । सहरसा ही रहना पड़ता है लोगों को

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, उसको देख लीजिये कि वह केन्द्र चले ।

श्री नंद किशोर यादव, मंत्री : ठीक है ।

डा0 अब्दुल गफूर : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से जवाब तो दिलवा दीजिये ।

अध्यक्ष : मंत्री जी कह दिए कि उसको चालू करवायेंगे उसमें सहमति बताये हैं ।

तारांकित प्रश्न संख्या 843 (डा0 रामानुज प्रसाद)

श्री दिनेश चंद्र यादव (मंत्री): अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सारण जिलान्तर्गत वर्ष 2016 में_बाढ़ के कारण प्रभावित परिवारों के सर्वेक्षण के उपरांत जिला पदाधिकारी, सारण द्वारा अधियाचित आवंटन के आलोक में विभाग द्वारा राशि आवंटित कर दी गयी है, जिसके आलोक में दिघवारा अंचल में कुल 18,946 बाढ़ प्रभावित परिवारों को अनुग्रही सहाय्य राशि जी.आर. का भुगतान किया जा चुका है, साथ ही दिघवारा नगर पंचायत के 4086 परिवारों को भी जी.आर. राशि का भुगतान किया गया है । चूँकि वर्ष 2016 में आयी बाढ़ के पश्चात् लम्बी अवधि के उपरांत दिसम्बर, 2017 में जिला पदाधिकारी द्वारा

दिघवारा नगर पंचायत के बाढ़ से प्रभावित अन्य 4430 परिवारों के लिए जी.आर. राशि की मांग की गयी है । अत: विभाग द्वारा इस मामले को मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य कार्यकारिणी समिति में रखने का निर्णय लिया गया है । राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में अग्रतर कार्रवाई की जायेगी ।

डा0 रामानुज प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी कार्रवाई की जायेगी, यह बात कह रहे हैं । कब तक कार्रवाई की जायेगी, कब तक बाढ पीड़ितों को राशि वितरित कर दी जायेगी, इसका समय कुछ बता दें, कार्रवाई की जायेगी यह नहीं है, जहॉ तक सवाल है, वह जो आंकड़ा मंत्री जी के पास भेजा गया है, वह गलत है । ये मैं कह रहा हूॅं, वहॉ हमलोगों को झेलना पड़ता है, इसकी आप जॉच करवाईये न ? सिर्फ दिघवारा में बल्कि सोनपुर में, छपरा में, तरैया में, मढ़ौरा में, हमारे यहॉ जब बाढ़ पीडितो के लिए सम्पर्क करते हैं, पदाधिकारियों से तो होता है कि राशि की अनुपलब्धता के कारण नहीं हमलोग दे पा रहे हैं, कब तक सरकार प्रक्रिया पूरी कर राशि भेजवाने का काम करेगी और वितरित करवायेगी ?

श्री दिनेश चंद्र यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, चूंकि यह मामला बहुत पुराना हो गया है 2016 का है और अब अपने प्रश्न के उत्तर में जो हम जानकारी आपको दिए हैं, तो इसको मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली जो कमिटी है, राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में इसको रख कर जो जिला पदाधिकारी राशि की मांग किए हैं उसको रख कर जिस तरह का निर्णय होगा आगे कार्यवाही निश्चित रुप से करायेंगे ।

डा0 रामानुज प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूॅं कि यह प्रक्रिया पूरी कर, सरकार अपने पदाधिकारियों के समक्ष रखकर अपने कर्त्तव्यों का इतिश्री मान लेती है तो दूसरी बात है अन्यथा मंत्री जी ये कहें कि जो रखा गया है कमिटी के सामने, उससे आप आगे बढ़कर लॉबी करके, आदेश करके निदेश दे करके, करवा देंगे, बंटवा देंगे, यह आश्वासन मंत्री जी, आपसे चाहिए ।

श्री दिनेश चंद्र यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, विभाग का जवाब तो स्पष्ट है कि जो बाढ़ में जिला पदाधिकारी ने राशि की मांग की है, तो चूॅंकि पुराना मामला है । यह तो प्रक्रिया है जो चीफ सेक्रेट्री की अध्यक्षता में बैठक में जो निर्णय होगा उसपर जल्द कार्रवाई करेंगे । डेट तो हम तय नहीं कर सकते कि हम अध्यक्ष तो उस कमिटी के है नहीं, इसलिए जब रिपोर्ट चली जायेगी, उस कमिटी में तो जो भी निर्णय होगा, तो पीड़ित के हक में तो सरकार काम करती है थोड़ी भी गुंजाईश होगी, तो उसको देखेंगे ।

डा0 रामानुज प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को कहना चाहता हूॅं कि 2017 में भी इसका वितरण नहीं हुआ है । उस समय के बाढ़ पीड़ितो के बीच नहीं हुआ है, आप इसको पुराना मामला बता रहे हैं तो नये मामले का ही हल करा दीजिये और पुराने मामले को भी हल कराईये, 2017 में भी नहीं बंटा है ।

अध्यक्ष : अब तारांकित प्रश्न संख्या 844 (श्री मो0 अफाक आलम)

श्री रामदेव राय : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न छूट गया है ।

अध्यक्ष : हम तो पुकारे थे आपका नाम । अच्छा ठीक है, आप बैठिये ।

श्री मुद्रिका प्रसाद राय : अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2017 में तरैया, पानापुर में बाढ़ आयी थी और मरौढ़ा में भी, मसरख में भी और वहॉं की स्थिति जो है, तो अभी तक न जी.आर. की राशि पहुंची और न फसल क्षति का मिला, तो कब तक सरकार ..

अध्यक्ष: वह सब सूचना माननीय मंत्री जी को दे दीजियेगा, अलग से वह देखवा लेंगे ।

श्री अमित कुमार : अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी के सुप्पी, बैरगनियॉं और रीगा में भी बाढ़ पीड़ितो के लिए राहत राशि नहीं पहुंची है ।

तारांकित प्रश्न संखया 844 (श्री मो0 अफाक आलम- अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या 845 (श्री हरि शंकर यादव)

श्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न विधि विभाग से संबंधित नहीं है । यह तो नगर विकास विभाग को जाना चाहिए ।

अध्यक्ष : नगर विकास विभाग में, ठीक है, स्थानांतरित । तारांकित प्रश्न संख्या 846(श्री तार किशोर प्रसाद).....

श्री नंद किशोर यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1- उत्तर अस्वीकारात्मक है ।..

श्री हरिशंकर यादव : अध्यक्ष महोदय, बहुत महत्वपूर्ण विषय है ।

अध्यक्ष : यह स्थगित हुआ है वह अगले दिन आयेगा ।

डा0 अब्दुल गफूर : यह अल्प संख्यक विभाग का है नगर विकास विभाग क्या करेगा ।

अध्यक्ष : तो अल्प संख्यक विभाग को ही भेज दिया जायेगा ।

श्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद,मंत्री : महोदय, यह अल्प संख्यक विभाग का नहीं है । यह नाली के पानी से संबंधित है सिवान शहर का , पानी- नाला वगैरह का काम करने का तो वह तो है नगर विकास विभाग देखता है, अल्प संख्यक विभाग तो देखता नहीं है ।

श्री हरिशंकर यादव : शहर का नहीं है, पंचायत का है , हुसैनगंज पंचायत का सवाल है ।

अध्यक्ष : अगर यह पंचायत का, देहात का एरिया है तब तो फिर पंचायती राज विभाग को चला जायेगा, फिर यह ग्राम पंचायत को चला जायेगा ।

श्री हरि शंकर यादव : सर, जहॉं से मिले, वह पानी को बंद करवाया जाय । नमाजी जो आते हैं गंदा पानी लांघ कर जाते हैं । यह बहुत समस्या है । हम कई बार चिट्ठी लिख चुके हैं।

अध्यक्ष : ठीक है, इसको देखवा कर, कर लीजिये ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या 846 (श्री तार किशोर प्रसाद)</u>

श्री नंद किशोर यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 1- अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि राष्ट्रीय अंधापन निवारण कार्यक्रम के द्वारा वर्ष 2017 में कोई सर्वे नहीं किया गया है । भारत सरकार के अनुमोदन के पश्चात् एम्स, नई दिलली के चयनित दल द्वारा बिहार के दो जिले क्रमशः वैशाली एवं सीतामढ़ी में अंधतत्व की दर निर्धारण हेतु सर्वे किया गया है, जिसका प्रतिवेदन प्राप्त नहीं है ।

2- अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि राष्ट्रीय अंधापन निवारण कार्यक्रम के अधीन स्कूली बच्चों के नेत्र का परीक्षण किया जाता है । वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल 5,25,227 बच्चों के नेत्रों की जॉच जिलों द्वारा की गयी जिसमें कुल 8,776 बच्चों में दृष्टिदोष पायी गयी जो कुल स्क्रीनिंग का 1.68 प्रतिशत है । कुपोषण दूर करने के लिए राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की गई है । अन्य कारणों से कुपोषण आधारित बीमारी के लिए रेफरल व्यवस्था भी लागू है ।

3- उपरोक्त खण्ड में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

श्री तार किशोर प्रसादः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने अपने जवाब में जो प्रतिवेदन है जांच एजेन्सी याा सर्वेक्षण एजेन्सी का, उसको नकारा है लेकिन जहॉ तक मुझे तथ्यात्मक जानकारी हे, वह सर्वेक्षण हुआ भी है और उसमें जो तथ्य आए हैं, वह सही हैं । भारत सरकार..

अध्यक्ष : इसमें आपने लिखा है कि राष्ट्रीय अंधता निवारण कार्यक्रम एजेन्सी और सी.ए.बी.- एक चीज हम सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहते हैं कि हम आए दिन देखते हैं कि बराबर समाचारपत्रों में छपी हुई, खबरों के आधार पर, प्रश्न पूछे जाते हैं, यह अच्छी बात है, समाचार पत्रों का भी काम है कि पूरे प्रदेश में जहॉ कहीं सरकारी काम में या जनता को परेशानी की चीज है, उसको उजागर करने का, माननीय सदस्यों का भी यह कर्त्तव्य है कि अगर कोई चीज संज्ञान में आती है, तो उसके संबंध में प्रश्न पूछने का लेकिन आए दिन होता है कि अगर समाचारपत्रों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे अभी ही माननीय मंत्री ने कहा कि ऐसा कोई सर्वे नहीं हुआ है और

क्रमशः

टर्न-6/09.3.2018/बिपिन

अध्यक्ष : क्रमशः... जो बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली है, उसमें भी स्पष्ट उल्लेख है कि समाचार पत्रों की खबरों के आधार पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं लेकिन समाचार पत्रों की उन खबरों की जो वेरैसिटी होती है, उसकी सत्यता होती है, उसके लिए पहले आपको जांच कर लेनी चाहिए । वह आपको अपनी तया जांच करने के बाद ही पूछना चाहिए, यह आपकी नियमावली में भी वर्णित है । इसलिए मैं, यह जो

सदन में होता है कि आप कोई समाचार पत्र के आधार पर प्रश्न पूछे और सरकार कह रही है कि ऐसा कोई सर्वे हुआ ही नहीं है । सदस्यों को भी सुविधा होगी और सदन में सही प्रश्नों पर सही विमर्श भी होगा कि अगर समाचार पत्र की खबरों पर आधारित प्रश्नों को पूछने से पहले माननीय सदस्यगण अगर उसकी सत्यता के संबंध में खुद भी अगर कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो इससे अच्छा एक माहौल भी बनेगा और सदन का समय भी सही जाएगा ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी: महोदय, माननीय सदस्य को यह अधिकार है कि जिस श्रोत से भी हो, सूचना ग्रहण करने के आधार पर प्रश्न पूछे । सरकार को जवाब देना है सही है या गलत है । यह ठीक है, व्यक्तिगत् हमारी रेस्पौंसिबिलीटी है कि जो समाचार हमें मिलता है, उसके बारे में हम अपने स्तर से भी छानबीन करें मगर जब किसी श्रोत के आधार पर हम प्रश्न करते हैं तो सरकार को उत्तर देना है येस और नो में ।

अध्यक्ष : इसमें कोई दो राय नहीं है । मैंने जो कहा, उसको सही परिप्रेक्ष्य में लीजिए । मैं आपको नियमावली की बात पढ़कर बताता हूं कि समाचार पत्रों के आधार पर अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो माना यह जाता है कि उन खबरों की सत्यता आपने जांच ली है । कहीं आपको कोई दूसरे श्रोत से सूचना मिलती है, आप पूछिये, लेकिन आपकी नियमावली में इस बात का विशेष उल्लेख है कि खबरों के आधार पर अगर आप प्रश्न पूछते हैं तो पूछने से पहले उसकी सत्यता आप भी जरा जांच कर लीजिए । चलिए, तार किशोर जी, अब आप प्रश्न पूछिये।

श्री तार किशोर प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को स्थगित किया जाए । जिस श्रोत से हमें जानकारी मिली है, वह श्रोत हम उपलब्ध कराते हैं ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री नन्द किशोर यादव, मंत्री: महोदय, स्थगित करने का क्या सवाल है महोदय ! ये दे देंगे, मैं इनको फिर से जवाब दे दूंगा महोदय अलग से । लेकिन महोदय, जो प्रश्न इन्होंने किया है, उस प्रश्न के बारे में बड़ा स्पष्ट जबाव दिया । मैंने जवाब देने में कोई इंकार नहीं किया । मैंने यह नहीं कहा कि आपने जांचा कि नहीं जांचा, मैं तो जो सिद्दीकी साहब कह रहे हैं, वही कह रहा हूं । प्रश्न अगर किसी भी सोर्स से इनको मालूम हुआ है, मैं उसका जवाब दे रहा हूं । महोदय, 2017 में कोई ऐसा सर्वे नहीं हुआ । तो मैंने बताया कि 2016-17 में कुछ सर्वे हुआ है जहां स्कूली बच्चे का हुआ, उनके आंख का हुआ, कितने लोगों का हुआ, कितने बच्चों में पाई गई, मैंने पूरी बात बताई है आपको । लेकिन आपको इसके अलावा कोई जानकारी है तो पूछिये पूरक और नहीं है तो मेरे जवाब से संतुष्ट होइए । आप जवाब सुनिये फिर से । अगर आपको कोई नई जानकारी बाद में मिलती है, फिर बताइएगा । फिर विभाग इसपर विचार करेगा । इसमें क्या आपत्ति है ।

श्री तार किशोर प्रसादः अध्यक्ष महोदय, कल ही माननीय प्रधानमंत्रीजी ने भी राष्ट्रीय पोषण मिशन का शुभारंभ किया है और सदन के साथ-साथ केन्द्र सरकार, राज्य सरकार की भी चिंता है कि जो हमारा मानव संसाधन है, उसको कैसे कुपोषण से मुक्त कराएं और इस बार भी सरकार ने बजट में बहुत स्पष्ट रूप से एक मौलिक चीज प्रस्तुत किया है कि जो राज्य के मानव संसाधन हैं, उसका बेहतर इस्तेमाल इस राज्य के विकास में किया जाएगा और उसके लिए स्वाभाविक है कि गर्भावस्था से लेकर, बचपन से लेकर उसके जवानी तक उसके स्वास्थ्य की चिंता सरकार और राज्य करेगी । हम माननीय मंत्री जी से सिर्फ इतना ही जानना चाह रहे हैं कि इंद्रधनुष कार्यक्रम भी राज्य की सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है जो काफी सफल भी हुआ है । हम माननीय मंत्री जी से सिर्फ इतना ही जानना चाह रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कल मिशन लागू किया है, राज्य सरकार की कई योजनाएं हैं, वो समेकित रूप से जो आधारभूत संरचना की कमी है, उस कमी को पूरा करते हुए पूरे राज्य में इस पर विशेष रूप से जोर करे, क्या सरकार चाहती है ? इतना ही पूछना है ।

श्री नन्द किशोर यादव, मंत्रीः महोदय माननीय सदस्य बहुत पुराने मेंबर हैं महोदय । इनको पता है कि पूरक प्रश्न वही पूछ सकते हैं जो इस प्रश्न से जुड़ा हुआ हो, और महोदय, ये अलग प्रकार का प्रश्न पूछना चाहते हैं । महोदय, मैं इनको बताना चाहता हूं, बड़ा स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को, जबसे एन.डी.ए. की सरकार 2005 में बनी, आपको भी ध्यान है, माननीय सदस्य महोदय और सबको ध्यान है कि बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था में व्यापक परिवर्त्तन हुआ है । पहले जो पी.एच.सी. की स्थिति थी, पहले जो स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति थी, पहले जो मेडिकल कॉलेज की स्थिति थी या जिला अस्पताल की स्थिति थी, जो परिवर्त्तन हुआ है महोदय....

(व्यवधान)

जो परिवर्त्तन हुआ है महोदय, उसका एहसास पूरा बिहार कर रहा है ...

(व्यवधान)

और हम विश्वास दिलाना चाहते है ...

(व्यवधान)

अरे, क्या बात करोगे आर.जे.डी. के लोग ? अस्पतालों का क्या हाल किया था आपने ? पंद्रह साल में जो हाल आपने किया है, लोग जानता है और जो परिवर्त्तन हमने करके दिखाया है महोदय....

(व्यवधान)

स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उसके बारे में मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है । पूरा बिहार अनुभव कर रहा है और माननीय प्रधानमंत्रीजी ने ...

(व्यवधान)

जो चिंता व्यक्त की है, राज्य सरकार ने लगातार स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार की है, स्वास्थ्य व्यव्स्था को बेहतर करेंगे, यह मेरी प्रतिबद्धता है ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी: महोदय, माननीय मंत्री ने यह बताया है कि एन.डी.ए. सरकार जबसे बनी है, स्वास्थ्य व्यवस्था में बहुत सुधार हुई है....

श्री नन्द किशोर यादव, मंत्री: बीच का बीस महीना छोड़ कर ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी: मैं कह रहा हूं एन.डी.ए. सरकार का । मैं, महोदय, आपसे अनुरोध करुंगा कि स्वास्थ्य मंत्री के आज के प्रभार में ये हैं और किसी भी तीन अन्य सदस्य को इनके साथ पी.एम.सी.एच. में भेजें । क्या आज भी मरीज जमीन पर लेटे हुए नहीं हैं? चलेंगे मेरे साथ ? मैं चुनौती देता हूं । मैं चुनौती देता हूं कि आज ही पी.एम.सी.एच. में कितने मरीज जमीन पर लेटे हुए हैं, यह आप दिखवाएंगे ?

श्री नन्द किशोर यादव, मंत्री: महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि पी.एम.सी.एच. के बारे में जो इनकी चिंता है, जायज है । मैं स्वीकार करता हूं और इसीलिए सरकार ने तय किया है कि पी.एम.सी.एच. का नया अस्पताल बनाएंगे, हम अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का अस्पताल बनाएंगे, विशेषज्ञों की बहाली करेंगे और पूरे भवन का नया निर्माण करेंगे महोदय, और बेड की संख्या इतनी बढ़ा देंगे कि किसी भी मरीज को जमीन पर सोने की आवश्यकता नहीं पड़े, यह निर्णय हमने किया है, यह एन.डी.ए. की सरकार ने निर्णय किया है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : ठीक है । बैठिये । माननीय सदस्यगण, अभी समाचार पत्रों में छपी खबरों के आधार पर प्रश्न पूछने के संबंध में कुछ बात चली थी । उसके संबंध में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली का नियम-83 है जिसमें प्रश्न का रूप और अन्तर्वस्तु के संबंध में स्पष्ट बातें की गई हैं, उसका जो सब-रूल-10 है, मैं उसको पढ़ना चाहता हूं कि इनमें समाचार पत्रों का निर्देश नाम से नहीं रहेगा, वह कंप्लाई होता है और न यह पूछा जाएगा कि समाचार पत्र में दिया गया कोई वक्तव्य या खबर सही है या नहीं, नम्बर एक, नम्बर दो, ... क्रमशः

टर्न 07/कृष्णा/09.03.2018

अध्यक्ष : (क्रमशः) किन्तु यदि प्रश्नकर्त्ता सदस्य उपर्युक्त शर्त-3 की आवश्यकतायें पूरी करें, प्रश्न को स्वत: पूर्ण बनायें तो ऐसे वक्तव्य की ओर ध्यान आकृष्ट सरकार का करेंगे । मतलब नियम की शर्त्त-3 है और शर्त-3 भी मैं पढ़ना चाहता हूं कि इसमें कोई विवरण हो तो उसकी परिशुद्धता के लिये, उसकी वेरेसिटी के लिये, उसकी सत्यता के

लिये सदस्य स्वयं उत्तरदायी होंगे । इसीलिये मैंने कहा कि समाचार पत्रों में छपी खबरों के आधार पर सीधे प्रश्न कर देना । यह अच्छी परम्परा होगी कि अगर उसकी परिशुद्धता क्योंकि नियम कहता है कि आप उसकी परिशुद्धता उस समाचार पत्र पर नहीं डाल सकते हैं । हमेशा जो प्रश्न आप पूछते हैं, उसकी परिशुद्धता के लिये आप स्वयं उत्तरदायी होते हैं । इसीलिये मैंने अनुरोध किया था ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी : अध्यक्ष महोदय, आपने ठीक कहा । आपने बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली का उल्लेख किया । माननीय सदस्य यदि कोई प्रश्न करते हैं तो आपके अधीन विधान सभा कार्यालय है और विधान सभा कार्यालय बिहार विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के तहत यदि वे प्रश्न नहीं आते हैं तो वे प्रश्न अस्वीकृत हो जायेंगे । मगर 25 सालों से विधान सभा कार्यालय ही यह परम्परा में स्वीकृत करती रही है ।

अध्यक्ष : सिद्दीकी साहब, आपको पता होना चाहिए कि यह परम्परा भी मैंने प्रारंभ की थी । अगर समाचार पत्रों की खबरों पर आधारित कोई प्रश्न पूछे जाते हैं तो मैंने चाहा था कि परम्परा मैं शुरू करूं कि सदस्य यह सत्यापित करें कि इस समाचार के खबर की परिशुद्धता मैंने स्वयं जांच ली है । अगर आप सहमत होईये, जो नियम कहता है, हम सर्टिफिकेशन ले लेंगे ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी : अध्यक्ष महोदय, निर्णय के लिये आप स्वयं सक्षम हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री रामदेव राय । यह अंतिम प्रश्न है । आप माननीय सदस्य श्री सदानन्द सिंह जी वाला प्रश्न पूछ दीजिये । तारांकित प्रश्न संख्या-839,ऊर्जा विभाग ।

तारांकित प्रश्न संख्या : 839 (श्री सदानन्द सिंह)

श्री रामदेव राय : महोदय, पूछता हूं ।

श्री विजेन्द्र प्र0 यादव,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि भागलपुर शहरी एवं समीपवर्त्ती क्षेत्रों में विद्युत आपूर्त्ति, रख-रखाव एवं राजस्व संग्रहण इत्यादि का कार्य दिनांक 01.01. 2014 से डिस्ट्रीब्यूशन फैंचाईजी एकरारनामा के तहत मेसर्स भागलपुर विद्युत वितरण कम्पनी प्रो0 लि0, कोलकाता द्वारा किया जा रहा था, जिसके अन्तर्गत कहलगांव, सोन्हौली, पीरपैंती एवं गोराडीह प्रखंड शामिल थे । एकरारनामा में निहित प्रावधान के अन्तर्गत फैंचाईजी क्षेत्र में ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य कराना था, जो उनके द्वारा नहीं

किया गया । दिनांक 25.11.2017 को उक्त डिस्ट्रीब्यूशन फैंचाईजी कंपनी को फैंचाईजी का एकरारनामा निरस्त कर दिया गया है ।

जिले में गांवों के विद्युतीकरण का कार्य दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (पूर्ववर्त्ती राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना) 12वीं योजना अन्तर्गत स्वीकृत है, जिसके तहत पूर्व में केवल गैर फैंचाईज क्षेत्र में कार्य किया जा रहा था । फैंचाईजी का एकरारनामा निरस्त होने के बाद अब इस क्षेत्र में भी गांवों का विद्युतीकरण स्वीकृत RE-DDUGJY के तहत प्रारंभ करते हुये सर्वे का कार्य पूर्ण किया जा चुका है । विद्युतीकरण का कार्य दिसंबर,2018 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है ।

श्री रामदेव राय : हुजूर, जो कार्य हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में प्राथमिकता के आधार पर बिहार में पूरा कराने का कोशिश किये हैं और इसबार बार-बार आश्वासन भी दिये हैं कि इस साल सारे गांवों को बिजली मिल जायेगी और फिर इतने महत्वपूर्ण जगहों पर इनकी कंपनी बिजली नहीं लगायी तो उस कंपनी को तो कुछ दण्ड देना चाहिए कि क्यों अपने समय पर कार्य पूरा नहीं किया ? इसके बाद जिस कंपनी को काम दिये हैं, उसको आप समय दीजिये । इसी मार्च में वह पूरा कर दे । मात्र 5 गांव बाकी है । हुजूर, इतना तो करवा दीजिये ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, मैं माननीय सदस्य रामदेव बाबू को कहना चाहता हूं कि इन्हीं की सरकार ने एक नियम बनाया कि चूंकि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बहुत घाटे में है तो शहरो में प्राईवेट एजेंसी को लाया जाय लाईक दिल्ली । इनकी सरकार थी तो दिल्ली में यह किया गया था । उसी के आधार पर हमलोगों ने यह एडॉप्ट किया और वह कंपनी नहीं कर पायी तो उस कंपनी को सजा भी हुई, निरस्त कर दिया गया है, वे कोर्ट भी गये, वहां उनको हार मिली है इसीलिये अब चिन्ता करने की जरूरत नहीं है । हो जायेगा दिसंबर,2018 तक ।

श्री रामदेव राय : महोदय, हम आश्वासन चाहते हैं कि इस काम को अप्रील-मई तक अवश्य पूरा करवा दें ।

अध्यक्ष : प्रश्नोत्तरकाल समाप्त हुआ । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों, सदन पटल पर रख दिये जायं ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 09 मार्च, 2018 को माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महासेठ एवं श्री अत्री मुनि उर्फ शक्ति सिंह यादव से कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है ।

आज सदन में वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों पर वाद-विवाद एवं मतदान का कार्यक्रम निर्धारित है ।

अतएव बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के निमय-172 (3) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना को अमान्य किया जाता है ।

शून्यकाल

श्री मो0 नेमतुल्लाह : महोदय, गोपाालगंज जिलान्तर्गत मांझा बरौली पीच रोड से रतनसराय स्टेशन होते हुये सीवान सरफरा पीच रोड तक जानेवाली सड़क अत्यंत जर्जर स्थिति में है जिसके कारण आम ग्रामीणों को काफी परेशानी होती है ।

अत: सरकार उक्त सड़क का निर्माण शीघ्र कराये ।

श्री समीर कुमार महासेठ : महोदय, राज्य के 6 विश्वविद्यालयों के अंतर्गत चतुर्थ चरण के 28 अंगीभूत कॉलेजों के शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मियों को केस संख्या- 2703/17 में पारित उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार 06.01.2018 तक वेतनादि दिया जाना है । परन्तु अभी तक भुगतान नहीं हुआ ।

चतुर्थ चरण के शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतनादि भुगतान की मांग है ।

श्री अमित कुमार : महोदय, सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बैरगनियां प्रखंड के आदम बॉन से पताही सड़क जो बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण आवागमन बाधित है, जल्द से जल्द जनहित में क्षतिग्रस्त सड़क को अतिशीघ्र बनवाने की कृपा की जाय ।

(व्यवधान)

(इस अवसर पर मा0स0 श्री सरोज यादव आसन के समीप जाकर कुछ बोलने लगे ।)

अध्यक्ष : आप अपनी जगह पर जाकर बोलिये न ।

श्री शमीम अहमद : महोदय, पूर्वी चम्पारण जिला के बंजरिया, बनकटवा, छौड़ादानों प्रखंड के किसान भाईयों के खेत में लगा मक्का फसल में दाना के अभाव में भूखमरी के साथ कर्ज की मार झेल रहे हैं ।

अतः सरकार से मांग करते हैं कि उक्त प्रखंडों में फसल क्षति का मुआवजा मिले ।

श्रीमती बेबी कुमारी : महोदय, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति का महत्व है परन्तु विकास कार्यों में पंचायत समिति सदस्य की कोई भूमिका नहीं है, सिवा प्रमुख के चयन के ।

अतः पंचायत समिति सदस्यों की सहभागिता पंचायत स्तरीय सभी विकास योजनाओं में सुनिश्चित करायी जाय ।

श्री श्याम बाबू प्रसाद : महोदय, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, शेखपुरा, पटना में सुपर स्पेशलिटी में सभी विभागों में डी0एम0 एवं एम0सी0एच0 की पढ़ाई हेतु केन्द्र सरकार को बिहार राज्य के स्वास्थ्य विभाग प्रस्ताव दे ।

श्रीमती भागीरथी देवी : महोदय, बेतिया जिलान्तर्गत प्रखंड गौनाहा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत पथ L022 से राजपुर (2) सेमरा श्री रामपुर से बैरटवा (3) L 022 से खैरटिया (4) T 03 से पड़रेन तक बन रहे पथों में उपयोग हो रहे बालू पत्थर प्राक्कलन के विपरीत है । इसकी जांच करने की मैं मांग करती हूं ।

श्री रामप्रीत पासवान : महोदय, जिला मधुबनी प्रखंड राजनगर के गांव केवान के अति पिछड़ा समुदाय के 22 वर्षीय गर्भवती रिंकी कुमार का दिनांक 03.03.2018 को सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गयी एवं पति रंजीत ठाकुर गंभीर घायल है ।

अतः पीड़ित परिवार को चार लाख मुआवजा एवं घायल के ईलाज की सरकार से मांग करता हूं ।

टर्न-8/सत्येन्द्र/9-3-18

श्री ललन पासवानः अध्यक्ष महोदय, रोहतास जिलान्तर्गत प्रखंड काराकाट (गोड़ारी) के विक्रमगंज-डेहरी एस0एच0 पथ के ईटवां गांव से रघुनाथपुर(बाल) तक का पहुंच पथ कच्ची है। आवागमन बाधित है । सरकार से मांग करते हैं कि उक्त पथ को पक्कीकरण करावें ।

श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंहः अध्यक्ष महोदय, हाजीपुर, वैशाली, केसरिया, अरेराज, बेतिया एस0एच0 रोड में अनावश्यक ब्रेकर होने से बराबर दुर्घटना जानमाल की क्षति एवं विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती रहती है । अवैध ब्रेकर को तोड़वाकर जानमाल की सुरक्षा तथा विधि व्यवस्था को ठीक करने हेतु सरकार से अनुरोध करता हूँ ।

श्रीमती गायत्री देवी: अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला के बेला थाना अन्तर्गत ग्राम धनहा की नबालिग लड़की निभा कुमारी का अपहरण दिनांक 6-3-10 को बदमाशों ने कर लिया है, थाना प्रभारी अपहरणकर्त्ता से मिला हुआ है । अत: मैं सरकार से मांग करती हूँ कि नबालिग निभा कुमारी को अपहरणकर्त्ता के चंगुल से मुक्त करावें ।

अध्यक्ष: श्री अत्री मुनि उर्फ शक्ति सिंह यादव ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

डॉ0 राजेश कुमार ।

डॉ0 राजेश कुमार: अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण जिले में पिछले पार्लियामेंट चुनाव के समय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वादा किया था मोतिहारी चीनी मिल चालू कराने के लिए किसानों की समस्या को देखते हुए सरकार से मांग करता हूँ कि मोतिहारी चीनी मिल चालू हो या फिर नया चीनी मिल की व्यवस्था की जाय ।

श्री विनय बिहारी: अध्यक्ष महोदय, बाढ़ प्रभावित लौरिया प्रखंड के पंचायत राज धमौरा, साठी, धोबनीधरमपुर, खजुरिया, बहुआरवा, गोनौली, डुमरा व बंसवरिया पराऊटोला सहित अन्य पंचायतों से कुल पांच हजार नौ सौ उन्चास परिवारों का भुगतान बकाया है । मैं सदन के माध्यम से पीड़ित परिवारों को शीघ्र भुगतान हो इसकी मांग करता हूँ ।

ध्यानाकर्षण सूचनाएं तथा उस पर सरकारी वक्तव्य

सर्वश्री हरिशंकर यादव,मुंद्रिका प्रसाद राय एवं श्री शमीम अहमद,स0वि0स0 से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उस पर सरकार (पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग)की ओर से वक्तव्य।

श्री शमीम अहमद: अध्यक्ष महोदय, राज्य में महंगे सरकारी सीमन पर छूट नहीं देने से गरीब पशुपालकों के साथ ही बिहार एनिमल ब्रीडिंग पॉलिसी, 2011 को भी काफी नुकसान पहुंच रहा है । नई दिल्ली, छतीसगढ़, केरल और पांडिचेरी जैसे राज्यों की तर्ज पर कृत्रिम गर्भाधान पूर्णत: नि:शुल्क कर देना व्यापक राज्यहित में है । राज्य में श्वेत क्रांति लाने के लिए मुख्यमंत्री पशुभाग्य योजना बनाकर इसे बजट में शामिल करने का एक प्रस्ताव भी राज्य सरकार को प्राप्त है जिसके तहत नि:शुल्क कृत्रिम गर्भाधान की व्यवस्था करना तथा पशुपालकों को प्रोत्साहन राशि देना पशुधन वृद्धि में काफी लाभकारी सिद्ध होगा । अत: इस लोक महत्व के विषय पर हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।

श्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद, मंत्री: महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि राज्य में फ्रोजेन सिमेन से कृत्रिम गर्भाधान कार्य सामान्य के लिए 40/-रू0 एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लिए 25/-रू0 प्रति पशु निर्धारित है । नि:शुल्क कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा

प्रदान करने वाले राज्यों से अध्ययन कराकर नि:शुल्क सुविधा प्रदान करने पर विचार किया जायेगा ।

श्री शमीम अहमद: अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष: सरकार ने तो सकारात्मक जवाब दिया है ।

श्री शमीम अहमद: एक मिनट सर, कृषि के क्षेत्र में, मवेशी को कृषि विभाग में ही लिया गया है, कृषि के लिए 2247 करोड़ रू0 लिये गये हैं और पशु एवं संसाधन में मात्र 443 करोड़ रू0 लिये गये हैं..

अध्यक्ष: आप यह बजटरी एलोकेशन कहां से ले आयें, मामला कहां है जा कहां रहे हैं ।

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

अध्यक्ष: माननीय प्रभारी मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: महोदय, मैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा-40(3) के तहत् पत्रांक 03, दिनांक 1-1-14/ 9493, दिनांक 12-12-14/3664, दिनांक 23-6-14/386, दिनांक 21-1-14/432, दिनांक 23-1-14/388, दिनांक 21-1-14/4342, दिनांक 29-5-15/8815 एवं 8817,दिनांक 19-11-15/923,924, दिनांक 8-2-16/2151, दिनांक 31-3-16 एवं 2910, दिनांक 19-6-16 द्वारा निर्गत विभागीय नियमावली, अधिसूचना एवं मार्गदर्शिका की एक-एक प्रति सदन के पटल पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष: अब सदन की कार्यवाही 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है।

टर्न-9/मधुप/09.03.2018

(अन्तराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया ।)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है ।

वित्तीय कार्य

माननीय सदस्यगण, आज शिक्षा विभाग के अनुदान की मांग पर वाद-विवाद, सरकार का उत्तर एवं मतदान होगा । इसके लिए तीन घंटे का समय उपलब्ध है । विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है, इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिए भी समय दिया जाएगा :-

राष्ट्रीय जनता दल	-	59 मिनट
जनता दल (युनाइटेड)	-	52 मिनट
भारतीय जनता पार्टी	-	39 मिनट
इंडियन नेशनल कांग्रेस	-	20 मिनट
सी0पी0आई0(एम0एल0)	-	02 मिनट
लोक जनशक्ति पार्टी	-	02 मिनट
हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा	-	01 मिनट
राष्ट्रीय लोक समता पार्टी	-	02 मिनट
निर्दलीय	-	03 मिनट

माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग अपनी मॉग प्रस्तुत करें ।

श्री श्रवण कुमार मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :-

''शिक्षा विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिए 321,25,63,75,000/- (तीन सौ एक्कीस अरब पचीस करोड़ तिरेसठ लाख पचहत्तर हजार) रूपए से अनधिक राशि प्रदान की जाए ।''

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

अध्यक्ष: इस मांग पर श्री रामदेव राय, श्री राजेन्द्र कुमार, डॉ0 फराज फातमी, श्री अत्री मुनी उर्फ शक्ति सिंह यादव, श्रीमती एज्या यादव, श्री महबूब आलम एवं श्री ललित कुमार यादव से कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो व्यापक हैं एवं जिनपर सभी माननीय सदस्य विचार-विमर्श कर सकते हैं ।

माननीय सदस्य श्री रामदेव राय का प्रस्ताव प्रथम है, अतएव माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

श्री रामदेव राय : हुजूर, जरा समय जानना चाहते थे ।

अध्यक्ष : आपके दल ने जो दिया है, उसके अनुसार आपका 5 मिनट समय है ।

श्री रामदेव राय : उससे अलग समय हमारा होगा या दल ही में मेरा समय सन्निहित रहेगा ?

अध्यक्ष : आपके दल को समय 20 मिनट पूरा था जिसमें सरकार को उत्तर के लिये समय के बाद लगभग 17-18 मिनट आपके दल का समय होता है लेकिन आपके दल के सचेतक महोदय ने जो समय का आवंटन किया है, उसमें 5 मिनट आपके लिये है, 10 मिनट मोहम्मद जावेद के लिये है और 5 मिनट सुश्री पूनम पासवान के लिये है ।

श्री रामदेव राय : मंजूर है, सर । मैं एक चीज बस जानना चाहता हूँ जानकारी के लिये कि माननीय मंत्री जी मूव करें, उनके लिये समय, फिर जवाब देंगे, उनके लिये समय, उनके लिये निश्चित समय नहीं है.....

अध्यक्ष : सरकार को हमेशा समय की सब दिन से प्राथमिकता मिलती है और माननीय मंत्री मूव करने में तो समय लेते नहीं हैं ।

श्री रामदेव राय : नहीं लेते हैं, यह तो उनकी कृपा है ।

अध्यक्ष : कृपा नहीं है, यह परम्परा है ।

श्री रामदेव राय : लेकिन कटौती में तो समय मिलना चाहिये ।

अध्यक्ष : कटौती में तो आपको समय है ही, बोलिये ।

श्री रामदेव राय : माननीय महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री जो अभी प्रभारी मंत्री के रूप में हैं, उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है यह बजट, इस बजट में मैं कटौती का प्रस्ताव पेश किया हूँ और उसका मुख्य कारण एक ही है । माननीय मंत्री जी को स्वयं यहाॅ रहना चाहिये, वे स्वयं नहीं हैं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री रामदेव बाबू, अपना प्रस्ताव तो पहले पेश कर दीजिये ।

श्री रामदेव राय : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"इस शीर्षक की माॅग 10/- रूपये से घटाई जाए ।"

हुजूर, सबसे बड़ी बात यह है कि कटौती प्रस्ताव मैं मजबूरी में पेश कर रहा हूँ क्योंकि इसमें दो मजबूरी हमारी है । एक मजबूरी है कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डाॅ0 राजेन्द्र प्रसाद जी थे, उनके गाॅव में, उनके स्कूल में मात्र 46 लड़के अभी पढ़ रहे हैं । इससे घोर कष्ट हुआ है । यह देश के स्वाभिमान पर खतरा है, इसलिये मैं कटौती पेश किया हूँ । दूसरा, कटौती इसलिये पेश किया हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जब से आये हैं, कई मायने में बिहार को आगे बढ़ाने के लिये प्रयत्न किये हैं - बिजली, सड़क लेकिन शिक्षा को उन्होंने अशिक्षित बना दिया । जिस राज्य की शिक्षा स्वयं अशिक्षित हो गई हो तो कटौती पेश करने के अलावे चारा क्या है ? भला संयोग यह है कि आप

आसन पर विद्वान आदमी हैं और विद्वता से ही किसी का ज्ञानवर्द्धन होता है और ज्ञानवर्द्धन करने से कार्य क्षमता बढ़ती है, कार्य क्षमता से व्यक्तित्व चमकता है और व्यक्तित्व जब चमकता है तब मनुष्य को 'श्री' मिलता है । मैं चाहता हूँ कि बिहार में कोई 'श्री' को ले आपके माध्यम से, चेयर के माध्यम से । कांग्रेस ने शिक्षा के क्षेत्र में जो किया, उसको कम से कम नकल करना चाहिये था । मुझे लगता है कि कांग्रेस कर गयी तो कांग्रेस का नाम किस तरह से हटा दिया जाय शिक्षा के पन्ने पर से, इसलिये इसकी यह दुर्गति हो रही है, अन्यथा नहीं, इसका कारण यह है । अगर आप देखेंगे हुजूर, मैं बता सकता हूँ, 5 मिनट ही तो समय है, मैं अपने साथी का समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ । हम निराश नहीं होना चाहते हैं, फिर भी, जो मनुष्य कल्याण के मार्ग पर चलता है, उसका जरा भी श्रम व्यर्थ नहीं जाता है । हम चाहते हैं कि कांग्रेस इस सिद्धांत को मानने वाली थी और इसी आधार पर कांग्रेस इतनी दूर तक आगे लाई, देश के गॉंव-गॉंव घर-घर में बच्चों को स्कूली शिक्षा से जोड़ी, भारतीय शिक्षा नीति बनी । याद होगा आपको सर, 1986 का कानून बना जिसपर हमारे मंत्री जी बिहार उच्चतर शिक्षा परिषद विधेयक, 2018 ला भी रहे हैं । क्या जरूरत है इसकी ? हमारे शिक्षा विभाग में कितने पैरा हैं, कमीश्नर हैं, सचिव हैं, डायरेक्टर हैं, काउंसिल है, इंटर काउंसिल है और परिषद्, कितने हैं । लेकिन आप विधेयक लाकर परिषद बनाते-बनाते आगे बढ़ा रहे हैं लेकिन स्कूल में पढ़ाई नहीं, स्कूल में शिक्षक नहीं, स्कूल में जमीन है तो मकान नहीं, मकान है तो शिक्षक नहीं, काम कैसे चलेगा ? तू ही मेरा, मैं ही तेरा, तेरा-मेरा कैसा ? कोई काम तो नहीं हुआ शिक्षा को बढ़ाने के लिये । शिक्षक को बढ़ाने के लिये आपने वादा किया था कि हाई स्कूल में जितने पद रिक्त हैं, उसको हम तुरंत भर देंगे, वह भी नहीं भरे । प्राइमरी स्कूल उसी तरह से खाली हैं । मध्याह्न भोजन की वही हालत है । पढ़ाई-लिखाई के बारे में तो मैंने कहा ही शिक्षा को अशिक्षित बनाने का काम आपके इस सरकार के जिम्मे जायेगा । कारण कि जिसकी बहाली आपने की है, जो समान काम के लिये समान वेतन की मॉंग तो कर रहा है लेकिन आप समान काम ले नहीं रहे हैं । देख नहीं रहे हैं कि वह क्या कर रहा है उस स्कूल में जाकर । जो अपना नाम स्वयं नहीं लिख सकता हो, तो बच्चे को नाम लिखना कैसे सिखा सकता है? याद कर लीजिये । एक स्कूल में छात्र ही शिक्षक को कहा कि सर, मेरा नाम आप गलत लिख रहे हैं । जिस राज्य की यह हालत होगी श्रीमान्, उस राज्य में शिक्षा के बढ़ोत्तरी के लिये हम कौन-सा उम्मीद कर सकते हैं ?

दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूँ कि अब इसके लिये समय आ गया है, हुजूर, जरा आप ध्यान दीजियेगा तो जरूर इसमें सफलता पा सकेंगे । चूंकि आप पुराने जमाने के पढ़े-लिखे लोग हैं, कितनी मेहनत किये होंगे । कहॉं परीक्षा में जूता और मोजा का कोई जॉंच होता था ? हमारा बिहार इतना कमजोर है, हमारा प्रशासन इतना कमजोर

है कि उसे जूता और चप्पल को भी जॉच कराना पड़ रहा है । हममें यह शक्ति नहीं है कानून का पालन करवाने के लिये कि हमारे आदेश को ओदश माने और उसके मुताबिक उसको चलना पड़े । हम ऐसा बिहार चाहते हैं । अगर ऐसा बिहार आप नहीं बना सकते हैं तो जल्दी से श्रवण बाबू, विजेन्द्र बाबू, गद्दी छोड़ दीजिये । हमलोग स्वयं सम्भाल लेंगे । नहीं तो एक स्कूल आप चलाइये, एक स्कूल महागठबंधन को दीजिये और एक महीना का समय दीजिये, पढ़ाई किसकी अच्छी होती है, देख लीजिये ।

.... क्रमशः ...

टर्न–10/आजाद/09.03.2018

.... क्रमशः .....

श्री रामदेव राय : अभी तक हुजूर, आपके सरकारी स्कूल के छात्र टेन्थ टॉपर में भी नहीं आया है विजेन्द्र बाबू, प्राइवेट स्कूल के छात्र–छात्रायें टेन्थ के हमेशा आस–पास रहता है । यह लज्जाजनक बात नहीं है क्या ? करोड़ों–अरबों रू0 हम लगाते हैं उनमें लेकिन हमारा विद्यार्थी टेन्थ के ऊपर जाता है, दसवां स्थान भी प्राप्त नहीं करता है । इसीलिए लज्जा होती है, यह नहीं है कि हम आपको पॉलिटिकली यह कह रहे हैं, यह नहीं है कि आपको पॉलिटिकली ह्रास करना चाह रहे हैं । हम यह चाहते हैं कि हर मायने में भारत सरकार जो कानून बनाये हैं, जो 1986 का कानून है । आप सभी लोग खुश होंगे, अभी हम बताते हैं एक आंकड़ा, आज 50 प्रतिशत महिला के आरक्षण के लिए परेशान हैं । लेकिन इनको मालूम है यदि आप यूनेस्को का रिपोर्ट पढ़े होंगे, विजेन्द्र बाबू तो अवश्य रटे होंग, कांग्रेस अपने समय में जिस समय कानून बनायी, उसी समय कांग्रेस यह निश्चित कर दी कि शिक्षा के क्षेत्र में जितनी भी बहालियां होंगी, उसमें 50 प्रतिशत महिलायें होंगी । एक ब्लैकबोर्ड स्कीम में , साढ़े चौदह वर्ष के बच्चे स्कूल में रहेंगे, उनको स्कूल से बाहर नहीं रहने देंगे । उनके समान पढ़ाई–लिखाई की व्यवस्था होगी और उसी समय कांग्रेस ने आदेश दिया कि जितनी भी नियुक्तियां होंगी, उसमें 50 प्रतिशत महिलायें होंगी और आज कांग्रेस को पीछे छोड़ देना चाहते हैं, सब चीज अपने जिम्मा रखना चाहते हैं । हम आपको पलक नहीं मारने देंगे, महिला को आगे बढ़ाने के लिए सारे सिस्टम, हर काम, हर कानून के साथ चाहे बिहार में हो या भारत में हो, हमारी पार्टी इसमें साथ रहेगी । यही कारण है कि आज शिक्षा का बजट का कितना बड़ा आकार बढ़ा है । बजट का आकार तो बढ़ा दिये, स्कूल का आकार बढ़ा, शिक्षकों का प्रकार बढ़ा, विद्यार्थियों का सकारात्मक विकास हुआ, बता दीजिए, कुछ नहीं ? आप चोरी के लिए परेशान हैं, पढ़ाई एक दिन भी नहीं कराये और आप चोरी रोकते हैं । वाह रे वाह, कैसा दायित्व आपका है, लड़का पढ़ नहीं रहा है, मैं कोई पार्टी पर नहीं बोल रहा हूँ, क्या यह कांग्रेस की बात है ? आपका बच्चा पढ़ा नहीं स्कूल में और बच्चा

पढ़ता है कॉन्वेंट में और दाखिल है हाईस्कूल में । परीक्षा लेते हैं हाईस्कूल में, कॉपी जॉच करवाते हैं हाईस्कूल में, वाह-वाह क्या है मिनस्टिर साहेब, कमाल है आपका । कुछ तो सोचिए, कुछ तो विचार कीजिए, बिहार आपका है, हमलोग बिहार का नेता आपको मानते हैं और नेता का यही काम है । नेता वह होता है जो कांटों पर चलता है, लेकिन आप गुलाब के फूल पर चलना चाहते हैं तो आप कभी सन्मार्ग पर चलने वाला व्यक्तित्व नहीं बना सकते हैं, सन्मार्ग पर वही चलेगा जो दूसरों को सन्मार्ग पर ले चलता है और उसका एक ही रास्ता है शिक्षा और अगर हम शिक्षा में कमी रखेंगे, कोई कमजोरी रखेंगे तो हम कभी कुछ नहीं कर सकेंगे ।

अध्यक्ष महोदय, 2017-18 में शिक्षा पर 17.58 प्रतिशत खर्च किये थे और इस बार 20.81 प्रतिशत है । आप खर्च कहां कीजियेगा, किस स्कीम पर इतना पैसा खर्च कीजियेगा, अभी तक आपने 40 प्रतिशत राशि भी खर्च नहीं कर पाये हैं । आप कितने ब्लिडिंग बनाये हैं, अभी समय नहीं है, नहीं तो हम अभी जिलावार आंकड़ा देते । हमारे पास आंकड़ा है, आपने कितनी ब्लिडिंग बनाई, कितने ब्लिडिंग का काम पूरा हुआ? ब्लिडिंग बन गया, चौखट-किवाड़ी नहीं है, ब्लैकबोर्ड नहीं है, कुर्सी-टेबुल नहीं है, आप आंकड़ा दे देते हैं कि कोठरी बन गई । मैं पूछता हूँ कि आप क्यों नहीं विधान सभा का सर्वदलीय कमिटी बनाकर उसको देखवाते हैं, इससे आपकी प्रगति होगी ।

अध्यक्ष : अब समय आपका 12 मिनट हो गया ।

श्री रामदेव राय : महोदय, अब हम खतम कर देते हैं । भारत में बिहार का बहुत ही निचला स्थान है और यूनेस्को ने कहा कि 87 विकासशील देशों के स्तर पर भारत का 50वां स्थान है। आंकड़ा में देखियेगा तो बिहार आज गोवा से भी पीछे है । गोवा एक छोटा सा राज्य है और हम उससे भी पीछे हैं । इसलिए बिहारवासियों से अपील है, बिहार के नेता से आग्रह है कि आप बिहार को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहिए, सबका साथ लीजिए, इससे आपका हाथ मजबूत होगा । सबका साथ नहीं लीजियेगा तो कैसे आपका हाथ मजबूत होगा । महोदय, अब मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ यह कहते हुए कि एक-दो केस देते हैं, आप उसको देख लीजिए । एक अध्यादेश के जरिए ....

अध्यक्ष : अब समाप्त कीजिए ।

श्री रामदेव राय : सर, बस लास्ट है । नहीं तो कहियेगा तो हम माननीय मंत्री जी को लिखकर दे देंगे ।

श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री : महोदय, बेगूसराय पर ख्याल रखियेगा तो आप पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा रिश्तेदारी पर ?

श्री रामदेव राय : लिखित दे देंगे सर ।

अध्यक्ष : लिखित दे दीजिये ।

श्री रामदेव राय : दे देते हैं सर, लेकिन डायरेक्शन दिया जाय कि उस पर वे बोलें भी ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री रामदेव बाबू, शिक्षा विभाग के संबंध में जो बात नहीं कह पा रहे हैं, वे लिखित दे देंगे, सरकार उसपर विचार करेगी ।

माननीय सदस्य श्री मो0 नेमतुल्लाह जी ।

श्री मो0 नेमतुल्लाह : अध्यक्ष महोदय, आज शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और आज इसपर वाद-विवाद हो रहा है लेकिन शिक्षा मंत्री जी यहां मौजूद नहीं हैं, उनको रहना चाहिए था और इसपर उनको विशेष विचार करना चाहिए था । महोदय, टोटल बजट का 40 प्रतिशत शिक्षा पर व्यय होता है और शिक्षा की बिहार में क्या हाल है, आये दिनों में जिस तरह से शिक्षा गिरते चला जा रहा है, डे बाई डे शिक्षा का स्तर गिर रहा है, उससे बहुत चिन्ता का विषय है और इससे पक्ष हो या विपक्ष हो, सबको इसपर सोचना चाहिए कि क्यों हमारे बच्चे बिहार के छोड़कर बाहर जा रहे हैं अच्छे तालिम हासिल करने के लिए । बिहार में वह क्वालिटी नहीं है क्या ? बिहार में टॉपर हो जाता है, टॉप कर जाता है लेकिन उसको नॉलेज कुछ नहीं रहता है, उसको जीरो आता है । जब मीडिया वाले पूछते हैं तो वह टॉप कर गया लेकिन जानकारी उसको कुछ नहीं होती है । जिस राज्य में टॉपर घोटाला हो, क्यों होता है ? टीचर्स की क्वालिटी नहीं है, आपने टीचर्स किस तरह के बहाल किया, डिग्री ले आओ और नौकरी पाओ । अगर आप इस तरह का टीचर्स बहाल करेंगे तो क्या होगा, आप क्वालिटी एजुकेशन दें । आज देखेंगे कि प्राइवेट स्कूल किस तरह से फैल रहे हैं । हर गांव में, हर टोले में, हर मुहल्ले में प्राइवेट स्कूल चल रहा है । सिर्फ नाम के लिए मिड-डे मिल के लिए सरकारी स्कूल में बच्चा नाम लिखवाता है और उसका गार्जियन उसको भेजता है जाओ प्राइवेट स्कूल में पढ़ो । प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है और यहां सेशन चल रहा है, चार साल लेट चल रहा है बिहार में । हमारे बिहार के छात्रों में प्रतिभा है, हमारे छात्रों में क्वालिटी है और जब वे बाहर जाते हैं पढ़ने तो वे वहां टॉप करते हैं । महोदय, बिहार से सबसे जयादा आई0ए0एस0 बच्चे निकलते हैं । आज कोटा एजुकेशन का हब बन रहा है, आज यूनिवर्सिटी कुकुरमुत्ते की तरह साऊथ में खुला हुआ है । लेकिन वहां जाकर के देखिए कि एक-एक कमरे में वहां यूनिवर्सिटी चल रहा है । वहां जाकर एजुकेशन प्राप्त करके बच्चे आते हैं, इंजीनियर और डॉक्टर बनते हैं और बनकर यहां बिहार में आते हैं और यहां सेवा करते हैं । हम यहां वह चीज क्यों नहीं दे रहे हैं । हम दावा करते हैं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी हम यहां ले आयेंगे, हम दावा करते हैं कि एजुकेशन के क्वालिटी को ठीक करेंगे, लेकिन यहां पर तो दिन पर दिन क्वालिटी गिरता जा रहा है। महोदय, टीचर्स किस तरह के हैं, जो बहाली हो रही है आप देखिए, जो अभी एक्जाम हुआ, आप देखें हैं, ठीक ही कहा रामदेव बाबू ने, पैंट उतरवाया जा रहा है, जूता-मोजा खोलवाया जा रहा है, आप शर्ट पहन कर आईए । आपके यहां एजुकेशन की कमी है, आप स्कूल में पढ़ाई नहीं करा रहे हैं तो बच्चा परीक्षा में चोरी नहीं करेगा तो कैसे होगा । आप टाईट

परीक्षा कर रहे हैं तो क्या करेगा बच्चा ? आप एजुकेशन दीजिए, आप पढ़ाईए, आप उस स्तर तक लाईए ताकि वह खुद कहेगा कि हम परीक्षा देने जायेंगे तो पढ़-लिखकर जायेंगे और हम अपने बलबूते पर परीक्षा देंगे और हम कमप्लीट करेंगे । लेकिन आज विद्यालय में पढ़ाई नहीं होता है, हम विद्यालय में एजुकेशन नहीं दे पाते हैं तब आपका ......

(व्यवधान)

अध्यक्ष : नेमतुल्लाह जी, आप जो कह रहे थे तो माननीय सदस्य इस तरफ इशारा कर रहे थे कि आपने जो कहा कि बच्चे चोरी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे तो बच्चों को चोरी करने के लिए प्रोत्साहित तो नहीं ही करना चाहिए, आप यह कहिए न कि सरकार व्यवस्था करे जिससे कि बच्चे चोरी नहीं करें ।

टर्न-11/अंजनी/दि0 09.03.18

श्री मो0 नेमतुल्लाह : हुजूर, आपने सही फरमाया । इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए कि सरकार चोरी नहीं करे । सरकार चोरी नहीं करे इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए।

(इस अवसर माननीय सभापति महोदय श्री तारकिशोर प्रसाद ने आसन ग्रहण किया)

आसन से इस तरह का आदेश होना चाहिए कि सरकार चोरी नहीं करे । महोदय, जहां तक अल्पसंख्यक स्कूल का सवाल है, उन लोगों को सात-सात महीना से पैसा नहीं मिल रहा है । महोदय, क्या होता है ? अल्पसंख्यक में बच्चे पढ़ते हैं, वहां प्राइवेट तौर पर, प्राइवेट मैनेजमेंट जो है, वे चलाते हैं लेकिन उसको भी जाल में फंसाकर सेक्रेटेरियट में दौड़ाकर किस तरह से उनको उलझाकर रख दिया जाता है, जल्दी उनको मायनोरिटी डिक्लेर्ड नहीं किया जाता है । कन्स्टीच्यूशन में आर्टिकल 29 एवं 30 में प्रावधान है कि मायनोरिटी चाहे अपनी इच्छा के अनुसार वह इन्स्टीच्यूशन खोल सकता है लेकिन उसका मायनोरिटी डिक्लयेरेशन होता है आपके शिक्षा विभाग से । मैनेजमेंट दौड़ते रह जाते हैं लेकिन नहीं मिलता है । मैनेजमेंट न्यायालय का शरण लेता है, न्यायालय उसको डायरेक्शन देता है कि जांच कराओ-जांच कराओ, जांच कराने के बाद से उसको मॉयनोरिटी डिक्लयरड करो और मॉयनोरिटी डिक्लयरड जब होता है तो फाइनेंसियल बर्डेन वह सरकार की हो जाती है, सरकार उनको पेमेंट नहीं करती है, वे ऐसे ही भटकते रहते हैं । महोदय, तो भूखे भजन न होय गोपाला, पेट में जब दाना रहेगा तब ही न टीचर पढ़ायेंगे । महोदय, कितनी विषमता है, नियोजित शिक्षक के संबंध में माननीय हाई कोर्ट ने भी डायरेक्शन दे दिया, बराबर पेमेंट नहीं करते हैं, रेगुलर टीचर को करते हैं तो दो तरह की बात कैसे हो सकती है । एक पैसा पाता है और वह भी वही काम करता है, equal वर्क तो equal पे होना चाहिए । एक टीचर वही काम करता है, जो मानदेय पर चलता है तो यह डायरेक्शन हाई कोर्ट ने दिया कि equal वर्क, equal पे होना चाहिए लेकिन नहीं मिलता है महोदय । समान वेतन होना चाहिए और समय पर

होना चाहिए । मॉयनिरिटी स्कूल का भी, रेगुलर टीचर का भी और उन लोगों को उसी के बराबर तनख्वाह मिलना चाहिए तो ये प्रोत्साहित होकर क्वालिटी एजुकेशन देंगे । महोदय, स्कूल में टीचर की इतनी कमी है कि साईंस टीचर के जगह पर संस्कृत शिक्षक पढ़ाने के लिए चले जाते हैं, केमेस्ट्री की जगह पर उर्दू टीचर चला जाता है पढ़ाने के लिए तो इस तरह से टीचरों की कमी के वजह से वहां एरेजमेंट लोग करते हैं कि लड़के हल्ला-गुल्ला नहीं करे और व्यवस्था बना रहे लेकिन पढ़ाई तो नहीं हो पा रही है तो इसपर ध्यान देने की जरूरत है । इसलिए जिस विषय का टीचर है, उसी विषय को पढ़ायें । महोदय, उर्दू के टीचर की बहुत कमी है । उर्दू के टीचर के लिए हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक डायरेक्शन हो गया है, उस दिन एक क्वेश्चन में बात आयी थी कि हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया, एडवोकेट जेनरल से भी एडवाइज ऑपिनियन ले लिया गया है लेकिन क्यों अधर में पड़ा हुआ है, क्यों लटका हुआ है उर्दू के टीचर के बहाली के लिए । इसके लिए सरकार को व्यवस्था करके उनकी बहाली करनी चाहिए । हमारे यहां बरौली की बच्चियां गोपालगंज में पढ़ने के लिए जाती है । वहां पर कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, इसलिए हम प्रभारी मंत्री से आग्रह करेंगे कि एक डिग्री कॉलेज गोपालगंज जिला के बरौली में खोलने की कृपा करें और एक मांझा में पॉलटेक्निक गर्ल्स कॉलेज खुलवायें, वहां की बच्चियां काफी क्वालिटी रखती हैं, वे बाहर जाकर अच्छा करती हैं, बच्चियां भी बाहर जाकर पढ़ती हैं दिल्ली में, साउथ में । वहां अपने गार्जियन के साथ रहती है लेकिन बच्चियों में, बेटियों में पढ़ने की जिज्ञासा हुई है । हमारे बच्चियों में एक बहुत बड़ा क्रांति आया है, बच्चे से ज्यादा उसमें क्वालिटी है और पढ़ाई में वे आगे बढ़ रही है । आप जाइए गांव में तो वे पढाई के लिए, सरकारी स्कूल में नहीं जाती है, वह कहती है कि सरकारी स्कूल में तो पढ़ाई ही नहीं है । वे अपने गार्जियन से कहती है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे और वहां अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे । बस जो प्राइवेट स्कूल की आती है, उसपर बैठकर जाती है और स्कूल में पढ़ती है । बच्चियां कहती है कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे तो तब ही हमलोग अच्छा शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर बन सकते हैं लेकिन सरकारी स्कूल में सुविधा नहीं है । सरकारी स्कूल भोजन देकर सोचती है कि हमारा काम हो गया । प्राइवेट स्कूल का मानव श्रृंखला में बहुत ज्यादा योगदान है जब शराबबंदी का हुआ । स्कूल के बच्चे-बच्चियां, टीचर शराबबंदी में जो वर्ल्ड रेकर्ड में नाम आया गिनीज बुक में नाम आया, वह सब बच्चों की देन है । एक बच्चा हमारे क्षेत्र में मांझा प्रखंड के इमलिया, वह बच्ची स्कूल में पढ़ती थी, वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी और हॉस्पीटल ले जाया गया लेकिन उसकी मौत हो गयी । लेकिन आज तक उसको कोई मुआवजा नहीं मिला तो सरकार इतना संवेदनहीन है, इसलिए मानव श्रृंखला जो दूसरा लगा, वह फ्लॉप कर गया, इसमें लोग गये नहीं, प्राइवेट स्कूल के लोग कोऑपरेट नहीं किये, इसलिए

उनका दूसरा श्रृंखला फ्लॉप करगया । इसलिए हम सरकार से चाहते हैं, सरकार को शिक्षा पर विशेष ध्यान दने की जरूरत है ।

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद) : माननीय सदस्य, आपका सिर्फ दो मिनट समय रह गया है ।

श्री मो0 नेमतुल्लाह : महोदय, जो मिड-डे मिल है, उसमें फर्जी स्टुडेंट का नाम लिखा जाता है और फर्जी स्टुडेंट का नाम लिखाकर पैसा ले लिया जाता है । यह जांच का विषय है । तो इसतरह से पैसा वसूला जाता है । महोदय, बहुत सारे स्कूल भवनविहीन हैं और सरकार दावा करती है कि एक भी स्कूल हम भवनविहीन नहीं रहने देंगे लेकिन मैं बताता हूँ कि मेरे क्षेत्र में, मांझा प्रखंड के श्रीरामपुर में आजतक स्कूल भवन नहीं बना, सृजित स्कूल है, प्राथमिक स्कूल है, बच्चे आज भी गाछ के नीचे पढ़ते हैं । मैंने जब वहां घूमने गया तो वहां पर एक कमरा मुख्यमत्री क्षेत्र विकास फंड से दिया, इसलिए माननीय मंत्री जी को भवन बढ़िया बनाकर देना चाहिए । एक मामला हमारे यहां लटका हुआ है, जबकि जमीन भी है,पैसा भी है लेकिन सरकार की उदासीनता के कारण आजतक वही मांझा प्रखंड में कोनही से टोली में एक प्राथमिक विद्यालयका भवन नहीं बना । जबकि पैसा है, जमीन है लेकिन सरकार का उसपर कोई ध्यान नहीं है । मैंने कई बार पत्र लिखा लेकिन आज तक वह भवन नहीं बनाया जा रहा हे । महोदय, तो इस तरह से नीचे स्तर के पदाधिकारी हैं, बी0ई0ओ0 है, डी0एस0सी0 है, बी0ई0ओ0 है, इन लोगों की धांधली चरम सीमा पर है । बिना पैसा लिये हुए कोई काम नहीं होता है। ये घोटाला करते हैं और मैनेज करके फिर आते हैं सेकेट्रेरियट में और उस घोटाले का फाईल खुद अपने ही देखते हैं ।

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद) : माननीय सदस्य आपका समय समाप्त हो रहा है ।

श्री मो0 नेमतुल्लाह : महोदय, एक मिनट । मदरसा का मामला है, मदरसा का पूरा ढांचा आज तक नहीं बना सिर्फ पदेन सदस्यों पर काम चल रहा है । जिसको नोमिनेट करना चाहिए, उसको नोमिनेट नहीं किया जा रहा है , क्यों नहीं हो रहा है ।

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री मो0 नेमतुल्लाह : एक सेकेंड महोदय । 735 में 211 मदरसों को अनुदान देने की बात कही थी, कुछ ही मदरसों को देकर खानापूरी कर लिया गया । इसलिए जितने भी बचे हुए मदरसे हैं, उनको अनुदान मिलना चाहिए । महोदय, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप टोला शिक्षक की बहाली होती थी, तालिमी मरकज की बहाली होती थी, जो टोला में घूमने वाले गली-गली में जो बच्चे हैं, उनको पढ़ाने के लिए ।

...क्रमशः...

टर्न-12/शंभु/09.03.18

श्री मो0नेमतुल्लाह : क्रमशः.......तालिमी मरकज कहां चला गया, ठप पड़ गया । आज जहां पूछिए तो न वो चल रहा है और न आगे के लिए कार्रवाई, उसमें टोला के लिए शिक्षक का, वो ये कर रहे हैं ।

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : अब आप समाप्त करें ।

श्री मो0नेमतुल्लाह : जो देख हैं वो टोला शिक्षक का बहाली नहीं हो रहा है और जो चल रहा था तो शिक्षा पर इतनी उदासीन सरकार रहेगी तो कैसे होगा । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : श्री जितेन्द्र कुमार जी, माननीय सदस्य जनता दल युनाइटेड, आपका समय है 10 मिनट ।

श्री जितेन्द्र कुमार : सभापति महोदय, आज शिक्षा विभाग के मांग के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूॅं । मांग के पक्ष में- आप बोलियेगा अपना कटौती के बारे में । सभापति महोदय, शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसके सहारे हम आगे बढ़ सकते हैं । शिक्षा एक ऐसा शस्त्र है जिसके सहारे हम हर चुनौतियों का सामना कर सकते हैं । शिक्षा एक अनमोल धन है जिसे खरीदा नहीं जा सकता है, जिसे बर्बाद भी नहीं किया जा सकता है। शिक्षा के सहारे आदमी आत्मनिर्भर बनता है, स्वाबलंबी होता है और किसी भी झंझावात से सामना कर सकता है । शिक्षा जीवन पर्यन्त मनुष्य के साथ रहता है और हर बुरे वक्त में शिक्षा एक सच्चे मित्र की तरह एक साये की तरह उस व्यक्ति के साथ रहता है और हर मुसीबत को झेलने में सहयोग करता है । इसी मर्म को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदरणीय नीतीश कुमार जी ने समझा। हमलोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और हमारा क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र है । माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि जब तक गांव का विकास नहीं होगा, ग्रामीणों का विकास नहीं होगा, गांव में रहनेवाले हमारे छात्र-छात्राओं का विकास नहीं होगा, रोजगार नहीं मिलेंगे तब तक बिहार का विकास संभव नहीं है । इसी को ध्यान में रखकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने सात निश्चय किया। सात संकल्प लिया और जिसमें सबसे ज्यादा फोकस किया गया है वह युवाओं पर छात्रों पर हमारे बच्चे शिक्षित हों, अपने पैरों पर खड़ा हों, हुनरमंद हो और रोजगार उन्हें मिले, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड उन्हें मिले । कई ऐसे हमारे अभिभावक हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, अपने बच्चों को पढ़ा नही पाते हैं, हायर एजुकेशन दिला नहीं पाते हैं । इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड चलवाया ताकि वे इंजीनियर की पढ़ाई कर सके, डाक्टर की पढ़ाई कर सकें, एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर सकें, डिप्लोमा कर सकें और अपने पैरों पर खड़ा हो सकें, यह माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है । इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी ने सोचा कि 20 से 25 साल के जो युवा हैं, नौकरी की तलाश में हैं उनको भी सुविधा दी जाय और प्रति माह एक हजार रूपये के हिसाब से दो वर्ष तक के लिए नौकरी प्राप्त करने के लिए, अध्ययन के लिए उन्हें वजीफा दिया जायेगा, छात्रवृत्ति दिया जायेगा ताकि वे अपने पैरों पर खड़ा हो सकें । लोगों को हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के युवा हैं उन्हें इंगलिश की जानकारी

हो, कम्प्यूटर की जानकारी हो ताकि वे हर कंपीटिशन को फेस कर सकें, अपनी प्रतिभा को निखार सकें । इसलिए इसकी भी पूरी व्यवस्था की गयी इस सरकार की तरफ से और आज यह स्थिति है । 2005 के पहले बिहार की स्थिति क्या थी ? मुझे भी 2005 में विधायक बनने का मौका मिला है और लगातार मैंने देखा है कि बिहार में क्या परिवर्तन हुआ है । बिहार में जो विकास हुआ है वह अभूतपूर्व है । उस समय स्कूलों की स्थिति क्या थी ? कमरे नहीं थे, भवन नहीं थे, टीचर नहीं थे, आज स्थिति है कि हर गांव में, हर टोले में स्कूल का निर्माण हुआ है, प्राथमिक विद्यालय बने हैं, मध्य विद्यालय बने हैं, हाईस्कूल लगातार बन रहे हैं और यह जो डाटा आया है, आंकड़ा आया है । अब एक परसेंट बच्चे हैं जो स्कूलों से बाहर हैं, उन्हें भी जोड़ने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है । हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जिनका सकारात्मक सोच है, जिनके रचनात्मक विचार हैं वे हर समय बिहार के विकास के बारे में सोचते हैं । समाज के अंतिम व्यक्ति के बारे में सोचते हैं और सरजमीन पर काम कैसे क्रियान्वित हो, कार्यों को कैसे अमलीजामा पहनाया जाय इसके लिए हमेशा गंभीर रहते हैं। आप देखते होंगे कि आम जनों की समस्या सुनते हैं और उसके निदान का प्रयास करते हैं। आप देखेंगे इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने न्याय यात्रा आरंभ किया, विकास यात्रा, प्रवास यात्रा, निश्चय यात्रा और समीक्षा यात्रा । यह दिखलाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी समाज के अंतिम व्यक्ति तक जाते हैं और उनकी समस्याओं को खुद सुनते हैं और उसके समाधान करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं । जनसंख्या की आधी आबादी महिलाओं की है, महिलाओं का कैसे विकास हो, हमारी लड़कियां कैसे पढ़े, गांव की लड़कियां कैसे पढ़े इसके लिए पूरी व्यवस्था की गयी है। मुख्यमंत्री साइकिल योजना को ही लीजिए- एक समय था 2005 के पहले जब पटना की सड़क पर कोई लड़की साइकिल चलाती थी या मोटर साइकिल चलाती थी या कार चलाती थी तो लोग घूरकर देखते थे, लेकिन आज गांव की पगडंडियों पर लड़कियां साइकिल चला रही है । क्या यह परिवर्तन नहीं है ? एक सामाजिक क्रांति है, एक पिन ड्राप साइलेंस रिवोल्युशन है, एक क्रांति है । इसलिए यह एक सामाजिक क्रांति हुआ ।

(व्यवधान)

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : शांति शांति बोलने दें, माननीय सदस्य को बोलने दें ।

श्री जितेन्द्र कुमार : एक मौन क्रांति हुई है, एक मौन क्रांति आप जान लीजिए ।

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : आपस में टीका टिप्पणी नहीं करें, माननीय सदस्य को बोलने दें ।

श्री जितेन्द्र कुमार : जो लड़कियां घर से निकलती नहीं थी वह आज सड़कों पर आ गयी हैं ।

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : आपका समय आयेगा तो बोलियेगा, अभी माननीय सदस्य को बोलने दें । कृपया माननीय सदस्य बैठ जाएं। आपस में टीका टिप्पणी नहीं करें, बैठ जाएं।

श्री जितेन्द्र कुमार : आपने क्या किया चरवाहा विद्यालय खोला कोई लाभ नहीं मिला । आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने साइकिल योजना दिया मात्र एक योजना पर मैं घंटों बोल सकता हूं ।

आपलोग भी घर में बैठते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा करते हैं भले राजनीतिक कारणों से आप कह दें कि बिहार में विकास नहीं हुआ, लेकिन अपने लोगों के बीच बैठते हैं, अपने घर में बैठते हैं तो निश्चित तौर पर कहते हैं कि बिहार में विकास हुआ है । माननीय मुख्यमंत्री जी के रहनुमाई में विकास हुआ है । आप निश्चित तौर पर कहते हैं । आज हरेक युनिवर्सिटी में, हरेक स्कूलों में, हरेक कॉलेजों में वाइफाई खुल रहा है- क्यों खुल रहा है कि हमारे बच्चे पढ़ें । आज दुनिया मुट्ठी में है जान सकें कि दुनिया में क्या हो रहा है, वाइफाई के माध्यम से, इन्टरनेट के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकें । पुस्तकालय जाने की जरूरत नहीं पड़े, इन्टरनेट पर अपना काम कर सकें । महोदय, आज बिहार में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बिहार में अद्‌भुत प्रतिभा है । आप कहीं किसी प्रदेश में जायेंगे, किसी देश में जायेंगे तो बिहार के लोग निश्चित रूप से आपको मिलेंगे । एक भी शिक्षण संस्थान यहां नहीं था, लेकिन आज बड़े बड़े चन्द्रगुप्त महाविद्यालय, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ है।

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : माननीय सदस्य, आपका दो मिनट है ।

श्री जितेन्द्र कुमार : महोदय, हमलोग तो सौभाग्यशाली हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी के रहनुमाई में विधायक बनने का मौका मिला और बहुत कुछ परिवर्तन देखने का मौका मिला है । हम एक दो बात कहना चाहेंगे क्षेत्र के बारे में कि हमारे शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव महाजन जी भी यहां उपस्थित हैं । प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की कमी है, उसको देखने की आवश्यकता है । एक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कई प्रखंड में हैं जैसे हमारे विधान सभा अस्थावां में नालन्दा जिला । अस्थावां के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कई जगह काम करते हैं तो काम नहीं हो पाता है । एक और कहना चाहेंगे । आपने प्लस टू कर दिया, लेकिन वहां उपस्कर नहीं भेजा, आपने वहां पर पुस्तकालय नहीं किया, आपने वहां लैब नहीं किया तो हमने आपके संज्ञान में दिया है । इसपर कार्रवाई करने की आवश्यकता है । दूसरी बात हम कहना चाहेंगे महोदय कि बहुत सारे एसी/डीसी बिल के कारण भवन अधूरे रह गये हैं । अस्थावां विधान सभा में माफी उच्च विद्यालय, चकदीन उच्च विद्यालय, महम्मदपुर उच्च विद्यालय आपके संज्ञान में हमने दिया है, अधूरे भवन हैं इसको पूर्ण कराने की आवश्यकता है ताकि वहां भी प्लस टू की पढ़ाई हो सके ।

क्रमशः

टर्न-13/अशोक/09.03.2018

श्री जितेन्द्र कुमार : क्रमशः... इसलिये महोदय बहुत कुछ कहना था और कई लोग कहते हैं कुछ नहीं हुआ तो यहां घण्टों तक उनका व्याख्यान करेंगे और सड़क पर जो अमलीजामा पहनाया गया है वो अद्‌भूत है, और आगे बिहार बढ़ रहा है, तरक्की बिहार कर रहा है तो हम तो समझेंगे ये जो इतिहास होगा, यह जो इतिहास होगा वह बिहार के

लिए गोल्डेन पीरियड होगा वह, नीतीश का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जायेगा, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ । जयहिन्द।

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद): माननीय सदस्य, श्री व्यासदेव प्रसाद जी । 13 मिनट ।

माननीय सदस्य टीका-टिप्पणी न करें, सबों को अवसर मिल रहा है, सभी अपनी बात कहेंगे ।

श्री व्यासदेव प्रसाद : माननीय सभापति महोदय, मैं शिक्षा विभाग के मांग पर जो कटौती का प्रस्ताव दिया गया है, उसके विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । माननीय महोदय, सियासत के दुनिया में, सियासत से इतर कुछ नहीं हो पाता है न कोई गठबन्धन, न कोई वादा, न कोई सेवा, न कोई बजट । फर्क सिर्फ शैली से पैदा होता है । बिहार के वित्त मंत्री माननीय सुशील कुमार मोदी की ओर से पेश 2018-19 के बजट में राजनैतिक शैली की संजीदगी एवं शालीनता के वजह से फर्क साफ दिखता है । राज्य की विधायी इतिहास में, विधायी इतिहास में सर्वाधिक नौ बार बजट पेश करने का साख रखने वाले माननीय श्री सुशील कुमार मोदी ने अपने इस बजट मिशन 2019 की रणनीति को जिस तरह से विकास के घूँघट का आवरण दिया, वह बाजीगरी काबिले तारीफ है । हर सम्भव राजनीतिक पुट के बावजूद यह बजट सिर्फ और सिर्फ विकास की मुनादि कर रहा है । बजट में पी.एम. एवं सी.एम. की सोच गॉव-शहर और किसान, युवा के बीच, संतुलन साधने की ईमानदार कोशिश हुई है। यह संतुलन ऐसा है कि विपक्ष को तथ्य आधारित आलोचना के लिए शायद ही कोई जगह मिले ।

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद): माननीय सदस्यगण, टीका-टिप्पणी न करें । माननीय सदस्य एक वरीय सदस्य हैं।

श्री व्यासदेव प्रसाद : महोदय, उत्तरप्रदेश के पिछले विधान सभा चुनाव में मतदाताओं ने साफ संदेश दिया था कि जाति आधारित वोट बैंक पॉलटिक्स से आजिज आ चुके हैं । अब हमें हमारे परिवार के लिये सहूलियत और राज्य के लिये विकास चाहिये । संयोग है कि इस सोच में हमारे पी.एम. श्री नरेन्द्र मोदी और सी.एम. श्री नीतीश कुमार बहुत करीब खड़े दिखाई पड़ रहे हैं । वित्त मंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जा का बजट इस बात का शंखनाद है कि बिहार की राजग सरकार विकास, खासकर ग्रामीण विकास को ही मिशन 2019 ब्रह्मास्त्र बनायेगी । माननीय सुशील कुमार मोदी जी ने बजट में पांच संकेत दिये हैं:- पहला, राष्ट्र के विकास में बड़ी भागीदारी निभाने की चाहत । मानव संसाधन के बेहतर प्रबंन्धन पर फोकस । दूसरा कुशल आर्थिक प्रबन्धन और सोशल सेक्टर पर ध्यान रखकर विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा होने का संकल्प । तीसरा है धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देकर राज्य की ब्रांडिंग की कोशिश, इसके लिए बौद्ध, जैन एवं सिख धर्मो से जुड़े स्थलों पर विकास पर जोर

दिया गया है । मान्यवर, सबसिडी लिकेज रोकने के लिये सरकार के द्वारा पुख्ता इंतजाम किया गया है । सेन्ट्रल बेनीफिशियरी डाटा बेस बनाने की पहल हुई है । पर्यावरण संरक्षण को तबज्जो प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के लिये हरित क्षेत्र को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 17 प्रतिशत करने का लक्ष्य निर्धारित सरकार के द्वारा किया गया है । माननीय सभापति महोदय, अब मैं शिक्षा बजट पर सदन के सामने अपनी बात रखना चाहता हूँ । आज शिक्षा मानव संसाधन के रूप में समावेशी विकास का मूल आधार है । बिहार प्राचीन काल से ही शिक्षा व ज्ञान का केन्द्र रहा है । मगध में नालन्दा विश्वविद्यालय और अंगक्षेत्र में विक्रमशिला विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के कन्द्र थे, जहां देश-विदेश के छात्र अध्ययन के लिये आते थे । चीनी यात्री व्हेनसांग ने नालन्दा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त की, इसी प्रकार मिथिला न्याय, मिमांसा, ज्योतिष और दर्शन के अध्ययन का केन्द्र था । वहां प्रारम्भिक शिक्षा टोल परम्परा से चलती थी । गुरू के घर पर रहकर विद्यार्थी अध्ययन करते थे । वे गॉवों में जाकर घरों से भिक्षाटन करते थे और भिक्षा में जो अन्न प्राप्त होता था उसी से गुरू परिवार और विद्यार्थियों का खाना बनता था । यह एक निर्धारित सामाजिक व्यवस्था थी । इस प्रकार मिथिला में शिक्षा का दायित्व समाज पर था । आज पुनः बिहार अपने प्राचीन गौरव को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हैं । माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के प्रयास से अर्न्राष्ट्रीय नालन्दा विश्वविद्यालय का पुनः उदय हो रहा है । प्राचीन विरासतों का संरक्षण एवं संवर्धन कया जा रहा है ।

माननीय सभापति महोदय, बिहार के बजट का आकार एक लाख छिहत्तर हजार नौ सौ नब्बे है, जिसमें शिक्षा बजट 2018-19 के लिये 32.1 हजार करोड़ रूपये मुहैया कराये गये हैं। पिछली बार दिये गये शिक्षा के मद में 25.2 हजार करोड़ था । मननीय सभापति महोदय, सरकार ने प्रदेश के युवाओं को बेहतर शिक्षा के साथ अच्छे रोजगार के काबिल बनाने की पहल कही जा सकती है जो सरकार का पहल है । महोदय, शिक्षा को मुख्य रूप से तीन भागों में बॉटा जा सकता है, पहला प्राथमिक शिक्षा, दूसरा माध्यमिक विद्यालय शिक्षा या उच्च माध्यमिक विद्यालय शिक्षा और उच्च शिक्षा । सर्वशिक्षा अभियान के तहत हमारी सरकार ने केन्द्र सरकार के द्वारा बिहार के लिए 21,420 प्राथमिक विद्यालयों की स्वीकृति प्रदान किया था।

....क्रमशः....

टर्न-14/ज्योति/09-03-2018

श्री व्यासदेव प्रसाद: जिसमें बिहार सरकार के द्वारा 21261 प्राथमिक विद्यालय खोले जा सकते हैं इसका प्रतिशत 99 प्रतिशत है, जो इस सरकार की उपलब्धि है । माननीय सभापति महोदय, इस बिहार के अंदर प्राथमिक स्कूल 19725 प्राथमिक विद्यालयों को सरकार ने 19621 प्राथमिक विद्यालयों को मध्य विद्यालयों में उत्क्रमित किया । वर्ष 2017-18 में विद्यालय से बाहर बच्चों की संख्या 1 परसेंट रह गयी थी अर्थात 1.91 लाख ही बच्चे स्कूल से बाहर है छात्र और क्लास रुम का अनुपात वर्तमान समय में 57.1 है सरकार का लक्ष्य है कि 40.1 करने हेतु 2.97 लाख के विरुद्ध 2.74 वर्ग कक्षा तक का निर्माण कराया जा चुका है जो कि 92 परसेंट इस सरकार की उपलब्धि है । कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के छात्रावास भवन निर्माण लक्ष्य 535 था, जिसमें 510 छात्रावासों का निर्माण कराया गया है ।

सभापति (श्री तार किशोर प्रसाद): माननीय सदस्य 1 मिनट में अपनी बात समाप्त करें ।

श्री व्यासदेव प्रसाद : दिव्यांग बच्चों के लिए जो सहाय्य उपस्कर होते हैं वह 1.3 लाख बच्चों को मुहैय्या करा दिया गया है । प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों की संख्या 70371 है, नामांकित छात्रों की संख्या 1.2 करोड़ हैं, बच्चे नामांकित है । इस बीच मध्याह्न भोजन से लाभान्वित बच्चों की संख्या 1.25 करोड़ है ।

सभापति (श्री तार किशोर प्रसाद): माननीय सदस्य अपनी बात को समाप्त करें ।

श्री व्यासदेव प्रसाद : जिन्हें सप्ताह में दो दिन मौसमी फल एवं एक दिन उबला हुआ अंडा दिया जा रहा है । उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र विषयों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था मैनेजिंग कमिटी के द्वारा किया जाता है । मौड्ल स्कूल योजना के तहत निर्मित 216 भवनों में वर्तमान शिक्षा सत्र से .....

सभापति (श्री तार किशोर प्रसाद): अपनी बात समाप्त करें ।

श्री व्यासदेव प्रसाद : माध्यमिक विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है । महोदय, शिक्षा की गुणवता को आगे ले जाने के लिए हमारी सरकार प्रयत्नशील है । इसके लिए बहुत सारे प्रशिक्षण महाविद्यालयों की स्थापना की गयी है और उनमें शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है । जहॉं तक प्रशिक्षण के गुणवत्ता का सवाल है, गुणवत्ता में निश्चित रुप से इस साल सफलता मिलेगी और बिहार अपने पूर्व के गौरव को प्राप्त करेगा । जयहिंद, जय भारत ।

सभापति (श्री तार किशोर प्रसाद) : माननीय सदस्य श्री विजय प्रकाश जी, 15 मिनट ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : महोदय, मैं व्यवस्था के सवाल पर हूॅं । महोदय, आपका संरक्षण चाहिए, नियमन चाहिए । वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की

मांग 03 शिक्षा विभाग, सूचना प्रावैधिकी विभाग, पर्यावरण एवं वन विभाग तथा समाज कल्याण विभाग पर वाद विवाद है, अनुदान रखा गया है । समाज कल्याण विभाग को छोड़कर किसी भी विभाग के मंत्री यहॉ उपस्थित नहीं है, तो कम से कम सदन यह अवगत होना चाहता है कि क्या उन विभागों के मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया, तो फिर सदन को अवगत कराईये ।

सभापति (श्री तार किशोर प्रसाद): माननीय सदस्य बैठ जांय । सरकार बैठी हुई है सरकार जवाब देगी ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : महोदय, सरकार बनती है, सरकार विभाग का बंटवारा इसलिए करती है कि उन विभागों की समस्याओं का निदान हो सके । महोदय, जब शिक्षा विभाग के मेन है और शिक्षा विभाग पर बहस हो रही है और शिक्षा विभाग के मंत्री यहॉ नहीं है, तो संसदीय कार्य मंत्री कम से कम सदन को यह अवगत करा दें कि इन विभागों के मंत्री किस परिस्थिति में अनुपस्थित हैं ?

सभापति (श्री तार किशोर प्रसाद): माननीय सदस्य सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी होती है और सरकार बैठी हुई है ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : महोदय, मैंने अपने जीवन काल में और संसदीय जीवन काल में ऐसा सीन कभी नहीं देखा कि विभिन्न विभागों के मंत्री उपस्थित न हों । महोदय, अगर विभिन्न विभागों के मंत्री उपस्थित नहीं हैं, तो बहस करने से बात सुनाने से क्या फायदा है इसलिए हमलोग जांय बाहर, कोई जरुरत नहीं है ।

सभापति (श्री तार किशोर प्रसाद): माननीय सदस्यों की भावना, एक बार बैठ जांय । माननीय सिद्दिकी साहेब , आप एक बार बैठ जांय ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : महोदय, कम से कम माननीय संसदीय कार्य मंत्री स्थिति तो स्पष्ट करें।

सभापति (श्री तार किशोर प्रसाद): करेंगे, आप एक बार बैठ जांय ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : आप इस पर नियमन दीजिये ।

सभापति (श्री तार किशोर प्रसाद): सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी है । सदन में सरकार के कई माननीय मंत्री बैठे हैं और पूरी जवाबदेही से बैठे हुए हैं और सरकार की ओर से समुचित उत्तर भी समय पर दिया जायेगा । माननीय सदस्य श्री विजय प्रकाश जी ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : महोदय, संसदीय कार्य मंत्री हैं, यहॉ सदन अवगत होना चाहता है संसदीय कार्य मंत्री ।

सभापति (श्री तार किशोर प्रसाद): सिद्दिकी साहेब, आप तो बहुत वरीय सदस्य हैं ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : इसलिए मैं पूछ रहा हूॅ कि संसदीय कार्य मंत्री हैं किस परिस्थिति में ये मंत्री अपने डिमान्ड्स को छोड़कर इनके सुपुर्द कर दिया है । बताईये ।

सभापति (श्री तार किशोर प्रसाद): आप बैठ जांय । माननीय सदस्य श्री विजय प्रकाश जी अपनी बात जारी रखें । अपनी बात शुरू करें, माननीय सदस्य श्री विजय प्रकाश जी समय बर्बाद नहीं करें । आपके दल का समय बर्बाद हो रहा है ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी : सरकार गंभीर नहीं है तो हमलोग इस बहस में क्यों शामिल होंगे, हमलोग बहिष्कार करते हैं ।

सभापति(श्री तार किशोर प्रसाद) : मेरा माननीय सदस्यों से आग्रह है कि एक बार बैठ जांय बहुत अच्छी बहस हो रही है सरकार समय पर उत्तर देगी । एक बार आग्रह है, माननीय सदस्य सिद्दिकी साहेब, आग्रह है कि आप बैठ जांय । माननीय मंत्री जवाब दे रहे हैं। एक बार माननीय सदस्य बैठ जांय ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : सभापति महोदय, माननीय सदस्य सिद्दिकी साहेब पुराने सदस्य हैं, अनुभवी भी हैं और जानकार भी हैं और ऐसे भी तो ये वाक आउट करेंगे, तो वाक आउट करने का पहले से बहाना ढूंढ रहे हैं । मैं आपको, सदन को बताना चाहता हूँ कि सरकार की पूर्ण जवाबदेही है, जो भी विभाग के डिमान्ड आए हैं, उसपर सरकार उत्तर देगी और माननीय सदस्यों के द्वारा जो सवाल उठाये जायेंगे, एक एक कर जवाब उनका दिया जायेगा, माननीय सदस्य को थोड़ा धैर्यपूर्वक सदन में प्रतीक्षा करनी चाहिए।

सभापति (श्री तार किशोर प्रसाद) : माननीय सदस्य श्री विजय प्रकाश जी, माननीय सदस्य दोजाना जी बैठ जांय । माननीय सदस्य श्री विजय प्रकाश जी अपनी भावना रखेंगे । माननीय सदस्य श्री विजय प्रकाश जी अपनी बात प्रारम्भ करें । एक बार बैठ जांय । सदन के चलाने में आप सभी माननीय सदस्यों का अभी तक बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। माननीय सदस्य श्री विजय प्रकाश जी प्रारम्भ करें।

श्री अब्दुल बारी सिद्दकी : हमलोग सदन का बहिष्कार करते हैं,आप अपनी बहस चलाते रहिये।

(इस अवसर पर रा.ज.द. के माननीय सदस्यों ने सदन से वाक-आउट किया)

टर्न-15/09.3.2018/बिपिन

सभापति (श्री तार किशोर प्रसाद): माननीय सदस्य श्री लक्ष्मेश्वर राय । 10 मिनट । जनता दल यूनाईटेड ।

श्री लक्ष्मेश्वर राय : सभापति महोदय, शिक्षा विभाग के बजट पर सरकार के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हूं ।

महोदय, बिहार का एक अपना पौराणिक इतिहास रहा है शिक्षा के क्षेत्र में । शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का बड़ा इतिहास रहा है । चाहे नालंदा विश्वद्यालय हो या और जो भी हमारा पौराणिक इतिहास है, वह शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही ऊंचा रहा है । वर्त्तमान में जो विद्यालय के लिए भौतिक संरचना हो, छात्र की उपस्थिति के अनुपात में

शिक्षकों की व्यवस्था हो, बच्चों का शत्-प्रतिशत् नामांकन, शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण हेतु सरकार पूर्ण रूप से प्रयास कर रही है । इसमें सफलता भी मिली है । बिहार जैसे प्रदेश के लिए मानव संसाधन सबसे बड़ी संपदा है । यहां के लोग परिश्रमी होते हैं । इस दिशा में शिक्षा विभाग पूर्ण रूप से प्रयासरत है ....

(व्यवधान)

सभापति (श्री तार किशोर प्रसाद): माननीय सदस्य आपस में बातचीत नहीं करें । माननीय सदस्य रामदेव बाबू । बातचीत नहीं करें ।

श्री लक्ष्मेश्वर राय: महोदय, बिहार सरकार में जो सात निश्चय आया है जिसमें सात निश्चय के तहत सात, निश्चय से पहले जो खासकर साईकिल योजना, पोषाक योजना, हमको लगता है यह मील का पत्थर साबित हुआ शिक्षा के क्षेत्र में हमारे बच्चे को आगे बढ़ाने में । साईकिल योजना से, गांव में जो शिक्षा से अछूता था, जो अंतिम व्यक्ति था, खासकर महादलित के बच्चे, अतिपिछड़ा के बच्चे, अल्पसंख्यक बच्चा जो शिक्षा से अछूता था, साईकिल और पोषाक योजना उन्हें प्रोत्साहन के रूप में काम किया और आज हमको लगता है कि गांव-गांव में शिक्षा के प्रति लोगों का भाव जगा है, लोगों को खुशहाल बनाया है और लगता है कि शिक्षा हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण अंग हो गया है ।

साथियों, सरकार भी खासकर आगे बढ़े, सात निश्चय के तहत अवसर बढ़े, आगे बढ़े, और सात निश्चय के तहत जो छात्र क्रेडिट कार्ड, स्वयं सहायता भत्ता जो योजना है, यह बड़े स्तर पर कामयाब हुआ है, खासकर सात निश्चय के तहत जो छात्र क्रेडिट कार्ड योजना जो आया है, जो गरीब बच्चा हमारे नहीं पढ़ पा रहे थे, हमको लगता है कि उनके लिए बड़ा प्रोत्साहन मिला है । सरकार को धन्यवाद हमलोग देते हैं कि आने वाले समय में हमारे जो छात्र अपनी गरीबी के चलते नहीं पढ़ पा रहे थे, आज सारे लोग उत्सुक होकर सरकार को धन्यवाद भी देते हैं । गांव के लोग उसके प्रति बहुत सजग भी है । दूसरा, आगे बढ़ें और अवसर बढ़े, उसके तहत भी जितने नर्सिंग कॉलेज हों, चाहे जी.एन.एम. कॉलेज हो और प्रशिक्षण संस्थान के साथ पारा मेडिकल कॉलेज, पारा मेडिकल संस्थान, बेगुसराय, वैशाली, सीतामढ़ी, भोजपुर, मधुबनी में, पांच जिला में नया मेडिकल कॉलेज की स्थापना, इसके अतिरक्त राज्य में जो 31 इंजीनियरिंग कॉलेज, 19 पॉलिटेक्निक कॉलेज, 76 सरकारी उद्योग प्रशिक्षण संस्थान, 21 महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खुलने के बाद गांव-गांव में और जिला में लोगों को, खासकर, लोगों में जो भाव जगा है, लोगों को जो टेक्निकल शिक्षा है, उसके प्रति लोगों का नजरिया बदला है, साथ-साथ उच्च शिक्षा में अवसर बढ़ाने के लिए तीन विश्वविद्यालय का भी जो सरकार द्वारा अधिसूचना जारी हुआ है, पूर्णिया, पाटलीपुत्र और मुंगेर में, यह भी उच्चतर शिक्षा के लिए एक बड़ा अवसर प्रदान किया है । साथ-ही, राज्य में जो तीन निजी विश्वविद्यालय खुला है, यह बिहार के इतिहास में पहली बार हुआ हैं । लोग इतने

उत्सुक हैं कि निजी विश्वविद्यालय खोला जा रहा है । यह बिहार के माहौल में जो परिवर्त्तन हुआ है, बिहार में जो सुशासन की सरकार है, नीतीश कुमार की जो सरकार है, पूरी तरह से बिहार के गांव में लोगों में शिक्षा के प्रति भाव जगा है, लोगों की शिक्षा के प्रति रूचि बढ़ी है, खासकर गांव में जो अंतिम व्यक्ति थे, महादलित, अतिपिछड़ा और कमजोर वर्ग के लोग, उनलोगों के अंदर भाव जगा है, दृष्टिकोण बदला है । हमारे जो पौराणिक इतिहास था, नालन्दा विश्वविद्यालय, जो दुनिया और देश में प्रसिद्ध था, आज उसी रूप में नीतीश कुमारजी का जो प्रयास है, हमको लगता है कि बिहार को इस देश और दुनिया में पुनर्स्थापना करने के लिए प्रतिबद्धता दिखाई पड़ रहा है । हम चाहेंगे, खासकर, जो कल तक लोग चरवाहा विद्यालय की बात कर रहे थे, जो चरवाहा विद्यालय हमलोगों को शिक्षा से दूर करने का प्रयास किया जा रहा था, हम लोगों को..

(व्यवधान)

सभापति (श्री तार किशोर प्रसाद): माननीय सदस्य जावेद जी । शांति बनाए रखें ।

श्री लक्ष्मेश्वर राय : जो गांव के अंतिम व्यक्ति थे, उनको, हमको लगता है शिक्षा से दूर करने का प्रयास था। आज चरवाहा विद्यालय में लोग नहीं जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि बड़ा-बड़ा मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज जो बिहार के लिए एक नया अध्याय जुड़ा है, गांधीजी का जो सपना था, जो गांधीजी के नाम पर आज शताब्दी समारोह पर विभाग द्वारा अच्छे-अच्छे कार्यक्रम किये जा रहे हैं जिससे देश में एकता की भावना जगे, देश में सद्भाव की भावना जगे, सरकार, खासकर, शिक्षा विभाग कई तरह की योजनाएं चला रही है । हमको लगता है कि बच्चों में शिक्षा के प्रति सामाजिक एकता, सद्भाव के प्रति देश की एकता की भावना भी बहुत मजबूती से सजग रहा है । आज जो खासकर, चम्पारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष के नाम पर जो भी कार्यक्रम किया गया है, हमको लगता है हमारे बच्चों में देश के प्रति भावना की भी जागृति के लिए भावना जग रहा है । साथ-साथ, एक बड़ा काम हुआ है कि राज्य के जो मदरसा और प्रस्वीकृत विद्यालय था, मदरसा हो या संस्कृत विद्यालय हो, जो मध्याह्न भोजन से अछूता था, यह पहली बार हुआ है कि मदरसा के बच्चों के लिए सरकार ने मध्याह्न से जोड़ा है, उनका जो वेतन कम था, उनका वेतन समान रूप में किया है। जो अल्पसंख्यक का बच्चा आज तक अछूता था, हम आदरणीय नीतीश कुमारजी के नेतृत्व में इनकी सोच के चलते आज अल्पसंख्यक स्कूलों में बच्चों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है । महोदय, आज मदरसा में अल्पसंख्यक के बच्चों की संख्या में बढ़ात्तरी हुई है । यह बड़ा इतिहास है कि जो लोग कल मुख्य धारा में नहीं थे, नीतीश कुमार जी का सोच है कि अल्पसंख्यक के बच्चे मुख्य धारा में आज बड़ी संख्या में आ गए हैं, चाहे वह मध्याह्न योजना हो, शिक्षक को प्रोत्साहन या उनका जो वेतन बढ़ा है, वह भी एक आधार बना है । मदरसा के बच्चों को भी जो पोषाक और साइकिल से उनको जोड़ा गया है, यह भी

एक हमको लगता है कि सामाजिक उन्नयन में, सामाजिक प्रगति में, सामाजिक शिक्षा में मजबूती से आगे आ रहा है । साथ ही ....

श्री शकील अहमद खाँ: सभापति महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है ...

(व्यवधान)

सभापति (श्री तार किशोर प्रसाद): आप आसन की ओर देखकर अपनी बात लगातार कहें ।

माननीय सदस्य शकील साहब, बैठ जाएं । अभी कोई प्वायंट ऑफ ऑर्डर का मामला नहीं है ।

(व्यवधान)

आपका जब समय आएगा तो आप विस्तार से अपनी बात रखेंगे । शकील साहब, आप बहुत बुद्धिमान सदस्य हैं, बैठ जाएं ।

सभापति (श्री तार किशोर प्रसाद): आप अपनी बात जारी रखें ।

(व्यवधान)

आपको जब समय मिलेगा, उसमें अपनी बात कहेंगे ।

श्री लक्ष्मेश्वर राय : सभापति महोदय, अब गुमराह नहीं होगा लोग, इसीलिए कि अब चरवाहा विद्यालय में नहीं पढ़ते और बड़ा बड़ा ...

(व्यवधान)

महोदय, अब बड़ा-बड़ा सुंदर कॉलेज नीतीश कुमार के राज्य में खुला है, इंजीनियरिंग कॉलेज भी खुल रहा है, मेडिकल कॉलेज भी खुल रहा है, यह बिहार का नया इतिहास है, बिहार का नया अध्याय है । याद करिए ।

(व्यवधान)

सभापति (श्री तार किशोर प्रसाद): शांति । शांति । आप आसन की ओर देखकर बोलें ।

श्री लक्ष्मेश्वर राय : सभापति महोदय, इनलोगों को अभी तक चरवाहा विद्यालय वाला प्रभाव है ही । अब नीतीश कुमार का राज्य है । अब देश में बिहार का अपना पौराणिक इतिहास जो था, उस रूप में बिहार देख रहा है । बिहार देश में मॉडर्न राज्य में प्रस्तुत हो रहा है । बिहार में शिक्षा दर बढ़ा है। बिहार की लड़की की जो शिक्षा है, वह बढ़ा है । बिहार का, खासकर, साक्षरता दर बढ़ा है । लोगों की मानसिकता बढ़ा है। शिक्षा के प्रति जो गांव अछूता था, कल लोग पहलवानी खेलते थे चरवाहा विद्यालय से लेकर और जगह, वो अब चरवाहा विद्यालय में नहीं जाना चाहते हैं । अब चाहते हैं स्कूल में जाएं । अब केवल एक प्रतिशत् बच्चा बिहार में स्कूल से बाहर रह गया है । यह इतिहास है । हमको लगता है चम्पारण शताब्दी वर्ष में बिहार का एक नया इतिहास जुड़ा है, नया इतिहास का एक अध्याय जुड़ा है । नीतीश कुमारजी के नेतृत्व में लगता है कि बिहार का अपना जो सम्मान था, गौरव था, आज वह अर्जन कर रहे हैं ... क्रमशः

टर्न 16/कृष्ण/09.03.2018

श्री लक्ष्मेश्वर राय (क्रमशः) कल जो चरवाहा विद्यालय में थे, वही खास करके यह घोटाला कर रहे थे । आज वे ही लोग शिक्षा में घोटाला कर रहे थे । यह ठीक बात है कि स्कूलों की जो स्थिति है, वह बदले । इसमें आपकी भी भूमिका की जरूरत है । आज गार्जियन, अभिभावक को भी चाहिए कि वे स्कूल के प्रति सजग रहें । स्कूल का संचालन कैसे हो, इस पर सजग रहना चाहिए । लेकिन एकतरफा जिम्मेवारी से नहीं होगा । हम मदरसा के संबंध में जो कह रहे हैं, वह ठीक कह रहे है कि मदरसा के शिक्षक पहले साईकिल से चलते थे लेकिन नीतीश कुमार जी के राज में अब वे मोटर साईकिल से मदरसा जा रहे हैं । बदलाव तो हुआ है । उनके चेहरे पर बदलाव आया है। उनके चेहरे की रौनकता बढ़ी है । उनके कपड़े का रंग बदला है । मदरसा का शिक्षक अब खुशहाल हैं नीतीश कुमार जी के राज में । आपको सोचना होगा ।

(व्यवधान)

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद) : शांति शांति ।

श्री लक्ष्मेश्वर राय : सरकार वेतन दे रही है । इसीलिये हम सबों से चाहेंगे कि यदि आप चाहते हैं कि बिहार उन्नत राज्य बने तो विपक्ष के भाईयों से कहते हैं कि यहां हल्ला से नहीं होगा, तर्क से कुछ नहीं होगा, परिश्रम से होगा । माननीय नीतीश कुमार जी कहते हैं कि कफन में जेब नहीं होता । माननीय नीतीश कुमार जी उसका नाम है जो कहते हैं कि कफन में जेब नहीं होता । माननीय नीतीश कुमार इस देश का पहले मुख्यमंत्री हैं कि उन्होंने अपनी निष्ठा और समर्पण के साथ बिहार का नाम पूरे देश और दुनियां में मजबूत किया है । यह आपको समझना होगा । आप याद कीजिये कल तक बिहार घोटाले का राज्य माना जाता था । आज लोग मानते हैं कि सामाजिक न्याय की सरकार है, यहां न्याय के साथ विकास हो रहा है, बिहार के प्रति लोगों की सोच बदली है, जहां भी जाईये बिहार की प्रतिष्ठा बढ़ी है, इस देश में कहीं भी जाईये, दुनियां में कहीं जाईये तो लोग कहते हैं कि आप बिहार से आये हैं, लोग कहते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी के राज्य से आये हैं, लोगों की सोच बदल जाती है, लोग समझते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी के बिहार से हैं, बड़ी परिश्रमी होंगे, बिहार के लोग बड़ी ईमानदार होते हैं, बड़ी निष्ठावान होते हैं । महोदय, यह चरित्र बदला है बिहार का । इसीलिये हम सबों से चाहेंगे कि सुंदर बिहार बनें, हम सब मिलकर माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आनेवाले समय में देश और दुनियां का सुंदर मोडल राज्य बने, इतना ही कहकर हम अपनी बात समाप्त करते हैं । धन्यवाद।

सभापति (श्री तारकिशोर प्रसाद) : माननीय सदस्या श्रीमती आशा देवी । आपका समय है 15 मिनट ।

श्रीमती आशा देवी : सभापति महोदय, वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिये शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्तुत मांग पर विपक्ष द्वारा दिये गये कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिये मैं खड़ी हुई हूं । महोदय, राज्य सरकार शिक्षा में सुधार के लिये सतत् प्रयत्नशील है, जिसके तहत 2017-18 में भी सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्य किये जा रहे हैं । वित्तीय वर्ष 2018-19 में शिक्षा विभाग के बजट में बढ़ोत्तरी कर क्षेत्र में विकास करने की इच्छाशक्ति को दर्शाता है । सभापति महोदय, सर्वशिक्षा अभियान के तहत अब तक 21,420 प्राथमिक विद्यालयों में से 21,261 प्राथमिक विद्यालय खोले जा चुके हैं । महोदय, 19,725 प्राथमिक विद्यालयों में से 19,621 को माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित किया जा चुके हैं । महोदय, सरकार की हमेशा मंशा रही है कि राज्य के गरीब बच्चों को स्कूल तक पढ़ाने के लिये लाया जा रहा है । शिक्षा के क्षेत्र में सरकार अच्छा काम कर रही है । महोदय, 2017-18 में अबतक विद्यालय से बाहर बच्चे की संख्या मात्र 1 लाख 91 रह गयी है । महोदय, सरकार बालिका विद्यालय के छात्रावासों के भवनों के निर्माण में 95 प्रतिशत अपना कार्य कर चुकी है । महोदय, अबतक 545 कस्तुरबा बालिका विद्यालय के भवनों में से 510 भवनों का निर्माण किया जा चुका है, जो सरकार की शिक्षा के प्रति इच्छाशक्ति को दर्शाता है । महोदय, सरकार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के कार्य-कलापों को प्रदर्शित करती है । सरकार शिक्षा के क्षेत्र में प्रयत्नशील है, जिसके तहत विगत वर्ष प्रमाण पत्र एवं सभी परीक्षाओं के लिये ऑन लाईन फौर्म भरने का काम किया था, जिससे कदाचारमुक्त परीक्षा का संचालन हो सके ।

महोदय, राज्य में निजी विश्वविद्यालय को खोलने में भी सरकार तीव्र गति से कार्य कर रही है, जिसके तहत अमीटी विश्वविद्यालय, पटना संदीप विश्वविद्यालय, सिजौल,मधुबनी तथा के0के0 विश्वविद्यालय, बिहारशरीफ की स्थापना हेतु अधिसूचना निर्गत की जा चुकी है एवं अल्ला कासिम विश्वविद्यालय, कटिहार तथा गोपाल नारायण विश्वविद्यालय, सासाराम को खोलने की दिशा में प्रयासरत हैं । महोदय, इसके अतिरिक्त तीन नये विश्वविद्यालय-पूर्णियां विश्वविद्यालय, पाटलीपुत्र विश्वविद्यालय एवं मुंगेर विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है, जिसका संचालन वर्तमान सत्र में शुरू किया जायेगा । महोदय, सरकार शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति का कार्य कर रही है, जिसके अन्तर्गत 9 हजार ऊर्दू एवं बंगला शिक्षकों का नियोजन किया जा चुका है । महोदय, राज्य के विश्वविद्यालय में रिक्त पदों पर 1354 सहायक प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति की जा चुकी है ।

महोदय, विपक्ष के माननीय सदस्यों को यह सब नहीं दिखता है । ये लोग सारे काम को उल्टा-सीधा करते रहते हैं । अभी शिक्षा विभाग के बजट पर सदन में चर्चा हो रही है, इसे सब को सुनना चाहिए । एक माननीय सदस्य बता रहे हैं कि बच्चे परीक्षा में चोरी करते हैं । जब बच्चे परीक्षा में चोरी करते हैं तो ये खुद बच्चे को

प्रोत्साहन देते हैं चोरी करने के लिये महोदय । माननीय सदस्य को खुद इस बात पर गर्व होना चाहिए कि शिक्षा के क्षेत्र में बिहार में काफी विकास हुये हैं । जिस तरह लालू प्रसाद जी के समय में चरवाहा विद्यालय खोला जाता था, उस समय बच्चे लोग क्षेत्र में कहते थे कि भैंस चरैब तो मट्ठा खईब । आज के बच्चे इस गाने को भूल गये हैं । इसलिये माननीय सदस्यों को बैठकर इस चर्चा को सुनना चाहिए, इस पर बहस करना चाहिए । महोदय, बिहार की स्थिति 1990 से लेकर 2005 तक इतनी खराब हो गयी थी महोदय, लॉ एण्ड ऑडर से लेकर शिक्षा तक सब कुछ ध्वस्त हो गया । इसलिए 1994 से 2003 तक मैं इनके सरकार में भुक्तभोगी हूं । आज की महिलायें अपना सब काम कर लेती हैं, महिलाओं का मनोबल बढ़ गया है, महिला सशक्तिकरण सचमुच में माननीय नीतीश कुमार जी के राज में हुआ है । आज हमारी महिलायें सारा काम करती है । पहले महिलायें डरती थी बाहर निकलने में, गार्जियन लोग अपनी बेटियों को विद्यालय पढ़ने के लिये नहीं जाने देते थे । महोदय, इनके शासनकाल में बहुत-सी बच्चियां अनपढ़ रह गयी हैं । पहले गांवों में प्राथमिक और मध्य विद्यालय तक रहता था। इसलिए पहले बच्चियां इससे आगे नहीं पढ़ पाती थी । वह बहुत पढ़ती थी तो 8वां 9वां तक ही पढ़ कर रह जाती थी, बच्चियां ग्रेजुएशन नहीं कर पाती थी । आज हमारी बच्चियां बिहटा से खगौल पढ़ने आती हैं, सदिसोपुर से खगौल पढ़ने आती हैं, नेवरा से खगौल पढ़ने आती हैं । दानापुर पढ़ने जाती है । पूरे बिहार की स्थिति है कि हमारी बच्चियां 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर चल कर पढ़ने के लिये जाती है और आज वे आत्मनिर्भर हुई है । आज ये कहते हैं कि सारी गलतियां पक्ष वाले करते हैं । महोदय, जनता ने इनको 18 महीने का समय दिया कि अपना कार्य ईमानदारीपूर्वक करें लेकिन नहीं कर पाये । जब ये सरकार में आये तो जनता में बहुत दशहत फैल गया कि अब क्या होगा ? 15 सालवाला फिर से जंगल राज आ गया । लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी, मैं इनके प्रति आभार प्रकट करती हूं कि इन्होंने अपनी बागडोर संभाल कर के रखा, इसीलिए 18 महीने हमारी क्षेत्र की जनता ठीक-ठाक रही । अगर 15 साल वाली स्थिति में अपनी बागडोर छोड़ देते माननीय मुख्यमंत्री जी तो हमारी जनता बहुत परेशान होती । आज ये कहते हैं कि हमारे क्षेत्र में यह हो रहा है, वह हो रहा है तो मैं पूछना चाहती हूं कि क्यों हो रहा है ? इसके लिये दोषी आप हैं, हम हैं । विद्यालय में टीचर क्यों नहीं जाता है? सारे विधायक अपने-अपने क्षेत्र के विद्यालय के अध्यक्ष होते हैं। तो टीचर विद्यालय क्यों नहीं जाते हैं ? महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारे क्षेत्र में भी विद्यालय है।

क्रमशः :

टर्न-17/सत्येन्द्र/9-3-18

श्रीमती आशा देवी(क्रमश:): मैं महीना में दो बार जरूर घूमती हूँ महोदय, बैठक यहां करें या न करें लेकिन वहां जाना जरूरी है इसलिए मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों को कहना चाहता हूँ कि हम आप में सुधारने की सख्ती होनी चाहिए । मैं यह कहना चाहती हूँ कि अभी तक बिहार में ये लोग 15 वर्षों में क्या किये, वह बतलायें और हमलोग 12-13 साल में क्या किये वह देखें । महोदय, मैं इनसे कहना चाहती हूँ कि जिस तरह ये लोग अफवाह उड़ाते हैं, क्षेत्र में अफवाह उड़ाकर जनता को गुमराह करने का काम करते हैं उससे हमारी जनता भयभीत होती है । माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब से सत्ता में आये हैं हमारी जनता इतनी सराहना करती है ,जनता कहती है कि विकास हुआ है । शिक्षा का स्तर, समाज कल्याण के स्तर को जब हमलोग देखते हैं, हमारी बच्ची लोग साईकिल चलाकर स्कूल जाती है, पहले बच्ची को स्कूल जाना होता था तो गार्जियन उनको पहुंचाने जाते थे, लाने जाते थे महोदय लेकिन आज देख रहे हैं कि हमारी बच्ची साईकिल चलाकर 2-4-5 कि0 मी0 से अपना घर आती-जाती है इसलिए आज हमारी बच्चियों का मनोबल बढ़ा है और इसके लिए मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देती हूँ । मैं माननीय मंजू वर्मा मंत्री जी को भी धन्यवाद देती हूँ कि आज आंगनबाड़ी केन्द्रों पर सभी बच्चों को पोषाहार मिल रहा है, जो महिलाएं गर्भवती है उनको भी पोषाहार दिया जा रहा है इसलिए सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि कहना यह है कि जबतक आप हम नहीं ईमानदार बनेंगे, बाकी लोग नहीं बन पायेंगे । माननीय विपक्ष के सदस्यों को मैं कहना चाहती हूँ कि यह सब आपके क्षेत्र में है आप उसको सुधार सकते हैं । माननीय मुख्यमंत्री जी अपना आदेश दिये हैं सारे विधायकों को कि अपने क्षेत्र में जायें और उसको सुधारें । महोदय, मैं यह कहना चाहती हूँ कि जिस तरह हमारे बिहार में सड़कों का जाल बिछा है, विद्यालय भवन के बारे में विपक्ष के सदस्य लोग बतला रहे थे कि नहीं बना है । महोदय, 2007-08 से पहले विद्यालय दिखाई नहीं देता था लेकिन आज दिखलाई दे रहा है कि फलां गांव में विद्यालय है और हमारे विद्यालय में टीचर भी जा रहे हैं इसलिए इस बात को मैं माननीय सदस्य से कहना चाहती हूँ जिस तरह आपका आंगनबाड़ी केन्द्र बन रहा है हर क्षेत्र में बन रहा है, माननीय सदस्य लोग अभी जो बोलते हैं कि यह चीज नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है तो यह उनलोगों को दखना चाहिए । अभी वृद्धावस्था पेंशन के लिए सरकार पैसा दे रही है लेकिन थोड़ा गलती हो जा रहा है कि जो आधार कार्ड से लोगों को जोड़ रहे हैं इसमें कुछ गलत हो जाने के कारण लोगों को वृद्धा पेंशन एकाउन्ट में नहीं आ रहा है । सरकार यह कह रही है कि सभी के एकाउन्ट में वृद्धा पेंशन जायेगा । महोदय, पहले मुखिया लोग के हाथ में वृद्धा पेंशन जाता है और वे लोग पहले मुंह देख देख कर कमीशन लेते थे और देते थे

इसलिए सरकार ने सोचा है कि हम अपना वृद्धा पेंशन लोगों के एकाउन्ट में देंगे इसलिए महोदय, मेरी सरकार यह सोची है । महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार प्रकट करती हूॅं कि वे इस तरह की व्यवस्था को ठीक ठाक किये हैं महोदय, सरकार द्वारा अभिभावक विहीन बच्चों को उनके दत्तक परिवार के पालन पोषण के हेतु पालक परिवार को 0-18 वर्ष के बच्चों को परिवरिश योजना के अन्तर्गत 1000/-रू0 प्रतिमाह की दर से अनुदान भत्ता दे रही है इसके तहत अब तक 14425 बच्चे को लाभान्वित किया है । महोदय, सरकार महिला के विकास और उनकी सुरक्षा के लिए भी कार्य कर रही है । महोदय, पीड़ित परिवार के महिलाओं को न्याय दिलाने हेतु सभी 38 जिलों के समाहरणालय परिसर में ही महिला हेल्प लाईन की स्थापना की गयी है जिसका टॉल फ्री नं0181 है । वित्तीय वर्ष 2017-18 में 3853 वादों का निष्पादन किया गया है साथ ही साथ पीड़ित परित्यकता महिलाओं के लिए 7 जिलों में सेंटर स्थापित किया गया है और इसके अन्तर्गत 911 वादों को निष्पादित किया गया है। महोदय, सरकार कन्या सुरक्षा हेतु .....

सभापति(श्री राजकिशोर प्रसाद): माननीय सदस्य आशा जी, अपने क्षेत्र की भी कुछ बात हो तो रख दें । अब आपका समय 3 मिनट रह गया है ।

श्रीमती आशा देवी: इस योजना के अन्तर्गत 2 लाख 82 हजार कन्या शिशुओं के लिए 2 हजार के फिक्स डिपोजिट का प्रमाण-पत्र दिया गया है । मेरे क्षेत्र में महोदय, शिक्षा मंत्री जी अभी बैठे हुए हुए है, श्रवण जी हैं जो अभी प्रभार में है । महोदय, दानापुर के दियारा क्षेत्र की समस्या है लॉ एंड आर्डर के तहत, दानापुर दियारा में 6 पंचायत है उसमें से 3 पंचायतों का छपरा जिला में थाना कर दिया गया है । महोदय, मैं आग्रह करूंगी कि उसको पटना जिला में ही रहने दिया जाय क्योंकि वहां के लोगों को बहुत कठिनाई छपरा आने-जाने में होगा इसलिए मैं मंत्री जी से आग्रह करती हूॅं कि पहले की तरह अकीलपुर का कार्य दानापुर से होता था उसे इस प्रखंड में ही रहने दिया जाय । महोदय, दानापुर के दियारा क्षेत्र में गंघारा, पानापुर में हाईस्कूल है वहां कोई टीचर उस पार जाने के लिए नहीं चाहते हैं । शिक्षा विभाग के जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, मंत्री जी से मैं कहना चाहती हूं कि उनको जो डियुटी मिला है, वह डियूटी समय से करें । ऐसा नहीं कि रजिष्टर इस पार मंगवाकर कर सिगनेचर करके अपना वेतन उठाते रहें इसलिए मंत्री जी से कहना चाहती हूॅं कि इसको जरूर सुधारें । उपरवार के विद्यालय में कहीं कोई दिक्कत नहीं है । वहां पुल नहीं रहने के कारण जाने में बहुत समय लग जाता है इसलिए वहां थोड़ा गड़बड़ी है उसको सुधार करें और दियारा वाला जो थाना है, कासिमचक, पुरानी पानापुर उसको दानापुर थाना से ही डील किया जाय क्योंकि वहां की जनता को छपरा जाने में बहुत कठिनाई होगी मैं इसलिए अपना दोबारा बात रख रही हूॅं, पहले जहां था वहीं रहने दिया जाय ।

श्री मुहम्मद जावेद: धन्यवाद सभापति महोदय, मुझे समय देने के लिए, मैं शिक्षा के कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए यहां खड़ा हुआ हूँ । सर, इसमें कोई शक नहीं कि शिक्षा एक बहुत ही अहम है किसी भी सोसाईटी के लिए और आपलोग जानते होंगे सर कि नेल्सन मंडेला ने कहा था- Education is most powerful weapon which who can use to change the world. इसमें कोई शक नहीं है कि किसी भी राज्य में या किसी भी देश में अगर शिक्षा अच्छी होती है तो वहां तरक्की बेहतर होती है, वहां का समाज ज्यादा खुशहाल होता है, वहां का समाज ज्यादा एकनोमिकली बेहतर होता है । सर, बिहार हमेशा सदियों से शिक्षा का केन्द्र रहा है और यहां हजारों माईल से दूर दूर से आकर लोग यहां से शिक्षा हासिल करते रहे हैं लेकिन कांग्रेस के राज के बाद से यह देखा गया है शिक्षा का स्तर धीरे धीरे गिरता गया और आज यह स्तर है कि लगभग दसों हजार करोड़ सलाना बिहार का पैसा बाकी राज्यों में खर्चा होता है सिर्फ पढ़ाई पर, अगर देखा जाय तो लाखों परिवार, लाखों पैरेंट्स अपने बच्चे को तालिम के लिए अपने पड़ोस के राज्यों में और यहां तक कि तमिलनाडू और गुजरात और राजस्थान तक अपने बच्चे को पढ़ने भेजते हैं, वह सिर्फ इसलिए कि यहां पर तालिम का स्तर बहुत ही निम्न स्तर की है ।(क्रमशः)

टर्न-18/मधुप/09.03.2018

...क्रमशः...

डॉ0 मुहम्मद जावेद : सर, वैसे तो जो जेनरल बजट है, उसका 18 परसेंट सिर्फ एजुकेशन में दिया गया है और एजुकेशन का बजट बढ़ाया भी गया है, जो 15 हजार करोड़ लगभग था 2017-18 में उसको 32 हजार कुछ करोड़ बढ़ा दिया गया है लेकिन इसका फायदा क्या हुआ ? क्या साक्षरता बढ़ी है ? क्या एजुकेशन का जो क्वालिटी है, वह बढ़ा है ? बिल्कुल नहीं । खास करके आज जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी फिर से एन0डी0ए0 में शामिल हुये हैं, जो साक्षरता का वैल्यू था धीरे-धीरे और घट गया है ।

आपलोग सब जानते होंगे, माननीय सभापति महोदय, हाल ही एक टी0वी0 इंटरव्यू में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने पकौड़ा तलने को भी एक रोजगार बता दिया है । जब से उन्होंने यह बोला है, साक्षरता का जो एक रूझान होता था पेरेन्ट्स में या स्टुडेंट्स में, उसमें काफी गिरावट आई है । हम मिसाल देना चाहते हैं, यू0पी0 के अभी बोर्ड के एक्जाम में 65 लाख स्टुडेंट्स जिनको इम्तिहान देना था बोर्ड का, लगभग 6.5 लाख स्टुडेंट्स ने एक्जाम देना नहीं पसन्द किया । उनलोगों ने माना है कि अगर पढ़-लिखकर भी हमें पकौड़ा ही तलना है तो हम पढ़-लिखकर क्या करेंगे ? यह सिर्फ इस वजह से है कि सरकार यहाँ की और केन्द्र की सरकार शिक्षा के लिये सीरियस नहीं है और शिक्षा को वह महत्व नहीं देना चाहती है और न देती है ।

माननीय सभापति महोदय, हमारे बिहार में जो आंकड़े आज शिक्षा विभाग की तरफ से दिये गये हैं, बताया गया है कि प्राइमरी स्टुडेंट्स लगभग 2.17 करोड़ हैं और 9वीं और 10वीं में 28 लाख है । 2 करोड़ 17 लाख और 28 लाख, मतलब सिर्फ 13 परसेंट हमारे बच्चे 9वीं और 10वीं में आ पाते हैं । क्यों ? कम से कम उनको ग्रेजुएट हमें बनाना है । 11वीं और 12वीं का जो आंकड़ा देखेंगे तो 2 करोड़ 17 लाख स्टुडेंट्स में सिर्फ 4.7 लाख स्टुडेंट्स 11वीं और 12वीं की पढ़ाई करते हैं जो सिर्फ 2 परसेंट हैं । क्या हमारा बिहार ऐसे आंकड़ों से आगे बढ़ेगा ? नहीं बढ़ेगा । अगर हमारे लोग बाहर जाते हैं तो या तो यहॉ से तालिम लेने के लिये जाते हैं या नहीं तो मजदूरी खटने के लिये जाते हैं, इसके अलावा तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है उनके लिये । जो बहुत गम्भीर है । सर, इतने स्टुडेंट्स के एजुकेशन के लिये जो नॉर्म्स है आर0टी0ई0 का, उसके तहत हर 30 स्टुडेंट्स पर एक टीचर की आवश्यकता है । हालॉकि किताब का आंकड़ा कुछ और बताता है लेकिन अगर आप जोड़ कर देखेंगे तो वह आंकड़ा 57:1 का रेशियो है । जहॉ हमें 7.5 लाख टीचर्स की आवश्यकता है, इनके पास 4 लाख भी टीचर्स नहीं हैं और उन टीचर्स की क्वालिटी भी आप देख लें सर, जो अपने-आप को टीचर ग्रेजुएट बताते हैं, वह एक पेज का एप्लीकेशन तक नहीं लिख पाते हैं । कई ऐसे उस्ताद हैं जो अपना नाम भी ठीक से नहीं लिख पाते हैं तो क्या हम अपने भविष्य को अंधकार में ठेलना चाहते हैं ? सर, कैसे हमारा एजुकेशन होगा ? जहॉ पर सेन्सस का काम होता है टीचर्स को लगा दो, इलेक्शन का काम होता है टीचर्स को लगा दो, कहीं आपदा होती है वहॉ टीचर्स लगा दो, कहीं पर वी0आई0पी0 मूवमेंट होता है, जन-सभा होती है, वहीं पर आप टीचर्स को इकट्ठा कर देते हैं गिनती दिखाने के लिये, और तो और यहॉ पर मानव श्रृंखला में भी उनको जोड़ दिया जाता है । यह बहुत ही दयनीय स्थिति है । इसको बदलना होगा नहीं तो हमारे बच्चे हैं हमें कभी माफ नहीं करेंगे । जो एमेनेटिज हैं, जो साधन हैं स्कूल में, कहा जाता है कि इतना करोड़ स्कूल के बिल्डिंग में खर्चा हुआ है । मेरे कंस्टीच्यूयेंसी में मॉडल स्कूल का फाउंडेशन हमने ले कर दिया दो साल कबल लेकिन दो-चार ईंटा के आगे नहीं बढ़ पाया है । क्यों नहीं बढ़ पाया है, कौन जिम्मेवार है इसका ? कहा जाता है कि स्वच्छ भारत अभियान, क्या-क्या तो नाम देते रहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, बहुत रेस्पेक्ट के साथ उनका नाम लेना पड़ता है अपने बचाव के लिये भी, स्वच्छ भारत । आप किसी भी स्कूल में चले जाइये सर, अगर टॉयलेट है तो वह भी इतना गंदा है कि बच्चे वहॉ नहीं जाते हैं, अव्वल तो टॉयलेट नहीं है । उसके अलावा न तो प्ले-ग्राउंड का कोई साधन है, न बेंच है, न टेबल है, न लेबोरेट्रीज हैं, न लाइब्रेरी है और किताब जो सरकार देती है, कभी-कभी तो साल भर के बाद । वरना जल्दी अगर दे दिया तो 6-8 महीना से कबल नहीं देती है । इसका जिम्मेवार कौन है ? क्या यही सुशासन राज है ? मैं जानना चाहता हूँ, सर, आपके माध्यम से । इसका

नतीजा क्या हुआ ? जब हमारा 32 हजार करोड़ 1 लाख 76 हजार करोड़ में 18 परसेंट 32 हजार करोड़ is going down the drains इसी का नतीजा है सर, कि गॉव-गॉव शहर तो छोड़ दें आप, गॉव-गॉव में कोचिंग इंस्टीच्यूट्स खुल गये हैं । कोचिंग इंस्टीच्यूट्स कब चलते हैं ? जब स्कूल चलता है । आप कभी भी इंस्पेक्शन करा लें सर, स्कूल में छात्र नहीं मिलेंगे, वे कोचिंग सेन्टर में मिलेंगे क्योंकि कम से कम वहॉ पर दो-चार सन्टेंसेज तो बना पाते हैं । यह दयनीय स्थिति है । सर, इसमें कोई शक नहीं है, हमलोगों की उम्र अधेड़ है, हमलोग जानते हैं कि जबतक कांग्रेस की सरकार रही हिन्दुस्तान का बेहतरीन से बेहतरीन एजुकेशन बिहार में मिलता था और इसमें गिरावट होते गई । आज यह स्थिति है कि अगर हम यहॉ से पढ़ भी लेंगे तो पकौड़ा तलने के अलावा हम और कुछ भी नहीं कर सकेंगे । सर, एक चीज बताते हुये मुझे फख्र नहीं हो रहा है, कुछ तस्वीरें होती हैं जो कोई दूर से देख ले तो पूरी दुनिया का लोग जानता है कि यह कौन है और यह किस अवसर का तस्वीर है - गॉधी जी का डांडी मार्च, नेहरू जी का वह शेरवानी और गुलाब लगा ले कोई, चेहरा न भी हो तो लोग बोलेगा कि नेहरू जी हैं, सुभाष चन्द्र बोस का यूनिफॉर्म जो आर्मी यूनिफॉर्म था वह, उसी तरह हमारे यहॉ एक पिक्चर छपी थी सर, तीन मंजिल का बिल्डिंग है और तीनों मंजिल के बाहर से लोग चढ़कर कुछ सप्लाई कर रहे थे, अन्दर एक्जामनेशन हॉल में । पूरा इंटरनेशनल फोरम में आप जाइये, पूरे दुनिया में लोग जानते हैं कि यह बिहार की तस्वीर है, यह सुशासन राज की तस्वीर है जहॉ पढ़ाई से नहीं पास होते हैं, यहॉ सिर्फ चीटिंग से पास होते हैं । यह वह स्टेट बनाकर इन्होंने रख दिया, जो कंडीडेट फर्स्ट आता है उसका री-एक्जामिनेशन होता है तो वह पास तक नहीं कर पाता है । यह वह स्टेट कर दिया इन्होंने । सर, बड़े अफसोस की बात है ।

आज बहुत लोग जो गवर्नमेंट में है और वह भी जो अपोजीशन में हैं, जो हमलोग हैं, हमलोग भी कहते हैं कि प्राइवेट एजुकेशन ठीक नहीं है । प्राइवेट एजुकेशन जरूरी नहीं होता अगर सरकारी एजुकेशन ठीक रहता लेकिन चूंकि सरकारी एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है, विफल है, फेल है तो कम से कम प्राइवेट को तो हम इनकरेज करें । मेरा सुझाव होगा सर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कि आप कम से कम नॉर्म्स बनाइये, सख्त से सख्त नॉर्म्स बनाइये, आप गरीबों के बच्चों का सीट रखिये लेकिन उनको भी मौका दीजिये । कम से कम दस हजार करोड़ ही सालाना हमारा पैसा जो बाहर जाता है, वह यहीं की धरती पर लगेगा । अगर स्कूलों में जो बहाली होगी तो हमारे ही पढ़े-लिखे बच्चे और बच्चियॉ उसमें टीचर्स बनेंगे और इम्पलायमेंट मिलेगा, हमारा समाज और बेहतर इकोनोमिकली होगा, डेवलप होगा ।

....क्रमशः ....

टर्न-19/आजाद/09.03.2018

.... क्रमशः ....

डॉ0 मुहम्मद जावेद : मेरा सुझाव है कि प्राइवेट स्कूलों को विलेन के नजरिये से नहीं देखा जाय। उनको सहुलियत दें, उनपर बिजली का दर कॉमर्शियल लगाते हैं, जबकि उसमें हमारे बच्चे पढ़ते हैं । उनको कामर्शियल बिल देना पड़ता है, हम चाहते हैं कि उनको इसमें छूट दें ताकि जिसमें आप फेसीलीटीज नहीं दे पायें, जो दे रही है, उसमें उनको सहूलियत मिले । सर, मिड-डे मिल की बात है, 1.90 करोड़ इनरोल्ड है, जिसमें से 1.25 करोड़ को मिड-डे मिलता है । आप भी एम0एल0ए0 हैं सर, हमलोग सब यहां पर एम0एल0ए0 हैं । क्षेत्र में जाते हैं, हमलोगों को बताया जाता है कि नहीं मिलता है, मिलता है लेकिन जिस क्वानटीटी और क्वालिटी में मिलना चाहिए, वह नहीं मिलता है । सरकार कहती है कि हफ्ते में दो दिन फल सिजनल मिलता है, लेकिन नहीं मिलता है। सरकार कहती है कि हम अंडा देते हैं हफ्ते में तो हम कह रहे हैं कि महीना में एक बार मिल गया सर तो बहुत है । मेरा सुझाव है कि लोकल टीचर्स नहीं रखा जाय । उसको जिला में ही दूसरे गांव में भेजा जाय, क्योंकि वह खेती के टाईम में वह खेती करता है, शादी के टाईम में वह शादी-विवाह में जाता है । इसलिए यदि आपको एजुकेशन में ध्यान देना है तो हमलोगों को इसपर जरूर सोचना होगा । समय कम रहते हुए यूनिवर्सिटी और कॉलेज की हमलोगों के यहां बड़ी किल्लत है । महोदय, हमने आंकड़ा दिया, 11 एवं 12 वर्ग का रेसियो हमने बताया कि सिर्फ 2 प्रतिशत है और कॉलेज और यूनिवर्सिटी का यदि आंकड़ा देखेंगे तो शायद मेरे हिसाब से .1 होगा, हमसे ज्यादा यहां के ऑफिसर बतायेंगे । मेरा सुझाव है ......

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : माननीय सदस्य, अब आप कनक्लूड करें ।

डा0 मुहम्मद जावेद : सर, दो मिनट । 100 उर्दू और 14 फारसी असिसटेंट प्रोफेसर का पद जमाने से वैकेंट है, इसको भरा जाय । मदरसा की हालत बहुत खराब है, उनकी जो सैलरी है, टीचर्स के हिसाब से होना चाहिए , उनको सिक्स पे मिलता है लेकिन उनको इनक्रीमेंट नहीं मिल पाता है । आपको लॉकल कमिटी को बर्खास्त करना चाहिए क्योंकि वे लोग वहां पर राजनीति करते हैं और अपने रिश्तेतार को टीचर्स में बहाली करते हैं । अगर टीचर्स की वैकेंसी हो तो बाजाप्ता सरकार एडवरटाईज करके सेलेक्शन करके टीचर्स को बहाल करे । बंगला-उर्दू टीचर्स के लिए 27हजार वैकेंसी थी, जो एक्जाम के बाद से 16882 पास किये, अभी तक इसमें से केवल 8 से 9 हजार लोगों को बहाली किया गया है । राजस्थान के तर्ज पर इनको ग्रेस मार्क्स देकर के इनको भी इम्पलायमेंट दिया जाय, चूँकि इनकी जरूरत है । मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि 2009 में माननीय

मुख्यमंत्री जी ने ऑल इंडिया उर्दू सेमिनार में उन्होंने कहा था कि हर स्कूल में टीचर्स होने चाहिए, उस हिसाब से 35हजार टीचर्स होने चाहिए । नियोजित शिक्षकों का सर मैं कहना चाहता हूँ कि जब वे सेम काम करते हैं तो उनको सेम सैलरी मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए । इसपर मेरी गुजारिश है कि इसपर सरकार का ध्यान देना चाहिए ।

सर, स्कॉलरशिप और लोन में बच्चे और पैरेंट्स परेशान हो जाते हैं । मेरा सुझाव होगा कि यह रिसपौंसबीलीटी स्कूल, टीचर्स और हेडमास्टर की होनी चाहिए, इसमें जिनको मिलना चाहिए, सबको मिले । जिनको नहीं मिले तो उनको क्वेश्चन पूछना चाहिए । जो टीचर्स अच्छे रिजल्ट लाते हैं, उसको चेक करके यह नहीं कि चीटिंग से करवा दिया या नम्बर से इधर से उधर जोड़-घटाव कर दिया, जेन्यूनली अगर वह अच्छा रिजल्ट देता है तो उनको अवार्ड मिलना चाहिए । पैरेंट्स-टीचर्स मीटिंग हर दो महीने में जरूर करना चाहिए, क्योंकि जो परेशानी लोकल है, इसका समाधान निकल सकता है सर। इसके अलावा ......

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : अब आप समाप्त करें । आपके क्षेत्र में तो कृषि महाविद्यालय बना है ।

श्री मुहम्मद जावेद : सर, यह पूरा मेरे क्षेत्र का ही बात है । मेरे क्षेत्र में और पूरा बिहार में मेरा यह मानना है कि जितने भी वैकेंसीज हैं, उसको जल्द से जल्द भरा जाय और उसको क्वालिटी टीचर्स से भरा जाय और उनके एटेंडेन्स को जरूर मॉनिटरिंग किया जाय और सी0सी0टी0वी0 लगाकर उसका मोनेटेरिंग किया जाय । मुझे मौका दिया आपने बोलने के लिए, मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ, बहुत-बहुत शुक्रिया, जयहिन्द ।

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : माननीय सदस्य श्री सुदामा प्रसाद जी, 5 मिनट ।

श्री सुदामा प्रसाद : माननीय सभापति महोदय, आपका आभार कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मैं अपने क्षेत्र की बात रखूँगा । विभाग ने तरारी विधान सभा में एक महिला कॉलेज खोलने के लिए जिलाधिकारी को जमीन चयन करने का निर्देश दिया है । लेकिन इस दिशा में जिला प्रशासन निष्क्रिय है, जबकि वहां जमीन भी उपलब्ध है हसन बाजार में। चूँकि वहां कोई महिला कॉलेज नहीं है पूरे अनुमंडल में, अनुमंडल का मुख्यालय है पीरो, अगर खुल जाय तो जो बच्चियां दशमा के बाद पढ़ नहीं पाती, उनके भविष्य का रास्ता खुलेगा ।

दूसरी बात सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करूँगा, सरकार से अनुरोध करूँगा कि बिहार के लाखों शिक्षकों की जो मांग है, जो आन्दोलनरत हैं कि समान काम के बदले समान वेतन मिलना चाहिए । उनकी मांगों को पूरा किया जाय, सरकार उसके प्रति उपेक्षा का रवैय्या नहीं अख्तियार करे । माननीय हाईकोर्ट ने भी इस सिलसिले में अपना फैसला सुनाया है और नये शिक्षकों की तेजी से

बहाली हो, बहुत ही अभाव है । छात्र लोग चन्दा करके टीचर्स रखे सरकारी विद्यालयों में, यह बहुत ही बदनामी की बात है सरकार के लिए । सहार में एक कन्या उच्च विद्यालय है, वहां एक ही शिक्षक हैं और बच्चियां 10रू0, 20रू0 चन्दा करके उन्होंने दो शिक्षकों को रखा है पढ़ाने के लिए । मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ कि शिक्षकों की तेजी से बहाली हो । वहां पर जो दो शिक्षक हैं, अगर आप उनको कानूनन भर्त्ती कर लें तो मैं समझता हूँ कि उस स्कूल का भला होगा । मेरे कहने से उन दो शिक्षकों का नुकसान नहीं हो, मैं ऐसा कह रहा हूँ ।

तीसरी बात जो है आंगनबाड़ी के बारे में कि आंगनबाड़ी जो है, वह कागज पर चल रहे हैं, आंगनबाड़ी की दुकान चल रही है। हर केन्द्र से तयशुदा राशि वसूली जाती है । वह केन्द्र चले या नहीं चले, बिल्कुल ही नहीं चल रहे हैं, खासकर के जो महादलितों के आंगनबाड़ी केन्द्र हैं, मुशहरी टोली के जो आंगनबाड़ी केन्द्र है और लोग दावे के साथ ताल ठोक कर लोग चालेंज करते हैं कि जहां जाना है जायं, हमको जो करना होगा, वही करेंगे । .....

श्री रत्नेश सदा : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था है ......

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : माननीय सदस्य श्री रत्नेश जी, आप बैठ जायं, उनको बोलने दें। माननीय सदस्य श्री सुदामा जी, आप अपनी बात जारी रखें । आप आसन को देखकर बोलें ।

श्री सुदामा प्रसाद : मैं अपनी बात वापस लेता हूँ । मैंने यह कोई दुर्भावना से यह बात नहीं कहा । महादलित बस्तियों में, महादलित मुहल्ले में, पीरो में, हसनबाजार में, फतेहपुर में, सिकरहटा में, बरूही में जाकर के आप पता करवा लीजिए । वहां सेविका नहीं जाती है, वहां केन्द्र के नाम पर दूसरे मुहल्ले में चलता है और उस मुहल्ले में अगर महादलितों के बच्चे जाते हैं तो दूसरे बच्चे या शिक्षिका या सेविका तक उनको डांटकर भगा देती है कि भागो तुम्हारा देह महक रहा है । महोदय, मैंने जिन केन्द्रों की चर्चा की, उसकी जॉच हो और केन्द्र चले क्योंकि सबसे ज्यादा उन्हीं मुहल्ले को इसकी जरूरत है । एक बात कि जो छात्रवृत्ति बन्द है कई सालों से, हमारे विधान सभा क्षेत्र के एक छात्र अम्बाला में पढ़ते हैं ओमप्रकाश, निजी संस्थान में पढ़ते हैं, उनका छात्रवृत्ति बन्द है । हमने कई बार यहां के जिलाधिकारी को भी कहा, कल्याण विभाग के मीटिंग में भी उठाया, लगता है कि उनकी पढ़ाई छूट जायेगी । इसलिए इसको चालू कराया जाय । खूटहॉ हाई स्कूल के कई बच्चे छात्रों ने हमसे शिकायत किया कि हमलोगों को पोशाक एवं साईकिल का पैसा नहीं मिला । स्कूल के हेडमास्टर कहते हैं कि पी0एन0बी0 के मैनेजर कहते हैं कि कुछ दम रखिए, हम इसको ठीक कर देंगे । यह नोट किया जाय, उनकी जो यह मनमानी चल रही है, इसपर रोक लगाया जाय । यह जो शिक्षा जगत के प्रति, शिक्षण-संस्थानों के प्रति जो सरकार का उपेक्षा है, इसी उपेक्षा के वजह से निजी

स्कूल फल-फूल रहे हैं । मैं समझता हूँ कि सरकार को इस मामले में गंभीर होना चाहिए । धन्यवाद महोदय ।

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : माननीय सदस्य श्री निरंजन कुमार मेहता ।

टर्न-20/अंजनी/दि0 09.03.2018

श्री निरंजन कुमार मेहता : माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2018 के अनूपूरक व्यय विवरणी पर सरकार द्वारा प्रस्तुत अनुदान की मांग के समर्थन में और कटैती प्रस्ताव के विपक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । महोदय, आपने समय दिया, मैं आपका हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ । इस सदन में इनके सानिध्य से सारा विभाग चल रहा है, शिक्षा विभाग चल रहा है, मैं विकास पुरूष माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ । मैं आभार प्रकट करता हूँ माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का, अभी उनकी जगह माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय विराजमान हैं, मैं उनका भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ । आज शिक्षा पर बोलना है और शिक्षा का जो बजट पेश हुआ है, मैं उसका समर्थन करता हूँ । शिक्षा पर बहुत सारी बात हमारे माननीय सदस्य लोग बोले हैं । विपक्षी लोगों को सत्ता पक्ष की बात सुनने का धैर्य ही नहीं है, केवल हल्ला-गुल्ला करके सदन से बाहर चले जाते हैं, वाकआउट कर जाते हैं । उनको भी सत्ता पक्ष की बात धैर्य से सुनना चाहिए । कल इधर थे तो अच्छा लगता था और आज उधर गये हैं तो किसी की अच्छी बात भी, सरकार की अच्छी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी की बात उनको ठीक नहीं लगती है ।

महोदय, आज शिक्षा को देखिए, वर्ष 2003 ई0 में उस समय हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथ में सत्ता नहीं थी, वर्ष 2003 में शिक्षा मित्र का बहाली किया गया ग्राम पंचायत के द्वारा । ग्राम पंचायत के जन-प्रतिनिधि माननीय मुखिया जी के द्वारा उनके कमिटी के द्वारा वर्ष 2003 में शिक्षा मित्र का नियोजन किया गया तो उस शिक्षा मित्र में मैंने देखा है, मैं स्वयं 2001 से 2015 तक ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व किया हूँ । उस समय कोई भी शिक्षक बनने के लिए तैयार नहीं थे, बुला-बुलाकर हमलोग शिक्षक बनाते थे, मात्र एक पंचायत में दो-तीन जगह दिया गया था । वर्ष 2003 में खोज-खोजकर हमलोग शिक्षक बनाने का ग्राम पंचायत में काम किये थे । 50 रूपया डेलीवेजेज पर और 1500 रूपया प्रति माह तय किया गया था सरकार के द्वारा जो उस समय की सरकार थी । लेकिन आज वर्ष 2005 में हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथ में जब सत्ता आयी, बागडोर आयी तो तुरंत वर्ष 2006 में, 2005 में उस शिक्षा मित्र को पंचायत शिक्षक का दर्जा दिया गया । वर्ष 2006 में फिर वही दर्जा रहा, वर्ष 2012 में फिर वही दर्जा रहा, उसके बाद टी0ई0टी0 की व्यवस्था की गयी शिक्षा विभाग

द्वारा और आप कहते हैं कि अनपढ़ शिक्षक की बहाली की गयी । आज कैसे-कैसे खोज करके शिक्षक को बनाने का काम किया है ग्राम पंचायत में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सानिध्य से, इनके विवेक से, इनके निर्देश से । आज जब वर्ष 2005 में पंचायत शिक्षक की बहाली की गयी, नियोजन किया गया तो फिर भरमार आवेदन आने लगे ग्राम पंचायत में लेकिन वर्ष 2003 में नहीं आवेदन आता था । आज जब वर्ष 2005 में पंचायत शिक्षक की नियुक्ति हुआ, वर्ष 2012 में, वर्ष 2005 में 6 हजार रूपया उसका मानदेय किया गया और आज टी0ई0टी0 के द्वारा फिर ग्राम पंचायत में शिक्षक का नियोजन हो रहा है और अभी-भी शिक्षा विभाग के दिशा निर्देश में परिवर्तन किया गया है, हरेक जगह उसकी व्यवस्था हो रही है । आज स्कूल में शिक्षक कम हैं लेकिन स्कूल की व्यवस्था जो सुदृढ़ हुआ है, व्यवस्था में जो सुधार हुआ है, चाहे आज भवन की बात हो, फर्नीचर की बात हो, वर्ष 2005 के पहले किस स्कूल में भवन खड़ा था, सब जर्जर भवन था । वर्ष 2005 के बाद आज हरेक विद्यालय का भवन सुसज्जित है, जहां-जहां जो चाहा एक मंजिल, दो मंजिल, तीन-तीन मंजिल तक का प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय का भवन बना हुआ है, फर्नीचर का भरमार है । सब जगह पूरी व्यवस्था है, बिजली की भी व्यवस्था ग्राम पंचायत के द्वारा दी गयी, हमलोग बिजली लगाने का काम किये थे हरेक स्कूल में, हरेक विद्यालय में तो यह किसकी देन है ? यह हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का देन है । माननीय नीतीश कुमार जी के सरकार की देन है । आज हम बताना चाहते हैं कि सभी 12वीं पास छात्र एवं छा़त्राओं के लिए सात निश्चय के तहत, आज जो 12वीं पास होता है, उसकी आर्थिक स्थिति तंगी रहती है, अभी-अभी तुरंत माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज चार लाख रूपये का शिक्षा ऋण की व्यवस्था की है, जो सात निश्चय के तहत है । महोदय, बैंक के अकर्मण्यता के चलते इन्होंने तुरंत शिक्षा वित्त निगम का व्यवस्था किया और चार लाख रूपया लेकर आज हमारे छात्र-छात्रायें जिनको पढ़ने का विचार है, पढने का मन है, जो तेजस्वी छात्र है, चाहे उनकी डाक्टरी की पढ़ाई हो या इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो चाहे सिम्पल बी0ए0, बी0एड0 करना चाहते हों, आज सरकार के द्वारा उनके लिए ऋण की व्यवस्था की गयी है । जिनको जितना पढ़ना है, उतना वह पढ़ सकते हैं । स्टुडेंट केडिट कार्ड की तरह चार लाख रूपये की पर्याप्त राशि की सुविधा प्रदान की गयी है और वे किसी भी तरह की पढाई कर सकते हैं । स्टुडेंट केडिट कार्ड लागू होने के बाद जब बैंक की अकर्मण्यता देखी गयी, छात्र-छात्रा को पैसे देने में बैंककर्मी देर की तो सरकार, माननीय मुख्यमंत्री महोदय अभी-अभी तत्काल शिक्षा वित्त निगम के द्वारा राशि उपलब्ध कराने का नियम लागू किया जो कि 01 अप्रील, 2018 से लागू किया जायेगा । इस शिक्षा ऋण का सम्पूर्ण भार सरकार उठायेगी । लाचार छात्र-छात्राओं जो 12वीं के बाद पढ़ाई करने से तंग हैं , वे ऋण लेंगे, उसकी सारी जवाबदेही सरकार की होगी । आज

देखिए, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था किया गया, पहले बच्चे स्कूल में नहीं आते थे, हमलोग अपने आंख से देखे हैं, गांव के लोग हैं, गांव से आये हैं, एक भी बच्चे स्कूल नहीं आते थे तो इसके लिए शिक्षक को भार दिया गया और टोला सेवक की बहाली की गयी कि आप बच्चे को लाकर स्कूल में दीजिए । हरेक जगह नवसृजित विद्यालय की व्यवस्था किया गया और जितने भी महादलित का टोला होगा, संभवतः कोई टोला नहीं होगा जहां नर्सरी, प्राथमिक विद्यालय की व्यवस्था नहीं की गयी होगी सरकार के द्वारा । आज टोला सेवक को घर-घर जाकर पकड़-पकड़कर बच्चों को लाकर पढ़ाने का काम किया गया है तो यह सारी व्यवस्था इस सरकार की है । आज जब मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की गयी तो बच्चे स्कूल में आने लगे, बच्चों की संख्या में, छात्र-छात्राओं की संख्या में वृद्धि हुई । हमलोग अपनी आंख से देखे हैं इस चीज को । महोदय, साईकिल की व्यवस्था की गयी नवम् वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए, वे पांच-पांच किलोमीटर गांव से हाई स्कूल जाते थे, आज हरेक ग्राम पंचायत में टेन प्लस टू की व्यवस्था की गयी है । मैक्सिमम जगह भवन बनकर तैयार है, सारी व्यवस्था हो`रही है, संचालन भी किया जायेगा, बहुत जगह हाई स्कूल संचालित हो ही गया है । हरेक ग्राम पंचायत में सरकार हाई स्कूल दे रही है, जहां नहीं है, वहां सरकार व्यवस्था कर रही है, इसके लिए हतोत्साहित होने की क्या बात है ? सरकार सब काम कर रही है । महोदय, स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड वर्ष 02 अक्टूबर, 2016 से प्रारंभ है और आज तक 13,538 आवेदन स्वीकृत किया गया शिक्षा विभाग के द्वारा चार लाख रूपये का ऋण । महोदय, आज सर्व शिक्षा अभियान के तहत आज तक जो डाटा डिटेल है, शिक्षा विभाग का जो बजट प्रतिवेदन है, जो भी प्रोगेसिव प्रतिवेदन दिया गया है, हम इसका पुरजोर समर्थन करते हैं । इस प्रतिवेदन को किसको सुनाया जाय, सुनने के लिए यहां है कौन ? हमलोग तो पक्ष के हैं, हमलोग सब तो डीटो कर रहे हैं लेकिन जो सुनने वाले थे, वे सुनने वाले भाग गये यहां से । हमलोग तो सुनेंगे ही । इसलिए इस प्रतिवेदन का हमलोग समर्थन करते हैं, मैं समर्थन करता हूँ, बजट का पुरजोर समर्थन करता हूँ । महोदय, सर्व शिक्षा अभियान के तहत अब तक 21,420 प्राथमिक विद्यालय के लक्ष्य के विरूद्ध 21,261, यानी 99 परसेंट प्राथमिक विद्यालय खोले जा चुके हैं । सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय से मध्य विद्यालय में उत्क्रमण के अब तक कुल 19,725 लक्ष्य के विरूद्ध 19,661 यानी 99 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों को मध्य विद्यालय में उत्क्रमित किया गया है। विद्यालय से बाहर के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने में मात्र एक परसेंट की कमी रह गयी है । ग्रामीण विकास विभाग के सहयोग से सरकारी विद्यालयों में नामांकित सभी छात्र-छात्राओं के आधार कार्ड के निर्माण का भी कार्य चल रहा है एवं लगभग 67 परसेंट बच्चों का आधार कार्ड पंजीकृत हो गया है । महोदय, सरकारी विद्यालय में नामांकित छात्र-छात्राओं को (क्रमशः)

टर्न-21/शंभु/09.03.18

श्री निरंजन कुमार मेहता : क्रमश :........प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है ।

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : अब कन्क्लुड करेंगे ।

श्री निरंजन कुमार मेहता : पहले जो प्रोत्साहन राशि दी जाती थी उसमें होता था कि शिक्षक इधर उधर करते रहे हैं । सरकार तो अब उसके गार्जियन के, उसके अभिभावक के खाते में राशि स्थानान्तरित कर रही है । यह भी देखने की बात है । महोदय, 70 परसेंट बच्चों का बैंक खाता खोला जा चुका है । माता पिता के खाते का संधारण किया जा चुका है। सबके खाता में राशि दी जा रही है । महोदय, कुछ बात बताना चाहेंगे, कुछ सुझाव देंगे। हमलोग तो सरकार, सत्तापक्ष में हैं । यहां पर हमारे प्रधान सचिव महाजन साहब भी बैठे हैं । हम बिहारीगंज विधान सभा से आते हैं और बिहारीगंज में हमने इसके पहले भी एक बी0इ0ओ0 का मांग किया था, चूंकि बी0इ0ओ0 बिहारीगंज में नहीं है । पिछले साल ही जब अशोक चौधरी साहब शिक्षा विभाग के माननीय मंत्री महोदय हुआ करते थे। हमने जाकर दिया था, लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि अभी तक वहां पर बी0इ0ओ0 का पदस्थापन नहीं किया गया है । हम प्रधान सचिव साहब से चाहेंगे कि इसको आप अपने संज्ञान में लें और बिहारीगंज में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी दिया जाय । माननीय मंत्री महोदय तो आदेश करेंगे ही- जब पदाधिकारी बैठे हैं तो उनको भी बोलना है न हमको ।

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : अब कन्क्लुड कीजिए, बातचीत न करें ।

श्री निरंजन कुमार मेहता : महोदय, मेरा एक सुझाव और यह है कि ग्राम पंचायत में जो पंचायत शिक्षक हैं, अभी हमारे कुछ साथी लोग बोले हैं इसपर । पंचायत शिक्षक की व्यवस्था में सुधार हो कि जो पंचायत में शिक्षक हैं लोकल हैं, उसी पंचायत के हैं । हम ही लोगों के कोई हैं भाई है या लड़का है या कोई है । उसमें होता क्या है कि मनमानी होती है, राजनीति भी पैदा हो गया है तो हम चाहेंगे माननीय मंत्री महोदय से और शिक्षा विभाग के पदाधिकारी हेड यहां बैठे हुए हैं । इस व्यवस्था पर थोड़ा विचार किया जाय और कम से कम एक पंचायत से दूसरे पंचायत में इसका स्थानान्तरण किया जाय तो पढ़ाई की व्यवस्था भी सुदृढ़ होगी और अनुशासन भी रहेगा । आज कोई जॉच करने के लिए जाते हैं तो उसमें दिक्कत होती है, सब लोकल है । पंचायत से ज्यादा दूर नहीं दिया जाय, पंचायत से पंचायत में जाने की अगर व्यवस्था होती है स्थानान्तरण करने का तो आपकी व्यवस्था में सुधार आयेगा ।

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : माननीय सदस्य, अपनी बात समाप्त करें ।

श्री निरंजन कुमार मेहता : महोदय, एक मिनट । हमलोग अपने आंख से देखे हैं इस बात को पढ़ाई की व्यवस्था भी सुदृढ़ हो जायेगी । हमलोग भी इसमें मदद करेंगे, सहयोग करेंगे । हमलोगों के सहयोग से काम होता है । एक सुझाव और है मेरा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय इसी सदन से निदेशित किये थे शिक्षा विभाग को कि बी0पी0एस0सी0 की जो परीक्षा होती है, आज

चार वर्ष में उसका रिजल्ट आऊट होता है । हमारे जो पढ़नेवाले बच्चे हैं, छात्र-छात्रा हैं वे दिल्ली में बैठकर तैयारी करते हैं । कोई कहीं पर करती है, उसको रेगुलर किया जाय और हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय कैलेंडर लागू किये थे और शिक्षा विभाग इसको सुचारू रूप से लागू करे । हरेक वर्ष का रिजल्ट हरेक वर्ष निकले तो बच्चे हतोत्साहित नहीं होंगे ।

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद) : अब आप समाप्त करें ।

श्री निरंजन कुमार मेहता : जिसको एक बार नहीं होता है उसको दूसरी बार परिश्रम का फल मिलेगा। यह बात भी होना चाहिए यह मेरा सुझाव है । हम तो सरकार में हैं, सत्ता में है जो बजट आया है उसका पुरजोर समर्थन करते हैं । मैं पुनः आपका आभार व्यक्त करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार प्रकट करता हूँ, मंत्री महोदय का आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद ।

श्री संजीव चौरसिया : महोदय, 2018-19 के लिए पेश शिक्षा विभाग के कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि शिक्षा के मापदंड के दृष्टि से हर विश्वविद्यालय कैंपस में हर चीज को सुदृढ़ करने के लिए छात्रसंघ की जो आवश्यकता होती है कि छात्र नेतृत्व उस चीज का ध्यान रखने का काम करे । 8 विश्वविद्यालय में 6 विश्वविद्यालय में चुनाव संपन्न हो चुके हैं सफलतापूर्वक उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बिहार सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद । आज निश्चित तौर पर बिहार के दृष्टिकोण से उच्च शिक्षा की बात करते हैं तो बहुत सारे आयाम को छूने का काम बिहार सरकार ने वर्तमान में किया है । मित्रों ने बहुत सारे विषय बताये हैं कि आज जब उच्च शिक्षा के दृष्टिकोण से बातें आती हैं तो दृष्टिगोचर जाता है कि पूर्व में उच्च शिक्षा के बारे में इन्होंने क्या किया है । किनकी सरकार बिहार में लंबे समय तक रही है । आज उनकी स्थिति क्या रही कि वास्तव में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता का जो आधार संरचना होनी चाहिए उसके बारे में विचार हुआ क्या । उच्च शिक्षा के दृष्टि से जितने प्रकार के विचार चल रहे हैं अब, उसके बारे में विचार उस समय हुआ क्या ? वास्तव में नकारात्मक पूरा दृष्टिकोण रहा था । आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ऐसे सरकार ने जो हरेक विषय को लेकर आगे बढ़ने का काम किया है और संसाधनों के कारण से डैक एविएडेशन की जो बात विश्वविद्यालय की तरह जो किया जा रहा है कि वित्तीय वर्ष के समग्र निर्माण हेतु 9.995 करोड़ रूपया स्वीकृत किया गया है । आज विश्वविद्यालय की जब बात करें तो विश्वविद्यालय के नये जो माननीय सदस्यों ने बताया है कि तीन सरकारी विश्वविद्यालय और खुलने जा रहे हैं- मुंगेर, पूर्णियां और पाटलीपुत्रा के नाम से इस बात का प्रमाण है कि सरकार भी चाहती है कि डिसेंट्रलाइज रूप से विश्वविद्यालय की व्यवस्था भी हो, कैंपस सुचारू रूप से चले, कॉलेज सुचारू रूप से चले। आज इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए सरकार ने निजी विश्वविद्यालय को भी अपनी स्वीकृति प्रदान करने का काम किया है । एमिटी विश्वविद्यालय, संदीप विश्वविद्यालय, सुजौली मधुबनी, के0के0 विश्वविद्यालय इस नाम से तीन की स्वीकृति प्रदान भी किया है ।

साथ ही साथ दो विश्वविद्यालय को और गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय की बात की है और अलकरीम विश्वविद्यालय कटिहार उसकी भी स्वीकृति प्रदान करने की योजना सरकार ने बनाया है । महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी । यह विश्वविद्यालय भवन निर्माण का कार्य पूरा कर चुका है जो विभिन्न प्रकार के अनेक आयाम को छूने का काम करती है । इसके उच्चतर शिक्षा के दृष्टि से भी इस विश्वविद्यालय परिसर में चार उत्कृष्ट संस्थानों की भी स्थापना की गयी है । यह संस्थान है- सेंटर फॉर जियोग्रेफिकल, सेंटर फॉर जर्नलिज्म ऐंड मास कम्युनिकेशन उसके दृष्टि से जो बिहार के छात्र पत्रकारिता जगत में विभिन्न आयामों पर है, लेकिन उनकी उपलब्धता यहीं पर हो, यहीं पर पढ़ाई की व्यवस्था हो । सोशल और जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन की व्यवस्था की है । पाटलीपुत्रा स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स और सेंटर फॉर रिवर स्टडीज । इस प्रकार के विषयों की भी स्थापना सरकार के माध्यम से की गयी है । जो अलग अलग विषय की आवश्यकता पड़ती है, जो बिहार के छात्र बाहर जाकर करते हैं इसकी आवश्यकता यहां पड़े । बिहार के छात्र यहां उस चीज को आवश्यकतापूर्वक ग्रहण करने का काम करे । चन्द्रगुप्त मौर्य के नाम से जो बड़ा मैनेजमेंट इन्स्टीच्यूट यहां प्रारंभ किया गया है कि चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान को आत्मनिर्भर बनाने हेतु सरकार ने 50 करोड़ रूपये का कॉर्पस फन्ड का भी गठन किया है । वर्तमान वित्तीय वर्ष में 31.1 करोड़ रूपया स्वीकृत करने की कार्रवाई अंतिम चरण में है । महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि आइ0आइ0एम0 जो सबसे बड़ी कल्पना इस दृष्टि से भी माननीय मुख्यमंत्री जी की कल्पना रही है- बोधगया में स्थापना हुई है । उसके लिए सरकार ने 119 करोड़ रूपया मगध विश्वविद्यालय के परिसर में नि:शुल्क उपलब्ध कराने का काम किया है । यह बड़ी उपलब्धि राज्य के दृष्टि से है । महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने गुणवत्ता शिक्षा के दृष्टि से इसके लिए राज्य के सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में नैक के मूल्यांकन के दृष्टि से करवाने का काम किया है । नैक के दृष्टि से संचालन के दृष्टि से उसके मोनेटरिंग के दृष्टि से उसका भी गठन सचिवालय में है और उसका परिणाम यह हुआ है कि लगभग 112 महाविद्यालय और 7 विश्वविद्यालय की नैक से मान्यता प्राप्त हो चुकी है । एग्रीगेटर की दृष्टि से, जो गुणवत्ता शिक्षा की दृष्टि से सरकार जो सोचती है उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि नैक के द्वारा एक्रीग्रिडेशन 112 महाविद्यालय और 7 विश्वविद्यालय का हो चुका है । मैं आपको बताना चाहूंगा कि शिक्षा के दृष्टि से जो बहालियां लंबे समय तक सरकार ने नहीं कर पायी थी वर्तमान सरकार वास्तव में 11 विषय में कुल 1354 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है । इतनी बड़ी नियुक्ति को देखते हुए सरकार ने बी0पी0एस0सी0 के माध्यम से कराने का काम किया है और बड़ी बहाली होगी उसके माध्यम से जो लंबे समय तक वेटिंग लिस्ट में था यू0पी0एस0सी0 का गठन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से जो युनिवर्सिटी पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से जो शिक्षकों की बहाली होनी है, उसका भी गठन के माध्यम से शिक्षकों की बहाली की

जायेगी ताकि जो अभाव पूरे विश्वविद्यालय के शिक्षकों के दृष्टि से है उसको पूरा किया जा सके । जैसा निजी विश्वविद्यालय के बारे में हमने बताया - मैं बताना चाहूंगा कि माननीय सदस्यों ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में बताया है । बिहार के मेधावी छात्र इन चीजों की कल्पना करते हैं । बिहार के मेधावी छात्र अपने परिस्थितियों में पढ़ नहीं पाते हैं तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत जो 4 लाख रूपया का लोन और आज ही पेपर के माध्यम से पढे होंगे कि सरकार ने जो निर्णय लिया है कि 30 वर्षों तक बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ जो बिहार से बाहर भी पढ़ रहे हैं उनके लिए भी जो योजना सरकार ने बनायी है उसके लिए सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद ।

टर्न-22/अशोक/ 09.03.2018

श्री संजीव कुमार चौरसीया : क्रमशः ... साथ ही साथ बिहार के बाहर जो पढ़ रहे हैं, उनके लिये भी जो योजना सरकार ने बनाई है उसके लिए सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद ।

महोदय, मैं बतलाना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अब तक कुल 16 हजार 82 विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण स्वीकृत की गई है, जो अपने आप में बड़ी उपलब्धि है । इसका बड़ा पैमाना छात्रों को मिलेगा, छात्र इस चीज को जानेगा, छात्र के आगे के शिक्षा के लिए, हर चीज के आगे बढ़ाने के लिए छात्र इस चीज को आगे बढ़ाने का काम करेगा । महोदय, मैं बतलाना चाहूंगा कि शिवहर में डिग्री महाविद्यालय स्थापित नहीं था, इस वित्तीय वर्ष में सरकार ने इसकी योजना बनाकर स्थापना की गई, और इसके लिए भी दो करोड़ की स्वीकृति की जा चुकी है । महोदय, इस विकास हेतु केन्द्र प्रायोजित, राष्ट्रीय उच्चतर अभियान योजना लागू की गई है । वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में, इस योजना के लिए 44.36 करोड़ स्वीकृत किये गये हैं, इस योजना के समुचित ढंग से राज्य में क्रियान्वयन करने हेतु राज्य के उच्चतर शिक्षा परिषद् का गठन अधिनियम के माध्यम से किया जाना आवश्यक है । इसके लिए विधान मंडल के वर्त्तमान सत्र में विधेयक सदन में प्रस्तुत किया जा रहा है और जो विषय सब के समक्ष आ रहा है कि पूरा विजलेंट होकर सरकार चाहती है कि प्रमाणिकता के साथ कैम्पसेस में पढ़ाई हो, उस पढ़ाई की दृष्टि से सरकार ने पूरी योजना बनाते हुये सी.सी.टी.वी. कैमरा की व्यवस्था सभी महाविद्यालय में शैक्षणिक सत्र में निश्चित रूप से हो और महाविद्यालयों में खासकर के स्वच्छता के दृष्टि को ध्यान में रखते हुये, शौचालय को दृष्टि को ध्यान रखते हुये, वाईफाई की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुये सरकार ने पूरी योजना बनाई है कि महाविद्याल, उच्चतर शिक्षा जबतक अपना बिहार का अच्छा नहीं होगा वास्तव में बिहार के छात्र जो बाहर जाकर अपने आयामों का परिणाम देने का काम करते हैं, यह बिहार के शिक्षा व्यवस्था के कारण ही

अलग-अलग प्रकार के जो आप आयाम देखते हैं कि बिहार के छात्र, बिहार के साथ-साथ पूरे देश के अन्तर्गत, कौन से ऐसे जिले नहीं हैं जहां ब्योरोक्रेट नहीं हों, पत्रकारिता के क्षेत्र में कहां बिहार के लोग नहीं हों, शिक्षा जगत में बढ़ते हुये परिणाम और सोच इस चीज को प्रदर्शित करता है कि वर्त्तमान परिप्रेक्ष्य में सरकार चाहती कि बिहार के शिक्षा का फैलाव जिस तरह से हो, इसलिये गुणवत्ता शिक्षा के लिए सरकार ने जो नैक के गठन के साथ-साथ पुनर्रचना का काम जो सरकार ने किया है कि अस्टैबलिशमेंट की दृष्टि से सरकार ने जो योजना बनाई है कि पूरे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलमपमेंट जब तक कैम्पसेस का नहीं करेंगे, कॉलेज कैम्पसेज का नहीं करेंगे गुणवतता शिक्षा का आधार नहीं हो सकता है । तो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलमपमेंट जो सरकार ने गठन किया है यह बहुत आयामी कदम सरकार के द्वारा उठाया गया है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलमपमेंट के बिना सरकार का शिक्षा जगत आगे नहीं बढ़ नहीं सकता है तो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलमपमेंट के लिए बहुआयामी कदम उठाने का काम किया है, यह बहुत योग्य कदम है, इसका परिणाम निश्चित तौर पर दिखलाई दे रहा है । मैं आपको बतलाना चाहूंगा मित्रों, जब निश्चित तौर पर पूरा विश्व में शिक्षा के क्षेत्र में अलख जगाने का काम नालन्दा विश्वविद्यालय किया है, एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी ने सोचा है और यथार्थ रूप में पूरे विश्व के मानव पटल पर नालंदा विश्वविद्यालय का स्वरूप दिखलाई दे रहा है। यह बड़ी उपलब्धि सरकार की है कि शिक्षा और बिहार को पूरे देश के अन्तर्गत क्या पूरे विश्व में जाना जाता है कि बिहारी शिक्षा से जुड़कर रहता हैं, हरएक बिहारी, हरएक बिहारी का परिवार यह चाहता है कि शिक्षा में सम्मलित करवा कर, शिक्षित करवाने का काम करे और उसी का परिणाम है कि वर्त्तमान सरकार यह चाहती है कि हरएक बिहारी को ठीक से शिक्षा मिले, यहां के छात्रों को शिक्षा मिले उसकी व्यवस्था बिहार की दृष्टि से करे तो आधारभूत संरचना ठीक हो, गुणवत्ता हो, बहाली हो, गुणवत्ता हो सब विषयों पर वर्त्तमान सरकार ने यह सोच कर आगे बढ़ाने का काम किया है । इस बात का प्रतीक है हरएक विषय पर डेवलपमेंट प्रोसेस में सरकार ने उच्च शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम किया है, उच्च शिक्षा का रिफलेक्शन जहां होता है प्रान्त का पूरा रिफलेक्शन दिखलाई पड़ता है । वर्त्तमान परिप्रेक्ष्य में, सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्रीजी ने हर विषय को जिस प्रकार उच्च शिक्षा का रिफलेक्शन देने का काम किया है मित्रों, माननीय सदस्य जी, माननीय महोदय, माननीय सभापति महोदय, इन सब बातों का प्रतीक है कि उसको आगे बढ़ाने का काम शिक्षा क्षेत्र में किया जा रहा है । आपने मुझे समय दिया सभापति महोदय, इसके लिये बहुत बहुत धन्यवाद ।

सभापति(श्री तारकिशोर प्रसाद): माननीय सदस्या सुश्री पूनम पासवान जी ।

सुश्री पूनम कुमारी उर्फ पूनम पासवान : माननीय सभापति महोदय, आज कटौती पक्ष में बोलने के लिए मैं खड़ी हुई हूँ। शिक्षा, खासकर शिक्षा, पूरे बिहार में शिक्षा का स्तर पंचायती स्तर से शिक्षकों की बहाली के कारण शिक्षा का स्तर नीचे गिरा है । इसका कारण जो बहाली शिक्षकों को की गई है, उनके सिर्फ सर्टिफिकेट देखकर बहाली करने के कारण आज यह कई विद्यालयों में ये समाने बात आ रही है कि शिक्षक नाम तक लिखना सही ढंग से नहीं जान पा रहे हैं । अगर यह बहाली सरकार के द्वारा परीक्षा के द्वारा या सरकारी विभागीय के द्वारा यह बहाली होती तो हम समझते कि बिहार में आज बिहार की रूपरेखा शिक्षा की स्तर में और आगे बढ़ती । लेकिन आज बिहार में यह चर्चा है कि चरवाहा विद्यालय की काफी चर्चा हुई, एक नारा था उस समय में जिस समय कि लड़कियां पढ़ने नहीं जाती थी, कि 'गाय, बकरी चरती जाय, मुनिया बेटी पढ़ती जाय ' और इस नारा के तहत लड़कियों में एक जागरूता पैदा हुई पूरे बिहार में और इस जागरूकता में लड़कियों और उनके माताओं ने बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरित हुआ और चरवाहा विद्यालय में कौन से शिक्षक थे ? जो कम्पटिशन से, जो कम्पटिशन से आये वैसे टीचर जाते थे और पढ़ाने का काम करते थे और गाय, बकरी आज भी ग्रामीणों में शिक्षा के बाद, आज भी ग्रामीणों में लड़कियां बकरी चराती हैं, ऐसी बात नहीं है क्योंकि उनका स्तर समाज में और घर में क्या है ? सभी लोग पूर्ण नहीं है, सभी लोग परिपूर्ण नहीं हैं, इसलिये हम यह न कहें कि लड़कियां हर स्तर से आगे है, चाहे शिक्षा के जगत में हो, चाहे नौकरी के जगत में हो, आज महिलाओं को आरक्षण मिला है शिक्षा के क्षेत्रों में और महिलायें आगे बढ़ी हैं, महिलायें सशक्त हुई हैं लेकिन शिक्षा जिस तरह से, आज खास कर, मेरा कोढ़ा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आज जो हाई स्कूलों को अपग्रेड किया गया, उत्क्रमित मध्य विद्यालय को हाई स्कूल बनाया गया, और सर्वशिक्षा अभियान के तहत कई विद्यालय बनाये गये हैं लेकिन आज उस स्कूल में शिक्षकों की कमी है, और शिक्षकों की कमी होने के कारण आज जो हमलोग गुण्वत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं वह गुणवत्ता शिक्षा कैसे पूरी होगी जब तक शिक्षकों की बहीली पूर्ण रूप से 25 से 30 बच्चों में एक शिक्षक की जरूरत होती हैं और आज एक-एक विद्यालय में 250-300 बच्चे हैं लेकिन किसी में एक शिक्षक, किसी में नगण्य, नहीं के बराबर । क्योंकि मेरे कोढ़ा के शिवलाल टोला के स्कूल में, हाई स्कूल तो चल रही है, 250 बच्चे हैं लेकिन प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक बच्चों शिक्षा को दे रहे हैं । आज कॉपी, जो बच्चें पास करते हैं, परीक्षा में बैठते हैं, उन सब बच्चों के लिए जो कॉपी जांच की व्यवस्था की गई है, आज इन्टर का, मैट्रिक की कॉपी जो जांच होती है किस तरह के शिक्षक जांच में जाते हैं ? मुझे पता है । सभापति महोदय, तो यह पता चलता

है कि जो उत्क्रमित मध्य विद्यालय के शिक्षक हैं, जो प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हैं वे कॉपी जांचने के लिए जाते हैं । आज शिक्षक की कमी है पूरे बिहार में, इसलिये माननीय हमारे मुख्यंत्री जी बैठे हुये हैं शिक्षा के स्तर को बिहार में शिक्षा दूरूस्त तभी होगी जब हम अच्छे शिक्षक की बहाली करेंगे और टी.ई.टी. का एगजाम आज देकर लोग बैठे हुये हैं ऐसे लेगों को बहाली कर इन विद्यालयों में लाया जाय ताकि शिक्षा का स्तर ऊपर बढ़े । आज शिक्षकों को हर काम में लगाया जाता है । क्रमशः

टर्न-23/ज्योति/09-03-2018

क्रमशः

सुश्री पूनम कुमारी उर्फ पूनम पासवान: आज शिक्षकों को हर काम में लगाया जाता है । चाहे वह जन गणना हो या बाढ़ पीड़ित लोगों की व्यवस्था हो, हर काम में शिक्षकों की जरुरत चाहे मानव श्रृंखला हो, हर काम में और प्राय: स्कूल में चार से पांच शिक्षक रहते हैं लेकिन अन्य काम में लगाने के कारण कभी कभी एक शिक्षक एक विद्यालय में रह जाते हैं, जिसके कारण पढ़ाई में बच्चे को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, आज स्कूलों की स्थिति जर्जर है, जिसे सुधारने की जरुरत है ।

सभापति (श्री तार किशोर प्रसाद): आप समाप्त करें ।

सुश्री पूनम कुमारी उर्फ पूनम पासवान: एक मेरे क्षेत्र का विषय है जिसे मैं सभापति महोदय बोलना चाहती हूं कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय बिंजीमरवा जिसमें कि पोशाक की राशि का, एक सौ बच्चे की कम से कम गबन करने का मामला सामने आया है। इसकी जॉच हुई है लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी है, इसलिए सदन के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि इसकी जॉच हो और एक आर्यभट्ट विश्वविद्यालय है, जो कि मेडिकल छात्र और छात्राएं भी इसमें सम्मिलित होते हैं । किसी भी विभागीय कारणवश अगर वे बच्चे फेल हो जाते हैं, तो कोई ऐसा इसमें सुधार करने की व्यवस्था नहीं है । आर.टी.ई. के द्वारा अगर वह मांगते हैं, अपनी कॉपी को, कॉपी मिलती है, उसमें अगर जोड़ते हैं, देखते हैं तो मार्क्स उनके पूरे हो जाते हैं लेकिन ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है कि उसको सुधार कर वैसे बच्चे को पास किया जाय । इसलिए हम सदन के माध्यम से सभापति महोदय मांग करते हैं कि इस व्यवस्था को सुधारा जाय जिससे कि बच्चे का जो साल बर्बाद होता है, वह बर्बाद न हो । कई ऐसे बच्चे हैं जिनका साल बर्बाद हो जाता है, वह नहीं हो और बी0पी0एस0सी0 मैं उनके बारे में कहना चाहती हूँ कि जो छात्र बैठते हैं, चाहे वह हिस्ट्री सब्जेक्ट हो या सोशल सायंस का हो या किसी भी सब्जेक्ट में तो जब उनके एग्जाम का रिजल्ट आता है, तो एक सब्जेक्ट से उठा कर बच्चे को पास किया जाता

है । यह तय करे सरकार कि हम किस सब्जेक्ट से बच्चे को पास करेंगे, क्योंकि हर सब्जेक्ट की प्राथमिकता होनी चाहिए । चाहे सोशल सायंश से आए, चाहे हिस्ट्री से आये या पॉलिटिकल सायंस से आए, सभी विषयों के बच्चे को पास करना चाहिए जो बच्चे अच्छे पढ़ने में है, मार्क्स ला रहे हैं, यह देखने की जरुरत है जिससे कि सभी बच्चे को न्याय मिल सके ।

सभापति (श्री तार किशोर प्रसाद) : अब समाप्त करिये ।

सुश्री पूनम कुमारी उर्फ पूनम पासवान: मैं इतना ही कह कर कम्पयूटर के शिक्षक हैं, जो लगातार दो सौ दिनों से धरणा पर बैठे हुए हैं और उनकी बहाली साढ़े नौ हजार में की गयी है लेकिन पॉच साल तक वे लोग जॉब किए लेकिन उन लोगों को सिर्फ आठ हजार रुपये मंथली सैलरी के रुप में मिला, पी.एफ. के रुप में पैसा रखा गया लेकिन उनको अभी तक पूरा भुगतान नहीं किया गया है । आज वे लोग सड़क पर हैं, चाहें तो आप देख ले । अन्य राज्य में यही कम्यूटर शिक्षक की, महोदय मैं एक मिनट में खत्म करती हूॅं । चाहे हरियाणा, राजस्थान, पंजाब हर जगह कम्पयूटर शिक्षक की नियुक्ति को रेगुलर किया गया है, इसलिए हम चाहते हैं कि बिहार में जो कम्पयूटर शिक्षक हैं, उनकी बहाली रेगुलर हो क्योंकि आज एक साल से विद्यालय में कम्पयूटर की शिक्षा नहीं हो रही है । आज कम्पयूटर ठप पड़े हुए हैं, उसको चालू कराया जाय। आज रजिस्ट्रेशन में काफी गड़बड़ी हुई हैं, अच्छे कम्पयूटर के अभाव में ।

सभापति (श्री तार किशोर प्रसाद): अब आप बैठ जांय ।

श्री नरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह: सभापति महोदय, आज तो शिक्षा विभाग की मांग के समर्थन में और हमारे गार्जियन रामदेव बाबू कटौती प्रस्ताव दिए हैं, तो उसके विरोध में खड़ा हूॅं । रामदेव बाबू मेरे गार्जियन भी हैं और सदा इनका प्यार मुझे मिलता रहा है । लेकिन द्ःख इस बात का है कि आज हमारे गार्जियन धरती की सच्चाई को अपनी जुबान पर लाने का कार्य नहीं किए । कौंग्रेस पार्टी की मैं निन्दा नहीं करता । कौंग्रेस पार्टी ने भी इस देश में बेहतर कार्य किया है लेकिन 1980 से 2005 का जो इतिहास रहा है हिंदुस्तान में, बिहार में वह बड़ा ही भयानक इतिहास रहा है रामदेव बाबू, बड़ा ही भयानक । हालात क्या थे ? माता-पिता अपने बच्चे को विद्यालय भेजना बंद कर दिए थे । विद्यालय में न भवन था, न टीचर थे, न बेंच था और न ब्लैक बोर्ड था ।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

समाज में गार्जियन चर्चा करते थे कि बच्चे को विद्यालय भेजने से क्या फायदा है, चूॅंकि विद्यालय गुल्ली डंडा का अड्डा बन गया था और इस संस्कार को आपने बिहार की धरती पर पैदा करने का कार्य किया । बिहार के बच्चे विद्यालय जाना बंद कर दिए । बिहार के बच्चे गोबर उठाते थे, गोईठा पाथते थे। अंडी तोड़ते थे, मकई काटते थे, गेहूॅं का बोझा बांधते थे । सम्पूर्ण बिहार की यही हालत थी और आज

बेगुसराय की बात करें, तो बेगुसराय के किसी गांव में चलिए, किसी पंचायत में चलिए उस पंचायत में यदि कोई जमींदार या पैसे वाला का दस मकान बेहतर होगा, तो उसमें एक बिहार सरकार का विद्यालय का भी नंबर होगा । वन टू टेन में विद्यालय का भी भवन आपको देखने को मिलेगा। मैं सरकार की बड़ाई नहीं करता लेकिन धरती की जो सच्चाई है, सच्चाई है और आप दिल से एक्सेप्ट करते हैं उस बिहार सरकार का जो 2005 से साढ़े बारह साल का कार्य काल रहा, वह बड़ा ही ऐतिहासिक कार्य काल रहा है और मैं अटल जी का भी सम्मान करता हूँ । अटल जी ने बापू के सपने को पहले हिंदुस्तान के गली कूची में लाने का कार्य किया । आज सर्व शिक्षा अभियान के बदौलत बिहार में शिक्षा का अलख जग रहा है और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री- अखबार में, हम उस दिन भी कहे थे कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री आज तक यह नहीं कहे, जो बिहार विकसित हो गया, विकासशील हो गया, उनका जब भी मैंने स्पीच सुना, पढ़ा, देखा उन्होंने स्पष्ट कहा कि बिहार में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है । आपका दिल कहता है जो आदरणीय नीतीश कुमार ने बिहार को दुनिया के नक्शे पर स्थापित करने का एक ऐतिहासिक कदम उठाया है, जिसको आपका दिल एक्सेप्ट करता है, तो सत्ता विपक्ष का खेल नहीं होना चाहिए । धरती की सच्चाई का खेल विधान सभा के फ्लोर पर भी होना चाहिए । सरकार ने जो अच्छे काम किए हैं, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए । सरकार में जो कमियाँ हैं, उन कमियों को हम सत्ता पक्ष के भी लोग शेयर करते हैं और आपको तो अधिकार है, विपक्ष सरकार की आंख है, आपका तो अधिकार बनता है, जो आप सरकार के ध्यान में जो कमियाँ हैं, उसको उजागर करने का कार्य करें ।

(व्यवधान)

भईया, आप को उकसा नहीं रहे हैं, बेहतर आपका भविष्य हो, इसके लिए हम सब आदमी आपस में शेयर कर रहे हैं, जो अपनी बात को फ्लोर पर जनता के हित में, छात्र के हित मे, किस रुप में रखना चाहिए ।

(व्यवधान)

चूँकि रामदेव बाबू हमारे गार्जियन हैं । संयोग से अवधेश बाबू भी मेरे गार्जियन हैं ।

(व्यवधान)

शकील बाबू से मेरा परिचय वैसा नहीं है ।

श्री अवधेश कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय,....

अध्यक्ष : अभी तक तो बिना आसन को शामिल किए आपलोग एक दूसरे को कह रहे थे ।

श्री अवधेश कुमाार सिंह : हम जब भी कहे अध्यक्ष जी की अनुमति से ।

अध्यक्ष : ठीक है, तब आप जरुर कहिये अध्यक्ष की अनुमति से ।

टर्न-24/09.3.2018/बिपिन

श्री अवधेश कुमार सिंह: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री सिंचाई और योजना मंत्री आज सुबह में अपने एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे जिसमें इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से कुछ कटौतियां की गई है । केंद्र सरकार से हमारे राज्य सरकार और खासकर, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री ने जो समझौता किया, उसमें यही था कि डबल इंजन होगा तो बिहार का विकास होगा । विपक्ष के लोग विशेष राज्य के दर्जा के लिए खासकर, कांग्रेस पार्टी, हम तैयार हैं आपके साथ चलने के लिए । आप विशेष राज्य की लड़ाई लड़ें और हम आपके साथ हैं ।

अध्यक्ष : अवधेश बाबू, इसका माने प्रश्नकाल में पूछे गए प्रश्न के संबंध में अभी आपका पूरक था!

श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह,मंत्री: अध्यक्ष महोदय, माननीय अवधेश बाबू ने सुना नहीं ठीक से, मैंने यह नहीं कहा था कि कटौती हुई है, मैंने कहा था कि जो हमारा हिस्सा है, उसमें से कम मिला है । अभी तो मार्च बाकी है, आप इंतजार करिए न ! आप किसलिए परेशान हैं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अभी शिक्षा विभाग की मांग पर विमर्श चल रहा है । बाकी आपलोग जो करना चाहते हैं, उसके लिए समय और स्थान अलग है ।

श्री नरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह: अध्यक्ष महोदय, बिहार सरकार का बजट हर साल शिक्षा पर बढ़ता चला जा रहा है और बेहतर होता चला जा रहा है । हम बिहार सरकार के ध्यान में दो-तीन बातों की चर्चा करना चाहेंगे । बिहार में जितने हमारे पास बच्चे हैं, बच्चों के अनुपात में हम शिक्षक देने में अभी तक सक्षम हो नहीं पाए हैं और जो शिक्षक दिए हैं, किसी विद्यालय में 10 शिक्षक हैं, किसी विद्यालय में 5 शिक्षक हैं, किसी विद्यालय में 15 शिक्षक हैं, छात्रों की जो संख्या है और जो शिक्षकों की संख्या है, उसको जिलास्तर पर मोनिटरिंग करके सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता है जिससे ऑल विद्यालय के ऑल बच्चे को सही रूप से शिक्षा मिल सके । यह मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं और साथ ही, विद्यालय में हमारे, चूंकि पीछे नहीं बोलना चाहिए, हमारे राजद के साथी नहीं हैं । उनके नेता के द्वारा कहा गया कि जो चोरी बिहार सरकार रोक रही है, चोरी नहीं रूकना चहिए, तो चूंकि संस्कार उनको ऐसा मिला है जो अपने बच्चे को चोरी करने के प्रति भाग-दौड़ करने में लगे हुए हैं और बिहार सरकार का ऐतिहासिक फैसला हुआ जो कदाचारमुक्त परीक्षा हो ताकि जो हमारा बच्चा पास करे, वह हिन्दुस्तान के किसी कोने में अपनी पहचान, अपनी व्यक्तित्व का परिचय देने का कार्य करे । इसके लिए हम बिहार सरकार को शाबासी देते हैं, धन्यवाद देते हैं जो इस बार कदाचारमुक्त परीक्षा हुई और बिहार के बच्चे ईमानदारी से अपने

पेशेंस का परिचय देने का कार्य किए । साथ ही, हमारे बच्चों के माता-पिता ने भी इस बात को समझने का प्रयास किया कि बिहार सरकार का जो निर्णय आया है, वह हमारे बच्चे के हित में निर्णय है । इसलिए हमारे बच्चों के माता-पिता ने भी बिहार सरकार के निर्णय का स्वागत किया है । इन्हीं शब्दों के साथ जय हिन्द, जय भारत, जय बिहार सरकार ।

अध्यक्ष : श्री रामप्रीत पासवान जी । दो मिनट में अपनी बात कहिए ।

श्री श्याम रजक : एक मिनट अध्यक्ष महोदय । अध्यक्ष महोदय, शिक्षा का बजट बहुत अच्छा आया है और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में शिक्षा का जो गति है, वह तीव्र चल रही है, सिर्फ एक आग्रह है माननीय मंत्री जी से कि जो प्राइमरी स्कूल है और माध्यमिक स्कूल है उन बच्चों के लिए बेंच और टेबुल की व्यवस्था के लिए अलग से राशि व्यवस्था करायी जाए ।

अध्यक्ष : ठीक है । रामप्रीत जी ।

श्री रामप्रीत पासवान : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा विभाग के बजट पर विपक्ष की कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । समय मात्र दो मिनट मिला है । मैं अपना सुझाव देकर ही बैठ जाना चाहता हूं ।

महोदय, मुझे 26 साल शिक्षक की नौकरी करने का अनुभव है । हमारे प्रधान सचिव भी यहां बैठे हुए हैं । मैं अपने मंत्री जी से भी आग्रह करता हूं, यदा-कदा उन्हें सलाह देने का भी काम करता हूं । शिक्षा विभाग में जो आपने बी.आर.सी. और सी.आर.सी. बनाया, उसमें से शिक्षक को आप निकाल दें । अलग से उसमें व्यक्ति को बहाल करें । शिक्षक को इसमें से निकालें । यहां राजनीति होती है । हम विधायक उच्च विद्यालय के प्रबंध समिति के अध्यक्ष होते हैं । उसको थोड़ा आप टाइट करें । बैठक प्रधानाध्यापक नहीं बुलाते हैं जिसके चलते विद्यालय में अराजकता की स्थिति है और साईकिल योजना, पोषाक योजना, यह जितने भी योजना मिलते हैं और बैंक द्वारा मिलते हैं, उसपर प्रधानाध्यापक को टाइट किया जाए । मैं एक दिन आपसे मिला भी था जो इस योजना में प्रधानाध्यापक लोग बच्चों के खाता में पैसा नहीं देते हैं और पैसा घूमकर फिर सरकार के पास आ जाता है, तो इस तरह की व्यवस्था हो कि समय पर प्रधानाध्यापक उसमें पैसा, साइकिल या पोषाक योजना का पैसा हमारे मुख्यमंत्रीजी खासकर, गरीब के बच्चों को पढ़ने के लिए बहुत सारी योजना चलाए । जहां कस्तूरबा विद्यालय है 5 से लेकर 9 तक वहां पढ़ाई होती है । वह विद्यालय अब शिक्षा की गुणवत्ता के लिए निश्चित रूप से अब हमलोग को लगना चाहिए । शिक्षा की गुणवत्ता रहेगी तो प्राइवेट स्कूल अपने आप समाप्त हो जाएगा । हमारे यहां शिक्षक की कमी नहीं है, केवल सामंजन की कमी है । आपने प्लस-टू विद्यालय खोला है, उसमें अभी तक शिक्षक की बहाली नहीं हुई है । मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि यथाशीघ्र उसमें

शिक्षक की बहाली हो और निश्चित रूप से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, इसीलिए इन्हीं शब्दों के साथ, मैं तैयारी करके भी आया था, लेकिन समय नहीं मिला, विस्तार से बताता लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अब गरीब-से-गरीब बच्चे जो सुदूर गांव में पहले विद्यालय में बच्चे जाते थे, अब वह विद्यालय बच्चों के बीच में है । इसलिए अब मात्र एक लाख बच्चे रह गए हैं जो विद्यालय में नामांकित नहीं हैं । हमलोग भी चाहते है कि विद्यालय में बच्चे नामांकित हों और उसे अच्छी-से-अच्छी शिक्षा मिले, उसे दूसरे जगह नहीं जाना पड़े । इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आपको बधाई देते हुए आपने जो मुझे दो मिनट का समय दिया, अपनी वाणी को विराम देता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सरकार का उत्तर होगा । माननीय प्रभारी मंत्री, शिक्षा विभाग ।

सरकार का उत्तर

श्री श्रवण कुमार, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, आज आपकी अनुमति से मैं सदन के समक्ष राज्य में शिक्षा से संबंधित मुद्दों एवं शिक्षा पर होने वाले वास्तविक व्यय के बारे में मांग संख्या-21 पर अपना वक्तव्य दे रहा हूं ।

महोदय, आज सत्ता पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों ने जो शिक्षा विभाग के मांग पर अपना विचार व्यक्ति किए हैं महोदय, माननीय सदस्य श्री रामदेव राय जी, माननीय सदस्य श्री नेमतुल्लाह जी, माननीय सदस्य श्री डा0 जीतेन्द्र कुमार जी, माननीय सदस्य श्री व्यासदेव प्रसाद जी, माननीय सदस्य श्री लक्ष्मेश्वर राय जी, माननीय सदस्य श्रीमती आशा सिन्हा जी, माननीय सदस्य डा0 जावेद साहब, माननीय सदस्य श्री सुदामा प्रसाद जी, माननीय सदस्य श्री निरंजन कुमार मेहता जी, माननीय सदस्य श्री संजीव चौरसिया जी, माननीय सदस्य सुश्री पूनम पासवान जी, माननीय सदस्य श्री नरेन्द्र प्रसाद सिंह जी । ये माननीय सदस्यों ने अपने बहुमूल्य सुझाव दिए हैं महोदय ।

महोदय, अभी कांग्रेस के डा0 जावेद साहब कुछ प्रश्न उठा रहे थे लेकिन उनको बताना चाहता हूं महोदय कि जबसे हमारी सरकार बनी है, माननीय नीतीश कुमारजी की जो सरकार है महोदय, 2006 के पहले सिर्फ उनके संज्ञान में यह बात डालना चाहता हूं कि 2006 के पहले मात्र उनके यहां हाई स्कूल की संख्या 25 थी, महोदय, किसनगंज जिले में और माननीय मुख्यमंत्रीजी के निर्देशन में जो काम हो रहा है शिक्षा के क्षेत्र में महोदय.... क्रमशः

टर्न 25/कृष्ण/09.03.2018

श्री श्रवण कुमार,मंत्री (क्रमशः) कुल हाई स्कूलों की संख्या 88 हो गयी यानी 63 हाई स्कूल नये बनाये गये । महोदय, 10 प्लस टू एक भी नहीं था और 10 प्लस टू की संख्या

बढ़कर 25 हो गयी यानी महोदय, कुल 88 आज वहां माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार ने ये काम किया है । अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की शाखा भी खोली गयी और पढ़ाई कहां हो रहा है, माननीय सदस्य को यह बताना चाहिए था कि पढ़ाई भी इन्हीं के क्षेत्र में हो रही है, किशनगंज जिले में ही हो रही है ।

महोदय, हमारे भारत के गौरव डा0 कलाम साहब के नाम पर कृषि महाविद्यालय की स्थापना कहां हुई महोदय, उनको भी यह बताना चाहिए । लेकिन बताते नहीं है, इन्हीं के क्षेत्र में हुआ है । माननीय सदस्य को ये सब बातें कहनी चाहिए जो काम यहां पर हुये हैं । तो मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि इनका शासन ज्यादा दिनों तक राज्य में भी रहा और देश में भी रहा । हुआ क्या ? जब इनका शासन था तब शिक्षा पर इनका ध्यान ही नहीं था और जब शासन बदल गया तो हमारी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है, इसको समझने की जरूरत है ।

महोदय, प्राचीनकाल से बिहार शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहा है । इसके प्राचीन महत्व को प्राप्त करने के लिये सरकार सतत् प्रयत्नशील है । प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक के लिये पर्याप्त भौतिक संरचना छात्र उपस्थिति के अनुपात में शिक्षकों की व्यवस्था बच्चों का शत-प्रतिशत नामांकन एवं शिक्षा में गुणवत्ता की संवृद्धि हेतु गंभीर प्रयास किये गये हैं एवं इसमें उल्लेखनीय सफलता मिली है । महोदय, पूरी दुनियां में जब ज्ञान प्राप्ति के लिये उच्च कोटि का विश्वविद्यालय नहीं था, उस समय नालन्दा विश्वविद्यालय था और पूरी दुनियां में ज्ञान की रोशनी नालन्दा विश्वविद्यालय से लोगों को मिली । महोदय, आज माननीय नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनके अथक प्रयास से नालन्दा विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी, जहां बच्चों की पढ़ाई आरंभ है एवं दो बैच के बच्चे पास कर देश और विदेश में बच्चे जाकर नाम रौशन कर रहे हैं । यह जानकर प्रसन्नता होगी कि वहां से पढ़ाई कर निकले बच्चे राज्य और राज्य से बाहर हैं । वे चाहते हैं कि बिहार में काम करे, ऐसा वातावरण बिहार में बना है । अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नालन्दा, बिहार और भारत का नाम शिक्षा के क्षेत्र में रौशन हो रहा है और खोई हुई प्रतिष्ठा वापस आ रही है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय, चम्पारण सत्याग्रह शदाब्दि समारोह के अंतर्गत राष्ट्रीय विमर्श स्वतंत्रता सेनानी सम्मान समारोह एवं बापू आपके द्वार कार्यक्रम चलाया गया, डेढ़ करोड़ घरों तक हमने बापू के संदेश को फोल्डर के रूप में पहुंचाया है । बच्चे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कहानियों से प्रेरणा लें, इसके लिये गांधी कथा वाचन जैसे कार्यक्रम किये गये, हमने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को घर-घर एवं जन-जन तक पहुंचाने का काम किया है ।

अध्यक्ष महोदय, भारत के प्रथम राष्ट्रपति स्व0 डा0 राजेन्द्र प्रसाद की जन्म तिथि 3 दिसंबर, 2017 को मेघा दिवस के रूप में मनाया गया । इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के घोषणा के उपरांत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा वार्षिक, माध्यमिक, इन्टरमीडिएट परीक्षा के टॉपर्स को देशरत्न डा0 राजेन्द्र प्रसाद मेघा छात्रवृत्ति, 2017 से प्रत्येक वर्ष दिये जाने का निर्णय लिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय, बाल विवाह एवं दहेज उन्मूलन जैसे सामाजिक कुरीतियों को हटाने के लिये 21 जनवरी, 2018 को राज्य सरकार ने राज्यव्यापी मानव श्रृखंला का कार्यक्रम रखा । बिहार की जनता-महिलायें, युवा, बच्चे, शिक्षक, व्यवसायी, बुद्धिजीवी, किसान, मजदूर सभी वर्गों के लोग, राजनीतिक दलों के नेता, कार्यकर्त्ता सम्पूर्ण बिहारवासी ने मिलकर ऐतिहासिक मिसाल राज्यव्यापी 14 हजार 60 किलोमीटर की मानव श्रृंखला निर्माण किया गया, जिसमें करोड़ों लोगों की भागीदारी हुई, बिहार में 21 जनवरी, 2017 को अपने विश्व रेकर्ड को खुद तोड़कर एक नया रेकर्ड कायम किया है ।

अध्यक्ष महोदय, बिहार में अब विद्यालय से बाहर बच्चों की संख्या काफी कम हो गयी है । समाज में हर वर्ग के बीच शिक्षा के लिये जागरूकता आयी है । शिक्षा वह साधन है, जिसके सहारे समाज का कोई व्यक्ति अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। पढ़ने के लिये, लिखने के लिये और जीवन में आगे बढ़ने के लिये लोगों के बीच सोच पैदा करने में हमारी सरकार कामयाब रही है । अब केवल वही बच्चे ही विद्यालय से बाहर हैं, जिनके माता-पिता, अभिभावक को इसमें रूचि नहीं है । हम लगातार शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं । बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिये मध्याह्न भोजन योजना, छात्रवृत्ति योजना, मेघावृत्ति योजना के साथ-साथ उन्हें स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की मुहिम से जोड़ा जा रहा है ।

महोदय, आप अवगत है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित 10वीं की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण सामान्य एवं पिछड़े वर्ग के प्रत्येक छात्र-छात्राओं को 10 हजार रूपया एवं द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण अनुसूचित जाति के श्रेणी के प्रत्येक छात्रों को 8 हजार रूपया मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना एवं मुख्यमंत्री बालक प्रोत्साहन योजना के तहत उपलब्ध करायी जाती है । इंटर से ऊपर की पढ़ाई की शिक्षा एकमात्र 14.04 परसेंट है, उससे ऊपर उठाने के लिये 30 प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से भी आगे पहुंचाने की दिशा में हमने काम प्रारंभ किया है ।

महोदय, बैंकों के नकारात्मक रवैया को देखकर सरकार ने फैसला किया कि बिहार राज्य वित्त शिक्षा निगम बनाकर बच्चों को उच्च शिक्षा में जो बाधा है, उसे समाप्त किया जाय ।

अध्यक्ष महोदय, पूरे देश में बिहार पहला राज्य है जिसमें वर्ग-1 से 8 तक के बच्चों के लिये आंतरिक मूल्यांकन प्रणाली लागू की गयी है एवं विद्यालय स्तर पर

बच्चों के सीखने क्षमता के लिये आंतरिक जांच आरंभ किया गया है । इसकी सराहना भी की जा रही है । वर्ष 2018 में भारत सरकार ने एन0सी0ई0आर0टी0 के द्वारा पूरे देश में नेशनल असेसमेंट सर्वे किया तो तुलनात्मक रूप से बिहार के बच्चों ने बेहतर प्रदर्शन किया यद्यपि अभी हमें बहुत आगे काम करना है ताकि हमारे विद्यालय में नामांकित एवं पढ़नेवाले बच्चे कक्षा के अनुरूप गुणवत्ता प्राप्त कर सके ।

महोदय, मध्याह्न भोजन योजना में गुणवत्ता एवं अधिकाधिक आच्छादन का लक्ष्य हम प्राप्त कर चुके हैं । सप्ताह में 3 दिन अतिरिक्त पोषक तत्व देने की व्यवस्था की गयी है । बिहार सरकार ने अपनी निधि से 300 करोड़ रूपये देकर सप्ताह में एक दिन मध्याह्न भोजन योजना में अण्डा को सम्मिलित किया गया है । इसके अतिरिक्त सप्ताह में दो दिन केला अथवा मौसमी फल भी बच्चों को दिया जा रहा है ।

(व्यवधान)

मौसमी फल मिल रहा है, अण्डा मिल रहा है बच्चों को तो घबरा गये ? खाने दीजिये, गरीब का बच्चा है, खायेगा तो बढ़िया से पढ़ेगा ।

अध्यक्ष महोदय, बाल भवन किलकारी के माध्यम से हमने झुग्गी-झोपड़ी के उपेक्षित बच्चों के साथ उनकी प्रतिभा को विकसित करने का कार्य किया है । सदन को बताते हुये खुशी हो रही है कि बालक वर्ग में पटना जिला के बाढ़ अनुमंडल के ग्राम बिजली, मलाही के अनुसूचित जाति के रवि रंजन कुमार ने श्रीलंका के साथ बैडमिंटन मैच में अद्भूत प्रदर्शन किया और श्रीलंका को 3-0 से पराजित किया । ऋतिक रौशन के साथ 13 बच्चे का चयन एक फिल्म के लिये किया गया, जहां पर बच्चों के लेखन, गायन, नित्य पेंटिंग, खेल-कूद सभी क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर पर सफलता प्राप्त की है ।

महोदय, आज बिहार राज्य के सभी स्थानों पर एक किलोमीटर के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय, 3 किलोमीटर के अंतर्गत मध्य विद्यालय एवं 5 किलोमीटर के अन्तर्गत माध्यमिक विद्यालय की सुविधा देने में हमारी सरकार सफल हुई है । हमने हर पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय की शिक्षा देने का लक्ष्य रखा है, जिसमें हम क्रमशः लक्ष्य प्राप्त करते हुये पंचायतों को आच्छादित कर चुके हैं ।

महोदय, माध्यमिक शिक्षा के विस्तार हेतु उच्च माध्यमिक विद्यालयविहीन पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की गयी है । 8 हजार 391 पंचायतों में से 5 हजार 59 पंचायतों में माध्यमिक विद्यालय एवं 2 हजार 200 पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालयों की सुविधा दी जा चुकी है । आच्छादित पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना के क्रम में खुले में शौचमुक्त पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की प्राथमिकता दिये जाने का निर्णय लिया गया है ।

क्रमश :

टर्न-26/सत्येन्द्र/9-3-18

श्री श्रवण कुमार,मंत्री(क्रमश:) साथ ही उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना के क्रम में भूमि की न्यूनतम उपलब्धता के मापदंड को 1 एकड़ से घटाकर 0.75 एकड़ निर्धारित किया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा विगत कई वर्षों से कदाचार मुक्त परीक्षा आयोजित की जा रही है एवं समिति की कार्यप्रणाली में व्यापक बदलाव किया गया है । वर्ष 2018 की माध्यमिक की परीक्षा में 8,91,243 छात्र एवं 8,78,794 छात्राएं सम्मिलित हुई है । इंटर की परीक्षा में इस वर्ष 7,19,847 छात्र तथा 4,88,130 छात्राएं सम्मिलित हुईं । शैक्षणिक सत्र 2015-17 से राज्य के 11 जिलों यथा गया, पटना, वैशाली, बेतिया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सुपौल, पूर्णियां, कटिहार, जमुई एवं मुंगेर में अवस्थित एक-एक राजकीय उच्च विद्यालयों में आई0एस0सी0 (कृषि) का पठन पाठन प्रारंभ है, शेष 27 जिलों में अवस्थित एक-एक सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आई0एस0सी0 (कृषि)का अध्यापन कार्य शैक्षणिक सत्र 2018-20 से प्रारम्भ किये जाने का निर्णय लिया गया है ।

(व्यवधान)

(इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यगण सदन से बाहर चले गये)

अध्यक्ष महोदय, अभी कांग्रेस के दो माननीय सदस्यों ने अपनी बात रखी है उनका जवाब हमने दिया है तो और क्या जवाब चाहते है ? आप भाषण करते आपको भी पार्टी समय देता तो आपका भी जवाब देते । महोदय, माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में भवन निर्माण, छात्रावास निर्माण, उनके लिए उपस्कर की व्यवस्था जैसे कार्य हम लगातार कर रह हैं । माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रयोगशालाओं को हम संचालित करा रहे हैं और इसके लिए प्रयोगशाला उपकरण एवं सामग्री की व्यवस्था करने जा रहे हैं । 6 हजार विद्यालयों एवं उच्च विद्यालयों के प्रयोगशाला के लिए 220 करोड़ रू0 की राशि एवं 2400 माध्यमिक विद्यालयों में उपस्कर के लिए 120 करोड़ रू0 की राशि निर्गत की जा रही है । 81 मॉडल स्कूल के लिए 186.67 करोड़ रू0 की राशि तथा 1,183 माध्यमिक विद्यालयों के लिए 12657.71 लाख रू0 की राशि स्वीकृत की गयी है। बालिका छात्रावास के लिए 22722.11 लाख रू0 की राशि स्वीकृत की गयी है । मैट्रिक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त बच्चों के लिए प्रोत्साहन राशि, नियमित छात्रवृत्ति, पोशाक साईकिल के लिए राशि बच्चों को सीधे उनके बैंक खाते में भेजा गया है । फलत: सभी बच्चों के नाम से खाता खोलना, आधार कार्ड बनाना और खाते में राशि को प्राप्त कराना जैसे मुहिम के कारण बच्चों के बीच प्रोत्साहन और पढ़ने की प्रेरणा बढ़ी है । डायरेक्ट बेनिफीट ट्रांसफर के कारण राशि के लिंकेज की संभावना शून्य हो गयी है । बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को सफल बनाने एवं विद्यार्थियों को

ससमय ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार द्वारा बैंकों के स्थान पर बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम की स्थापना की गयी है । इस माध्यम से हम उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों को सरलतापूर्वक अल्प समय में शिक्षा ऋण देंगे एवं बैंक के प्रक्रिया की जटिलता से मुक्ति मिलेगी । बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 में संशोधन करते हुए 3 नये विश्वविद्यालय पूर्णियां विश्वविद्यालय, पाटलीपुत्र विश्वविद्यालय एवं मुंगेर विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है जिसका संचालन शुरू किया जा रहा है। राज्य में चार निजी विश्वविद्यालयों क्रमशः अमिटी विश्वविद्यालय, पटना, संदीप विश्वविद्यालय, सिजौल, मधुबनी, के0 के0 विश्वविद्यालय, बिहारशरीफ तथा डॉ0 सी0बी0रमण विश्वविद्यालय, वैशाली की स्थापना हेतु अधिसूचना निर्गत हो चुका है तथा अल–करीम विश्वविद्यालय, कटिहार, सी0बी0 रमण विश्वविद्यालय, वैशाली तथा गोपाल नारायण विश्वविद्यालय, सासाराम की स्थापना शीघ्र होने जा रही है । आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के अन्तर्गत चार उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्थानों सेंटर फॉर जियोग्राफिकल स्टडीज, स्कूल ऑफ जरनलिज्म एंड मास कॉम्युनिकेशन, पाटलीपुत्र स्कूल ऑफ इकोनोमिक्स, सेंटर फॉर रिवर स्टडीज की स्थापना की गयी है । हमारा उद्देश्य सबके लिए गुणात्मक शिक्षा एवं जीवनपर्यन्त सीखने का अवसर देना है । इसे हम प्राप्त करेंगे और बिहार का हर बच्चा श्रेष्ठ मानव के रूप में प्रतिष्ठित होगा । गुणात्मक शिक्षा के लिए माता–पिता, परिवार, शिक्षक, विद्यालय समाज एवं सरकार प्रयत्नशील है । बिहार जैसे प्रदेश के लिए मानव संसाधन सबसे बड़ी समस्या है । यहां के लोग परिश्रमी होते हैं । शिक्षा एवं कौशल सम्पन्न बनाने से ये अपने और समाज के लिए अधिक उपयोगी सिद्ध होंगे । इस दिशा में बिहार सरकार लगातार शिक्षा विभाग के द्वारा प्रयत्न कर रही है । शिक्षकों को वेतन भुगतान के लिए विश्वविद्यालयों को अपेक्षित राशि निर्गत की गयी है और ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि समय पर भुगतान में कठिनाई नहीं हो । वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य योजना मद के लिए प्रस्तावित राशि 19107.03 करोड़ में से मुख्य योजनाओं में निम्न प्रकार से राशि व्यय किये जाने का प्रस्ताव है । सर्वशिक्षा अभियान योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत बजट के विरूद्ध पिछले कई वर्षों से काफी कम राशि दी जा रही थी जिसके कारण शिक्षकों को वेतन देने में कठिनाई होती थी इसलिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2018–19 में शिक्षकों के वेतन हेतु राज्य योजना मद से 5 हजार करोड़ रू0 की व्यवस्था की गयी है । छात्र/छात्राओं को पोशाक देने हेतु 625 करोड़ रू0, साईकिल के लिए 360 करोड़ रू0, छात्रवृत्ति प्रोत्साहन के लिए 287 करोड़ रू0 एवं अन्य योजनाओं के लिए राशि की व्यवस्था की गयी है । विद्यालय/महाविद्यालयों में आधारभूत संरचना के विकास हेतु लगभग 250 करोड़ रू0 की व्यवस्था की गयी है । मध्याह्न भोजन योजना के लिए केन्द्रांश 1302.88 करोड़ एवं राज्यांश 868.58 करोड़ रू0 की व्यवस्था की गयी है । सर्व शिक्षा अभियान के लिए

केन्द्रांश 6600 करोड़ रू0 एवं राज्यांश 2384.10 करोड़ रू0 की व्यवस्था की गयी है । राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के लिए केन्द्रांश 250 करोड़ रू0 एवं राज्यांश 166.67 करोड़ रू0 की व्यवस्था की गयी है । राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के लिए केन्द्रांश 60 करोड़ रू0 एवं राज्यांश 25.16 करोड़ रू0 की व्यवस्था की गयी है । शिक्षा विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 के व्यय वहन हेतु कुल रू0 321,25,63,75,000/- का उपबंध मांग संख्या-21 के अन्तर्गत प्रस्तावित है । इसमें गैर योजना व्यय के अलावे राज्य योजना एवं केन्द्र प्रायोजित योजना शामिल है । इसमें गैर योजना व्यय के लिए रू0 130,18,61,01,000/- प्रस्तावित है । राज्य योजना के लिए कुल रू0 191,07,02,74,000/-का प्रस्ताव है, जिसमें से केन्द्र प्रायोजित योजना अन्तर्गत केन्द्रांश की राशि रू0 82,14,02,74000/- राज्यांश की राशि रू0 34,45,00,00,000/-राज्य स्कीम के लिए रू0 7,00,00,00,000/-एवं वाह्य सम्पोषित परियोजना हेतु रू0 3,00,00,00,000/-का बजट प्रस्तावित है । अंत में, मैं आप सबों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि आपने हमारे वक्तव्य को ध्यानपूर्वक सुना । हम चाहते हैं कि शिक्षा के सवाल पर, बच्चों के भविष्य के सवाल पर सभी हमारे सम्मानित जन प्रतिनिधि हमारा सहयोग करे । हम सब मिलकर उत्तम शिक्षा के सपने को बिहार में साकार करें एवं अनुरोध करता हूँ कि बिहार एवं शिक्षा के विकास हेतु 321,25,63,75,000/-रू0 (तीन सौ एक्कीस अरब पचीस करोड़ तिरेसठ लाख पचहत्तर हजार) की मांग पर सदन अपनी स्वीकृति प्रदान करे, यही मैं अनुरोध करना चाहता हूँ और इसमें जो बातें रह गयी है उसको प्रोसिडिंग का पार्ट बना दिया जाय । (परिशिष्ट)

महोदय, तो ये विपक्ष के लोग तो चले गये हैं इनको सुनने का आदत है नहीं, ये सिर्फ अपनी बात कहना चाहते हैं इसलिए कटौती प्रस्ताव लाते हैं और भाग जाते है महोदय तो किनसे अनुरोध करें फिर भी अनुरोध करते हैं कि वे अपना कटौती प्रस्ताव वापस ले लें ।

(परिशिष्ट- द्रष्टव्य)

टर्न-27/मधुप/09.03.2018

अध्यक्ष : सरकार का उत्तर समाप्त हुआ ।

क्या माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

(माननीय सदस्य श्री रामदेव राय अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''इस शीर्षक की माँग 10 रूपये से घटाई जाय ।''

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूँ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''शिक्षा विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्त्ति के लिए 321,25,63,75,000/- (तीन सौ एक्कीस अरब पचीस करोड़ तिरेसठ लाख पचहत्तर हजार) रूपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

माँग स्वीकृत हुई ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 09 मार्च, 2018 के लिये स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या 22 (बाईस) है । अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक सोमवार, दिनांक-12 मार्च, 2018 को 11:00 बजे पूर्वाह्न तक के लिये स्थगित की जाती है ।

परिशिष्ट

प्रभारी मंत्री,

शिक्षा विभाग

का

मांग संख्या – 21 पर

<u>वक्तव्य</u>

2018 – 2019

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आज आपकी अनुमति से मैं सदन के समक्ष राज्य में शिक्षा से संबंधित मुद्दों एवं शिक्षा पर होने वाले प्रस्तावित व्यय के बारे में माँग संख्या–21 पर अपना वक्तव्य दे रहा हूँ।

1. प्राचीन काल से ही बिहार शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। इसके प्राचीन महत्व को प्राप्त करने के लिए बिहार सरकार सतत् प्रयत्नशील है। प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक के लिए पर्याप्त भौतिक संरचना, छात्र उपस्थिति के अनुपात में शिक्षकों की व्यवस्था, बच्चों का शत प्रतिशत नामांकन एवं शिक्षा में गुणवत्ता की सम्प्राप्ति हेतु गम्भीर प्रयास किये गए हैं एवं इसमें उल्लेखनीय सफलता भी मिली है।

   पूरे दुनिया में जब ज्ञान प्राप्ति के लिए विश्वविद्यालय नहीं था उस समय नालन्दा विश्वविद्यालय था और पुरे दुनिया में ज्ञान की रौशनी नालन्दा विश्वविद्यालय से लोगों को मिली। आज माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिनके अथक प्रयास से अन्तर्राष्ट्रीय नालन्दा विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी जहाँ बच्चों की पढ़ाई आरम्भ है एवं दो बैच के बच्चें पास कर देश एवं विदेश में जाकर नाम रौशन कर रहे हैं।

यह जानकर प्रसन्नता होगी कि वहाँ से पढ़ाई कर के निकले बच्चे जो राज्य और राज्य के बाहर के हैं, वे भी चाहते है कि बिहार में काम करें, ऐसा वातावरण बिहार का बन गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर नालन्दा का नाम, बिहार का नाम, एवं भारत का नाम शिक्षा के क्षेत्र में रौशन हो रहे हैं तथा खोई हुई प्रतिष्ठा वापस आ रही है।

2. **अध्यक्ष महोदय,** चम्पारण सत्याग्रह शताब्दी समारोह के अंतर्गत राष्ट्रीय विमर्श, स्वतंत्रता सेनानी सम्मान समारोह एवं बापू आपके द्वार कार्यक्रम चलाया गया । डेढ़ करोड़ घरों तक हमने बापू के संदेश को फोल्डर के रूप में पहुँचाया है। बच्चे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन की कहानियों से प्रेरणा लें, इसके लिए गाँधी कथा वाचन जैसे कार्यक्रम किए गए। हमने राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी जी के संदेश को घर–घर एवं जन–जन तक पहुँचाने का काम किया है।

3. भारत के प्रथम राष्ट्रपति देशरत्न स्व0 डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद जी के जन्म तिथि 03 दिसंबर, 2017 को 'मेधा दिवस' के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के घोषणा के उपरान्त बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा वार्षिक माध्यमिक/इंटरमीडिएट परीक्षा के टॉपर्स को देशरत्न डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद मेधा छात्रवृत्ति वर्ष 2017 से प्रत्येक वर्ष दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

4. बाल विवाह एवं दहेज उन्मूलन 21 जनवरी, 2018 को राज्य सरकार ने राज्य व्यापी मानव श्रृंखला का कार्यक्रम रखा। बिहार की जनता, महिलाएँ, युवा, बच्चे, शिक्षक, व्यवसायी, बुद्धिजीवी, किसान, मजदूर, सभी वर्गों के लोग, राजनीतिक दलों के नेता, कार्यकर्त्ता, सम्पूर्ण बिहारवासियों ने मिलकर ऐतिहासिक विशाल राज्यव्यापी 14,060(चौदह हजार साठ) किलो–मीटर की मानव श्रृंखला का निर्माण किया गया, जिसमें करोड़ों लोगों की भागीदारी हुई। बिहार ने 21 जनवरी, 2017 के अपने विश्व रिकॉर्ड को खुद तोड़कर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया।

5. बिहार में अब विद्यालय से बाहर बच्चों की संख्या काफी कम हो गई है। समाज में हर वर्ग के बीच शिक्षा के लिए जागरूकता आयी है। शिक्षा वह साधन है जिसके सहारे समाज का कोई व्यक्ति अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। पढ़ने के लिए, लिखने के लिए और जीवन में आगे बढ़ने के लिए लोंगो के बीच सोच पैदा करने में हमारी सरकार कामयाब रही है। अब केवल वहीं बच्चे ही विद्यालय से बाहर है जिनके माता–पिता एवं अभिभावक को इसमें रूची नहीं है। हम लगातार शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए मध्याह्न भोजन योजना, छात्रवृति योजना, मेघावृति योजना के साथ–साथ स्टुडेन्ट क्रेडिट कार्ड के मूहिम से उन्हें जोड़ा जा रहा है। महोदय, आप अवगत है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित 10वीं की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण समान्य एवं पिछड़ा वर्ग के प्रत्येक

छात्र–छात्राओं को 10,000 (दस हजार रूपया) एवं द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण अनुसूचित जाति के श्रेणी के प्रत्येक छात्राओं को 8000 (आठ हजार) रूपया मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना एवं मुख्यमंत्री बालक प्रोत्साहन योजना के तहत उपलब्ध करायी जाती है।

इंटर से उपर की पढ़ाई का शिक्षा रेट मात्र 14. 40 प्रतिशत है उसे उपर उठाने एवं 30 प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से भी आगे पहुंचाने की दिशा में काम प्रारंभ किया गया है। बैंकों के नकारात्मक रवैया को देखकर सरकार ने फैसला किया है बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम बनाकर बच्चों के उच्च शिक्षा में जो बाधा है उसे समाप्त की जाय।

6. पूरे देश में बिहार पहला राज्य है, जिसमें वर्ग I से VIII (वर्ग एक से आठ) तक के बच्चों के लिए आंतरिक मूल्यांकन की प्रणाली लागू की गयी है एवं विद्यालय स्तर पर बच्चों के सीखने की क्षमता के लिए आंतरिक जाँच आरंभ किया गया है। इसकी सराहना भी की जा रही है। वर्ष 2018 में जब भारत सरकार ने एन.सी.ई.आर.टी. के द्वारा पूरे देश में नेशनल एसेसमेंन्ट सर्वे किया तो तुलनात्मक रूप से बिहार के बच्चों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। यद्यपि अभी हमें आगे बहुत काम करना है ताकि हमारे विद्यालयों में नामांकित और पढ़ने वाले बच्चे कक्षा के अनुरूप गुणवत्ता प्राप्त कर सकें।

7. मध्याह्न भोजन योजना में गुणवत्ता एवं अधिकाधिक आच्छादन का लक्ष्य हम प्राप्त कर चुके हैं। सप्ताह में तीन दिन अतिरिक्त पोषक

तत्व देने की व्यवस्था की गई है। बिहार सरकार ने अपने निधि से 300 (तीन सौ) करोड़ रूपये देकर सप्ताह में एक दिन मध्याह्न भोजन में अंडा को सम्मिलित किया है। इसके अतिरिक्त सप्ताह में दो दिन केला अथवा मौसमी फल भी बच्चों को दिया जाता है।

8. बाल भवन 'किलकारी' के माध्यम से हमने झुग्गी–झोपड़ी के उपेक्षित बच्चों के साथ उनकी प्रतिभा को विकसित करने का कार्य किया है। सदन को बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि बालक वर्ग में पटना जिला के बाढ़ अनुमंडल के ग्राम– बिजली मलाही के अनुसूचित जाति वर्ग के रविरंजन कुमार ने श्रीलंका के साथ बॉल बैडन्टिन मैच में अद्‌भुत प्रदर्शन किया और श्रीलंका को 3–0 से पराजित किया। ऋतिक रोशन के साथ 13 बच्चों का चयन एक फिल्म के लिए किया गया है। यहाँ पर बच्चों के लेखन, गायन, नृत्य, पेंटिंग, खेलकूद सभी क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर पर सफलता प्राप्त की है।

9. आज बिहार राज्य के सभी स्थानों पर 1 किलो मीटर के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय, 3 किलो मीटर के अन्तर्गत मध्य विद्यालय एवं 5 किलो मीटर के अन्तर्गत माध्यमिक विद्यालय की सुविधा देने में हमारी सरकार सफल हुई है। हमने हर पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय की सुविधा देने का लक्ष्य रखा है जिसमें हम क्रमशः लक्ष्य प्राप्त करते हुए पंचायतों को आच्छादित कर चुके हैं।

10. माध्यमिक शिक्षा के विस्तार हेतु उच्च माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की गई है। 8391(आठ हजार तीन सौ एकानबे) पंचायतों में से 5059(पॉच हजार उनसठ) पंचायतों में माध्यमिक विद्यालय एवं 2200(दो हजार दो सौ) पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय की सुविधा दी जा चुकी है। अनाच्छादित पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना के क्रम में शौचमुक्त (ODF) पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की प्राथमिकता दिये जाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना के क्रम में भूमि की न्यूनतम उपलब्धता के मापदण्ड को 1 (एक) एकड़ से घटाकर 0.75 (पौने एक) एकड़ निर्धारित किया गया है।

11. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा विगत कई वर्षों से कदाचार मुक्त परीक्षा आयोजित की जा रही है एवं समिति की कार्यप्रणाली में व्यापक बदलाव किया गया है। वर्ष 2018 की माध्यमिक की परीक्षा में 8,91,243(आठ लाख एकानबे हजार दौ सौ तैतालिस) छात्र एवं 8,78,794(आठ लाख अठतर हजार सात सौ चौरानबे) छात्राएँ सम्मिलित हुई हैं। इंटर की परीक्षा में इस वर्ष 7,19,848(सात लाख उन्नीस हजार आठ सौ अड़तालीस) छात्र तथा 4,88,130 (चार लाख अट्ठासी हजार एक सौ तीस) छात्राएँ सम्मिलित हुई।

12. शैक्षणिक सत्र 2015–17 से राज्य के 11 जिलों यथा गया, पटना, वैशाली, बेतिया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सुपौल, पूर्णियां, कटिहार, जमुई एवं मुंगेर में अवस्थित एक–एक राजकीय उच्च विद्यालयों में आई0एस0सी0 (कृषि) का पठन पाठन प्रारंभ है। शेष 27 जिलों में अवस्थित एक–एक सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आई0एस0सी0 (कृषि) का अध्यापन कार्य शैक्षणिक सत्र 2018–20 से प्रारंभ किये जाने का निर्णय लिया गया है।

13. माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में भवन निर्माण, छात्रावास निर्माण, उनके लिए उपस्कर की व्यवस्था जैसे कार्य हम लगातार कर रहे हैं। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रयोगशालाओं को हम संचालित करा रहे हैं और इसके लिए प्रयोगशाला उपकरण एवं सामग्री की व्यवस्था करने जा रहे हैं। 6 (छः) हजार विद्यालयों एवं उच्च विद्यालयों के प्रयोगशाला के लिए 220 (दो सौ बीस) करोड़ रूपये की राशि एवं 2400 (दो हजार चार सौ) माध्यमिक विद्यालयों में उपस्कर के लिए 120 (एक सौ बीस) करोड़ रूपये की राशि निर्गत की जा रही है। 81 मॉडल स्कूल के लिए 186.67 करोड़ (एक सौ छियासी करोड़ सरसठ़ लाख) रूपये की राशि तथा 1,183 (एक हजार एक सौ तेरासी) माध्यमिक विद्यालयों के लिए 12657.71 लाख रू. (एक सौ छब्बीस करोड़ सनतावन लाख एकहतर हजार) की राशि स्वीकृत की गयी है। बालिका

छात्रावास के लिए 22722.11 लाख (दो सौ सताइस करोड़ बाईस लाख ग्यारह हजार) रू0 की राशि स्वीकृत की गयी है। मैट्रिक की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त बच्चों के लिए प्रोत्साहन राशि, नियमित छात्रवृत्ति, पोशाक, साईकिल के लिए राशि बच्चों को सीधे उनके बैंक खाते में भेजा गया है। फलतः सभी बच्चों के नाम से खाता खोलना, आधार कार्ड बनाना और खाते में राशि को प्राप्त कराना जैसे मुहिम के कारण बच्चों के बीच प्रोत्साहन और पढ़ने की प्रेरणा बढ़ी है। डायरेक्ट बेनिफीट ट्रॉन्सफर (DBT) के कारण राशि के लिकेज की संभावना शून्य हो गई है।

14. बिहार स्टुडेन्ट केडिट कार्ड योजना को सफल बनाने एवं विद्यार्थियों को ससमय ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार द्वारा बैंकों के स्थान पर बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम की स्थापना की गई है। इस माध्यम से हम उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों को सरलता पूर्वक अल्प समय में शिक्षा ऋण देंगे एवं बैंक के प्रक्रिया की जटिलता से मुक्ति मिलेगी।

15. 'बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976' में संशोधन करते हुए 3 नये विश्वविद्यालय पूर्णियां विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय एवं मुंगेर विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है जिसका संचालन शुरू किया जा रहा है।

16. राज्य में चार निजी विश्वविद्यालयों क्रमशः अमिटी विश्वविद्यालय, पटना, संदीप विश्वविद्यालय, सिजौल, मधुबनी, के0 के0 विश्वविद्यालय, बिहारशरीफ तथा डा0 सी0वी0 रमन विश्वविद्यालय, वैशाली की स्थापना हेतु अधिसूचना निर्गत हो चुका है तथा अल–करीम विश्वविद्यालय, कटिहार, सी0वी0 रमण विश्वविद्यालय, वैशाली तथा गोपाल नारायण विश्वविद्यालय,सासाराम की स्थापना शीघ्र होने जा रही है।

17. आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के अन्तर्गत चार उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्थानों (i) सेंटर फॉर जियोग्राफिकल स्टडीज (Centre for Geographical Studies) (ii) स्कूल ऑफ जरनलिजम एण्ड मास कॉम्यूनिकेशन (School of Journalism and Mass Communication) (iii) पाटलिपुत्र स्कूल ऑफ इकेनोमिक्स (Patliputra School of Economics) एवं (iv) सेंटर फॉर रिवर स्टडीज (Centre for River Studies) की स्थापना की गई है।

18. हमारा उद्देश्य सबके लिए गुणात्मक शिक्षा एवं जीवनपर्यन्त सीखने का अवसर देना है। इसे हम प्राप्त करेंगे और बिहार का हर बच्चा श्रेष्ठ मानव के रूप में प्रतिष्ठित होगा। गुणात्मक शिक्षा के लिये माता–पिता, परिवार, शिक्षक, विद्यालय, समाज एवं सरकार प्रयत्नशील है। बिहार जैसे

प्रदेश के लिये मानव संसाधन सबसे बड़ी संपदा है। यहाँ के लोग परिश्रमी होते हैं। शिक्षा एवं कौशल सम्पन्न बनाने से ये अपने और समाज के लिये अधिक उपयोगी सिद्ध होंगे। इस दिशा में बिहार सरकार लगातार शिक्षा विभाग के द्वारा प्रयत्न कर रही है।

19. शिक्षकों को वेतन भुगतान के लिए विश्वविद्यालयों को अपेक्षित राशि निर्गत की गई है और ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि समय पर भुगतान में कठिनाई नहीं हो।

वितीय वर्ष 2018–19 में राज्य योजना मद के लिए प्रस्तावित राशि 19107.03 करोड (उन्नीस हजार एक सौ सात करोड़ तीन लाख) में से मुख्य योजनाओं में निम्नप्रकार से राशि व्यय किये जाने का प्रस्ताव है–

I. सर्व शिक्षा अभियान योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत बजट के विरूद्ध पिछले कई वर्षो से काफी कम राशि दी जा रही थी, जिसके कारण शिक्षकों को वेतन देने में कठिनाई होती थी। इसलिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2018–19 में शिक्षको के वेतन हेतु राज्य योजना मद से 5000 करोड़(पॉच हजार करोड़) रूपये की व्यवस्था की गई है।

II. छात्र/छात्राओं को पोशाक देने हेतु 625 करोड़(छःसौ पचीस करोड़) रूपये,साईकिल के लिए 360 करोड़ (तीन सौ साठ करोड़) रूपये, छात्रवृत्ति/ प्रोत्साहन के लिए 287 करोड़ (दौ सौ सतासी करोड़)रूपये एवं अन्य योजनाओं के लिए राशि की व्यवस्था की गई है।

III. विद्यालयों /महाविद्यालयों में आधारभूत संरचना के विकास हेतु लगभग 250 करोड़(दो सौ पचास करोड़)रूपये की व्यवस्था की गई है।

IV. मध्याह्न भोजन योजना के लिए केन्द्रांश 1302.88 करोड़ (एक हजार तीन सौ दो करोड़ अठासी लाख) एवं राज्यांश 868.58 करोड़ (आठ सौ अरसठ करोड़ अन्ठावन लाख) रूपये की व्यवस्था की गई है।

V. सर्व शिक्षा अभियान के लिए केन्द्रांश 6600 करोड़ (छः हजार छः सौ करोड़) रूपये एवं राज्यांश 2384.10 करोड़ (दो हजार तीन सौ चौरासी करोड़ दस लाख) रूपये की व्यवस्था की गई है।

VI. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के लिए केन्द्राश 250 करोड़ (दो सौ पचास करोड़) रूपये एवं राज्यांश 166.67 करोड़ (एक सौ छियासठ करोड़ सड़सठ लाख) रूपये की व्यवस्था की गई है।

VII. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के लिए केन्द्रांश 60 करोड़ (साठ करोड़) रूपये एवं राज्यांश 25.16 करोड़ (पचीस करोड़ सोलह लाख) रूपये की व्यवस्था की गई है।

शिक्षा पर व्यय

(क) शिक्षा विभाग के लिये वित्तीय वर्ष 2018–19 के व्यय वहन हेतु कुल रू0–321,25,63,75,000/– (तीन सौ इक्कीस अरब पचीस करोड़ तिरसठ लाख पचहत्तर हजार रूपये) का उपबंध माँग संख्या– 21 के अन्तर्गत प्रस्तावित है। इसमें गैर योजना व्यय के अलावे राज्य योजना एवं केन्द्र प्रायोजित योजना शामिल है।

(ख) इसमें गैर योजना व्यय के लिये रू0. 130,18,61,01,000/– (एक सौ तीस अरब अठारह करोड़ एकसठ लाख एक हजार रूपये) प्रस्तावित है।

(ग) राज्य योजना के लिए कुल रू0. 191,07,02,74,000/–(एक सौ इक्यानवे अरब सात करोड़ दो लाख चौहत्तर हजार रूपये) का प्रस्ताव है, जिसमें से केन्द्र प्रायोजित योजना अन्तर्गत केन्द्रांश की राशि रू0.82,14,02,74,000/–(बेरासी अरब चौदह करोड़ दो लाख चौहत्तर हजार रूपये), राज्यांश की राशि रू0. 34,45,00,00,000/– (चौतीस अरब पैतालिस करोड़ रूपये), राज्य स्कीम के लिए रू0.7,00,00,00,000/– (सात अरब रूपये) एवं वाह्य सम्पोषित परियोजना हेतु रू0. 3,00,00,00,000/– (तीन अरब रूपये) का बजट प्रस्तावित है।

अन्त में, मैं आप सबों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि आपने हमारे वक्तव्य को ध्यानपूर्वक सुना। हम चाहते हैं कि शिक्षा के सवाल पर, बच्चों के भविष्य के सवाल पर सभी हमारे सम्मानित जन–प्रतिनिधि हमारा सहयोग करें। हम सब मिलकर उत्तम शिक्षा के सपने को बिहार में साकार करें एवं अनुरोध करता हूँ कि बिहार एवं शिक्षा के विकास हेतु **321,25,63,75,000/– (तीन सौ इक्कीस अरब पच्चीस करोड़ तिरसठ लाख पचहत्तर हजार) रूपये** की मॉग पर सदन अपनी स्वीकृति प्रदान करे।

मुख्यमंत्री बालक–बालिका साईकिल योजना

अध्यक्षा महोदय,

वर्ष 2007 में मुख्यमंत्री बालक–बालिका साईकिल योजना की शुरूआत माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया था। 2007 में नवम् वर्ग में लड़कियों की संख्या एक लाख 70 हजार से भी कम थी और आज यह संख्या बढ़कर 15 लाख के करीब पहुंच गयी है, इसके बावजूद विपक्ष के माननीय सदस्य कहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में काम नहीं हो रहा है। जहां पहले सरकारी स्कूलों में न बच्चे पढ़ना चाहते थे और न अभिभावक भेजना चाहते थे, आज विद्यालय के कमरे छोटे पड़ रहे थे अब स्थिति यह है कि एक–एक वर्ग को तीन चार सेक्सन में विभक्त कर स्कूलों में पढ़ाई की जा रही है। ये बदलाव बिहार में हुआ है। आज जब राज्य के लड़के और लड़कियॉ पोशाक पहनकर साईकिल पर सबार होकर घर से स्कूल और स्कूल से घर जाती है, तो राज्य का नजारा बदला–बदला दिखता है।

अध्यक्ष महोदय,

बिहार की क्या हालात थी खासकर विद्यालय भवन के संदर्भ में। जब गॉव में हमलोग जाते थे तो गॉव के बाहर जो सबसे खराब भवन, गिरा हुआ है, क्षतिग्रस्त है तो लोग समझते थे कि यह भवन विद्यालय का होगा या कोई सरकारी भवन होगा।

माननीय श्री नीतीश कुमार जी के हाथो जबसे राज्य का बागडोर बिहार की जनता ने दिया है तब से स्कूल भवन का स्वरूप दिन–प्रतिदिन बदलता दिख रहा है।

अब तो स्कूल का भवन गॉव के सबसे बड़े आदमी के घर की तरह दो मंजीला, बॉन्डरी एवं रसोईघर के साथ सुन्दर, आर्कषक बेहतरीन दिखता है, फिर भी कहते हैं कोई काम ही नहीं हुआ है।

अध्यक्ष महोदय,

शिक्षा के प्रति बच्चों एवं अभिभावकों को प्रेरित एवं आकर्षित करने के उद्देश्य से राज्य में कुल 353 मॉडल विद्यालय की स्वीकृति दी गई है जिस पर प्रति ईकाई तीन करोड़ 36 लाख रूपये का व्यय होगा। 218 मॉडल विद्यालय का निर्माण पूर्ण हो चुका है एवं शेष के निर्माण की प्रक्रिया चल रही है।

मध्य विद्यालय से उच्च विद्यालय में उत्क्रमित कुल 771 उच्च विद्यालय के भवन निर्माण हेतु प्रति ईकाई 58 लाख का व्यय होगा। जिसमें 577 ईकाई का निर्माण पूर्ण हो चुका है, शेष निर्माणाधीन है।

उच्च माध्यमिक विद्यालय (+2) के लिए 993 ईकाई की स्वीकृति दी गई है जिस पर प्रति ईकाई एक करोड़ पन्द्रह लाख रूपये का व्यय होगा। 578 ईकाई पूर्ण हो चुके हैं शेष प्रक्रियाधीन है।

उच्च विद्यालय की संख्या– 6068
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की संख्या– 5293
उत्क्रमित उच्च विद्यालय की संख्या– 3131

आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी कहते है कि बिहार की हवा में, बिहार की मिट्‌टी में, बिहार के धरती में इतनी तासीर है कि हमारे बच्चों का इम्तिहान नीचे कौन कहें आसमान के उपर भी ले तो हमारे बच्चें कभी नम्बर दो नहीं होते हमेशा फस्ट करते है। इतनी प्रतिभा है, हमारे बच्चों के अन्दर इसलिए अपने बच्चों के जज्बें को मैं सलाम करता हूँ।